



Exam Genius

India's No. 1 Platform for UPSC
| SSC | BANK RAILWAY Exam

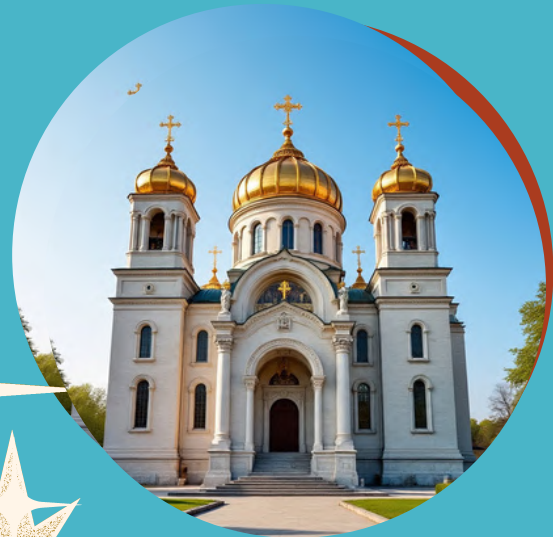


WEEKLY CURRENT AFFAIRS

1 - 7 FEB 2026

1ST WEEK OF FEBRUARY

150+ MCQ
with detailed
explanation



- Banking & finance
- National
- International
- Sports





Ques: Why has the Reserve Bank of India (RBI) proposed changes to the framework for calculating banks' net foreign exchange (FX) exposure and capital requirements?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों के शुद्ध विदेशी मुद्रा (FX) जोखिम और पूंजी आवश्यकता की गणना के ढांचे में बदलाव का प्रस्ताव क्यों दिया है?

- A) To align India's FX risk norms with global standards and ensure uniformity / भारत के एफएक्स जोखिम मानदंडों को वैश्विक मानकों के अनुरूप और एकरूप बनाने के लिए
- B) To promote higher foreign currency lending / विदेशी मुद्रा ऋण को बढ़ावा देने के लिए
- C) To reduce banks' capital burden on FX exposure / एफएक्स जोखिम पर बैंकों का पूंजी बोझ कम करने के लिए
- D) To exempt small banks from FX risk regulations / छोटे बैंकों को एफएक्स जोखिम नियमों से छूट देने के लिए
- E) To postpone implementation of FX risk norms indefinitely / एफएक्स जोखिम नियमों के क्रियान्वयन को अनिश्चितकाल तक टालने के लिए

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- The RBI has proposed changes to the framework for calculating banks' net foreign exchange (FX) exposure and the associated capital requirements.
- आरबीआई ने बैंकों के शुद्ध विदेशी मुद्रा (FX) जोखिम और उससे जुड़ी पूंजी आवश्यकताओं की गणना के ढांचे में बदलाव का प्रस्ताव रखा है।
- The objective is to align India's FX risk norms with global standards prescribed by the Basel Committee and ensure uniform implementation across all regulated entities.
- इसका उद्देश्य बेसल समिति द्वारा निर्धारित वैश्विक मानकों के अनुरूप भारत के एफएक्स जोखिम मानदंडों को बनाना और सभी विनियमित संस्थाओं में एकरूप क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।
- Under the proposed framework, banks will be required to maintain a minimum capital charge of 9% on their net open foreign exchange positions.
- प्रस्तावित ढांचे के तहत, बैंकों को अपने शुद्ध खुले विदेशी मुद्रा जोखिम पर न्यूनतम 9% की पूंजी रखना अनिवार्य होगा।
- The RBI has invited public feedback on these proposals.
- आरबीआई ने इन प्रस्तावों पर जनता से प्रतिक्रिया (फीडबैक) आमंत्रित की है।
- The proposed changes are expected to come into effect from 1 April 2027.
- ये प्रस्तावित बदलाव 1 अप्रैल 2027 से लागू होने की संभावना है।





Ques: What key insight was revealed by SEBI's survey on Indian households' participation in the securities market?

भारतीय घरों की प्रतिभूति बाज़ार में भागीदारी को लेकर सेबी (SEBI) के सर्वेक्षण से कौन-सा प्रमुख तथ्य सामने आया?

- A) More than 50% households actively invest in equities and bonds / आधे से अधिक घर इक्विटी और बॉन्ड में सक्रिय निवेश करते हैं
- B) Awareness and participation levels are almost equal / जागरूकता और भागीदारी का स्तर लगभग समान है
- C) Only about 9.5% of Indian households participate despite higher awareness / उच्च जागरूकता के बावजूद केवल लगभग 9.5% घर ही भागीदारी करते हैं
- D) Rural households have higher participation than urban households / ग्रामीण घरों की भागीदारी शहरी घरों से अधिक है
- E) Participation is highest in complex instruments like derivatives and AIFs / डेरिवेटिव्स और AIFs जैसे जटिल साधनों में भागीदारी सबसे अधिक है

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- A SEBI survey revealed that out of 33.72 crore Indian households, only 3.21 crore households (9.5%) invest in securities such as equities, mutual funds, and corporate bonds.
- सेबी के सर्वेक्षण में पाया गया कि 33.72 करोड़ भारतीय घरों में से केवल 3.21 करोड़ घर (9.5%) ही इक्विटी, म्यूचुअल फंड और कॉर्पोरेट बॉन्ड जैसे प्रतिभूति बाज़ार में निवेश करते हैं।
- Although 63% households (around 21.3 crore) are aware of at least one market-linked product, actual participation remains very low at 9.5%.
- लगभग 63% घर (करीब 21.3 करोड़) कम से कम एक बाज़ार-संबंधित उत्पाद के बारे में जागरूक हैं, लेकिन वास्तविक भागीदारी केवल 9.5% ही है।
- The survey was conducted by Kantar between May and July 2025, covering over 90,000 households across 400 cities and 1,000 villages.
- यह सर्वेक्षण कांतर (Kantar) द्वारा मई से जुलाई 2025 के बीच किया गया, जिसमें 400 शहरों और 1,000 गांवों के 90,000 से अधिक घर शामिल थे।





- Nearly 30.51 crore households remain outside the securities market, highlighting significant under-penetration despite strong market growth over the past decade.
- लगभग 30.51 करोड़ घर अब भी प्रतिभूति बाज़ार से बाहर हैं, जो पिछले एक दशक में तेज़ बाज़ार वृद्धि के बावजूद कम पहुंच को दर्शाता है।
- Awareness is highest for mutual funds (53%) and ETFs (49%), while participation in complex instruments like corporate bonds, derivatives, REITs, InvITs, and AIFs is extremely limited.
- म्यूचुअल फंड (53%) और ETF (49%) के प्रति जागरूकता सबसे अधिक है, जबकि कॉर्पोरेट बॉन्ड, डेरिवेटिव्स, REITs, InvITs और AIFs जैसे जटिल साधनों में भागीदारी बहुत सीमित है।
- Urban households show higher awareness (74%) compared to rural households (56%), reflecting clear geographic disparities.
- शहरी घरों में जागरूकता (74%) ग्रामीण घरों (56%) की तुलना में अधिक पाई गई, जो भौगोलिक असमानता को दर्शाती है।

EXAM
Genius





Ques: What is the key objective of the newly launched Aadhaar App dedicated to the nation?

राष्ट्र को समर्पित नए आधार ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A) To replace physical Aadhaar cards completely / भौतिक आधार कार्ड को पूरी तरह से बदलना
B) To provide a secure, convenient and privacy-first digital identity platform / सुरक्षित, सुविधाजनक और गोपनीयता-प्रथम डिजिटल पहचान प्लेटफॉर्म प्रदान करना
C) To enable only biometric authentication for all services / सभी सेवाओं के लिए केवल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सक्षम करना
D) To store Aadhaar numbers with service providers / सेवा प्रदाताओं के पास आधार नंबर संग्रहीत करना
E) To limit Aadhaar usage to government services only / आधार के उपयोग को केवल सरकारी सेवाओं तक सीमित करना

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Minister of State for Commerce and Industry and Electronics & Information Technology, Shri Jitin Prasada, dedicated the new Aadhaar App to the nation.
- वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने नए आधार ऐप को राष्ट्र को समर्पित किया।
- The Aadhaar App has been developed by the Unique Identification Authority of India (UIDAI) as a next-generation mobile application.
- आधार ऐप को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा एक नेक्स्ट-जेनरेशन मोबाइल एप्लिकेशन के रूप में विकसित किया गया है।
- It provides Aadhaar Number Holders with a secure, convenient and privacy-first way to carry, share, show and verify their digital identity.
- यह आधार संख्या धारकों को अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित, सुविधाजनक और गोपनीयता-आधारित तरीके से रखने, साझा करने, दिखाने और सत्यापित करने की सुविधा देता है।
- The app supports multiple real-life use cases such as hotel check-ins via OVSE QR code scanning, optional face verification, age verification for cinema tickets, hospital admissions, and verification of gig workers.
- यह ऐप OVSE क्यूआर कोड के माध्यम से होटल चेक-इन, वैकल्पिक फेस वेरिफिकेशन, सिनेमा टिकट के लिए आयु सत्यापन, अस्पताल प्रवेश और गिग वर्कर्स के सत्यापन जैसे कई वास्तविक उपयोग मामलों को सपोर्ट करता है।





- Advanced features include face verification for proof of presence, one-click biometric lock/unlock, viewing authentication history, and a QR-based contact card.
- उन्नत सुविधाओं में उपस्थिति प्रमाण के लिए फेस वेरिफिकेशन, एक-क्लिक बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक, प्रमाणीकरण इतिहास देखना और क्यूआर-आधारित कॉन्टैक्ट कार्ड शामिल हैं।
- The app allows management of up to five Aadhaar profiles on one device under the concept of “One Family – One App” and enables mobile number updates along with address updates.
- यह ऐप “वन फैमिली – वन ऐप” की अवधारणा के तहत एक डिवाइस पर पाँच तक आधार प्रोफाइल प्रबंधित करने की सुविधा देता है तथा पते के साथ-साथ मोबाइल नंबर अपडेट करने की भी अनुमति देता है।
- It ensures data minimisation by sharing only digitally signed verifiable credentials and not storing Aadhaar numbers with verifiers, in line with the DPDP Act.
- यह सत्यापनकर्ताओं के पास आधार नंबर संग्रहीत न कर केवल डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण साझा कर डेटा न्यूनतमकरण सुनिश्चित करता है, जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम के अनुरूप है।

EXAM
Genius





Ques: Who has been appointed as the Managing Director & CEO of Fino Payments Bank for a tenure of three years till May 01, 2029?

फिनो पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MD & CEO) के रूप में तीन वर्ष (01 मई 2029 तक) के कार्यकाल के लिए किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Rajesh Kumar / राजेश कुमार
- B) Deepak Mehta / दीपक मेहता
- C) Anil Sharma / अनिल शर्मा
- D) Sanjay Malhotra / संजय मल्होत्रा
- E) Rishi Gupta / ऋषि गुप्ता

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Mr. Rishi Gupta has been appointed as the Managing Director & CEO of Fino Payments Bank for a tenure of three years until May 01, 2029.
- श्री ऋषि गुप्ता को फिनो पेमेंट्स बैंक का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तीन वर्ष के लिए (01 मई 2029 तक) नियुक्त किया गया है।
- Fino Payments Bank has received in-principle approval from the Reserve Bank of India (RBI) for conversion into a Small Finance Bank, becoming the first among payments banks to receive such approval.
- फिनो पेमेंट्स बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित होने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है, जिससे यह ऐसा करने वाला पहला पेमेंट्स बैंक बन गया है।
- Fino Payments Bank was established in 2015 and its headquarters is located in Navi Mumbai.
- फिनो पेमेंट्स बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय नवी मुंबई में स्थित है।
- The tagline of Fino Payments Bank is "Qadar Aapki Mehnat Ki".
- फिनो पेमेंट्स बैंक की टैगलाइन "कदर आपकी मेहनत की" है।





Ques: Why did the Department of Posts (DoP) sign an agreement with Stock Holding Services Limited (SSL)?

डाक विभाग (DoP) ने स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड (SSL) के साथ समझौता क्यों किया?

- A) To introduce postal savings bonds / डाक बचत बांड शुरू करने के लिए
- B) To promote access to regulated capital market services for citizens / नागरिकों के लिए विनियमित पूंजी बाज़ार सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए
- C) To privatize selected post offices / चयनित डाकघरों का निजीकरण करने के लिए
- D) To replace banks with post offices for all investments / सभी निवेशों के लिए बैंकों को डाकघरों से बदलने के लिए
- E) To launch a new digital currency platform / नया डिजिटल मुद्रा प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Department of Posts (DoP), Ministry of Communications, Government of India, signed an agreement with Stock Holding Services Limited (SSL) to promote access to regulated capital market services for citizens across the country.
- भारत सरकार के संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग (DoP) ने नागरिकों के लिए विनियमित पूंजी बाज़ार सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड (SSL) के साथ समझौता किया है।
- India Post, with its extensive nationwide network of over 1.65 lakh post offices, including a strong presence in rural and remote areas, plays a key role in extending financial services to underserved populations.
- 1.65 लाख से अधिक डाकघरों के व्यापक राष्ट्रीय नेटवर्क और ग्रामीण व दूरदराज़ क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति के कारण इंडिया पोस्ट वंचित वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- Under the agreement, citizens will be able to access SSL's services through digital utilities such as onboarding links and QR codes available on official platforms and at selected post offices.
- इस समझौते के तहत नागरिक आधिकारिक प्लेटफॉर्म और चयनित डाकघरों पर उपलब्ध ऑनबोर्डिंग लिंक और क्यूआर कोड जैसे डिजिटल माध्यमों के जरिए SSL की सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
- The services include opening demat and trading accounts, investing in mutual funds, participating in IPOs, and accessing other permitted investment products.
- इन सेवाओं में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना, म्यूचुअल फंड में निवेश, आईपीओ में भागीदारी और अन्य अनुमत निवेश उत्पाद शामिल हैं।



Ques: What is the significance of Microsoft introducing the 'Maia 200' AI chip?

माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 'माइया 200' एआई चिप पेश करने का क्या महत्व है?

- A) It marks Microsoft's entry into consumer smartphone processors / यह माइक्रोसॉफ्ट के स्मार्टफोन प्रोसेसर क्षेत्र में प्रवेश को दर्शाता है
- B) It replaces all third-party AI chips used by Microsoft immediately / यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी तृतीय-पक्ष एआई चिप्स को तुरंत बदल देता है
- C) It is Microsoft's first AI chip launched in 2026 / यह 2026 में लॉन्च की गई माइक्रोसॉफ्ट की पहली एआई चिप है
- D) It is designed exclusively for gaming consoles / यह विशेष रूप से गेमिंग कंसोल के लिए डिज़ाइन किया गया है
- E) It strengthens Microsoft's push to build an integrated AI ecosystem / यह एकीकृत एआई इकोसिस्टम बनाने की माइक्रोसॉफ्ट की रणनीति को मजबूत करता है

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Microsoft has introduced the second generation of its in-house artificial intelligence processor, named 'Maia 200', along with a new suite of AI-focused software tools.
- माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इन-हाउस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसर की दूसरी पीढ़ी 'माइया 200' को एआई-केंद्रित सॉफ्टवेयर टूल्स के नए सूट के साथ पेश किया है।
- The launch strengthens Microsoft's strategy to build an integrated AI ecosystem across hardware and software.
- यह लॉन्च हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों स्तरों पर एकीकृत एआई इकोसिस्टम विकसित करने की माइक्रोसॉफ्ट की रणनीति को मजबूत करता है।
- Maia 200 builds on Microsoft's first Maia AI chip, which was initially introduced in 2023.
- माइया 200, माइक्रोसॉफ्ट की पहली माइया एआई चिप पर आधारित है, जिसे पहली बार 2023 में पेश किया गया था।
- The Maia 200 AI chip is manufactured by Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).
- माइया 200 एआई चिप का निर्माण ताइवान सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग कंपनी (TSMC) द्वारा किया गया है।
- It uses advanced 3-nanometer (nm) process technology and incorporates high-bandwidth memory for improved AI performance.
- इसमें उन्नत 3-नैनोमीटर (nm) प्रोसेस तकनीक और हाई-बैंडविड्थ मेमोरी का उपयोग किया गया है, जिससे एआई प्रदर्शन बेहतर होता है।



Ques: At which two major international theatre festivals will the Brazilian production Passado Presente Zenturo make its international debut in 2026?

ब्राज़ील का नाट्य प्रोडक्शन पासाडो प्रेसेंटे ज़ेंटुरो 2026 में किन दो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय रंगमंच महोत्सवों में अपनी अंतरराष्ट्रीय शुरुआत करेगा?

- A) Edinburgh Festival & Cannes Theatre Festival / एडिनबर्ग महोत्सव और कान्स थिएटर फेस्टिवल
- B) Bharat Rang Mahotsav (India) & GITIS FEST (Russia) / भारत रंग महोत्सव (भारत) और GITIS FEST (रूस)
- C) Avignon Festival & Tokyo Theatre Festival / एविग्नन महोत्सव और टोक्यो थिएटर फेस्टिवल
- D) Berlin Theatre Festival & Sydney Arts Festival / बर्लिन थिएटर फेस्टिवल और सिडनी आर्ट्स फेस्टिवल
- E) Shanghai Theatre Festival & Seoul Drama Festival / शंघाई थिएटर फेस्टिवल और सियोल ड्रामा फेस्टिवल

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Brazilian theatre production Passado Presente Zenturo will make its international debut in 2026.
- ब्राज़ील का नाट्य प्रोडक्शन पासाडो प्रेसेंटे ज़ेंटुरो वर्ष 2026 में अपनी अंतरराष्ट्रीय शुरुआत करेगा।
- It will represent Brazil at the 25th Bharat Rang Mahotsav in India, one of the world's most prestigious international theatre festivals.
- यह भारत में आयोजित विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय रंगमंच महोत्सवों में से एक 25वें भारत रंग महोत्सव में ब्राज़ील का प्रतिनिधित्व करेगा।
- Bharat Rang Mahotsav is organized by the National School of Drama (NSD) under the Ministry of Culture, Government of India.
- भारत रंग महोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD) द्वारा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत किया जाता है।
- The production will be performed in Bengaluru on February 5, 2026, and New Delhi on February 7, 2026.
- यह प्रस्तुति 5 फरवरी 2026 को बेंगलुरु और 7 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में की जाएगी।
- Additionally, the production will represent Brazil at the 5th GITIS FEST in Moscow, Russia, scheduled for April 2026.
- इसके अलावा, यह नाट्य प्रस्तुति अप्रैल 2026 में मॉस्को (रूस) में आयोजित 5वें GITIS FEST में भी ब्राज़ील का प्रतिनिधित्व करेगी।





Ques: What is the objective of NITI Aayog's 'Sampoornata Abhiyan 2.0'?

नीति आयोग के 'सम्पूर्णता अभियान 2.0' का उद्देश्य क्या है?

- A) To launch a long-term infrastructure development programme / दीर्घकालिक अवसंरचना विकास कार्यक्रम शुरू करना
- B) To achieve saturation of key development indicators in Aspirational Districts and Blocks / आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में प्रमुख विकास संकेतकों की संतृप्ति हासिल करना
- C) To provide direct financial assistance to all districts / सभी जिलों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना
- D) To replace the Aspirational Districts Programme / आकांक्षी जिला कार्यक्रम को प्रतिस्थापित करना
- E) To conduct a nationwide population census / राष्ट्रीय जनगणना कराना

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- NITI Aayog has launched 'Sampoornata Abhiyan 2.0', a three-month nationwide campaign aimed at achieving saturation of key development indicators in Aspirational Districts and Aspirational Blocks.
- नीति आयोग ने 'सम्पूर्णता अभियान 2.0' की शुरुआत की है, जो आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों में प्रमुख विकास संकेतकों की संतृप्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से तीन महीने का राष्ट्रीय अभियान है।
- The campaign will be conducted from January 28 to April 14, 2026, and builds upon the outcomes of the first Sampoornata Abhiyan conducted in 2024.
- यह अभियान 28 जनवरी से 14 अप्रैल 2026 तक चलेगा और 2024 में आयोजित पहले सम्पूर्णता अभियान के परिणामों पर आधारित है।
- Under Sampoornata Abhiyan 2.0, five Key Performance Indicators (KPIs) will be saturated in Aspirational Districts and six KPIs in Aspirational Blocks.
- सम्पूर्णता अभियान 2.0 के तहत आकांक्षी जिलों में पाँच और आकांक्षी ब्लॉकों में छह प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPI) की संतृप्ति का लक्ष्य रखा गया है।
- The initiative covers 112 Aspirational Districts and 513 Aspirational Blocks under the Aspirational Districts and Blocks Programme.
- यह पहल आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत 112 आकांक्षी जिलों और 513 आकांक्षी ब्लॉकों को कवर करती है।





Ques: Why is the National Highways Authority of India (NHA) planning to reduce its total debt below ₹2 lakh crore by March 2026?

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHA) मार्च 2026 तक अपना कुल ऋण ₹2 लाख करोड़ से कम क्यों करना चाहता है?

- A) To increase fresh borrowing for new projects / नई परियोजनाओं के लिए ताज़ा उधारी बढ़ाने के लिए
- B) To comply with RBI banking regulations / RBI के बैंकिंग नियमों का पालन करने के लिए
- C) To improve financial sustainability by cutting borrowing and interest costs / उधारी और ब्याज लागत घटाकर वित्तीय स्थिरता सुधारने के लिए
- D) To transfer debt to state governments / ऋण को राज्य सरकारों को स्थानांतरित करने के लिए
- E) To privatize national highways / राष्ट्रीय राजमार्गों के निजीकरण के लिए

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The National Highways Authority of India (NHA) aims to reduce its total debt to below ₹2 lakh crore in the financial year ending March 2026.
- राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHA) मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष में अपना कुल ऋण ₹2 लाख करोड़ से कम करने का लक्ष्य रखता है।
- NHA's debt peaked at ₹3.5 lakh crore in 2021–22.
- NHA का ऋण 2021–22 में ₹3.5 लाख करोड़ के उच्चतम स्तर पर था।
- As of 31 December 2025, the outstanding debt stood at ₹2,35,947 crore.
- 31 दिसंबर 2025 तक कुल बकाया ऋण ₹2,35,947 करोड़ था।
- A key step taken was no fresh borrowing since 2023, resulting in a 32% reduction in debt.
- 2023 से कोई नई उधारी नहीं लेने के कारण ऋण में 32% की कमी आई है।
- NHA has also prepaid loans worth ₹86,000 crore, including a ₹50,000 crore loan from the National Small Savings Fund (NSSF).
- NHA ने ₹86,000 करोड़ के ऋण का पूर्व भुगतान किया है, जिसमें राष्ट्रीय लघु बचत कोष (NSSF) से लिया गया ₹50,000 करोड़ का ऋण शामिल है।
- By renegotiating bank loans, interest rates were reduced by 80 basis points (0.8%), leading to savings of over ₹3,500 crore in the last two years.
- बैंक ऋणों के पुनः वार्ता से ब्याज दरों में 80 बेसिस पॉइंट (0.8%) की कमी हुई, जिससे पिछले दो वर्षों में ₹3,500 करोड़ से अधिक की बचत हुई।





Ques : Which state launched Raj-UNNATI to Monitor Development Projects ?

किस राज्य ने विकास परियोजनाओं की निगरानी के लिए राज-उन्नति की शुरुआत की?

- A) Maharashtra / महाराष्ट्र
- B) Karnataka / कर्नाटक
- C) Gujarat / गुजरात
- D) Rajasthan / राजस्थान
- E) Andhra Pradesh / आंध्र प्रदेश

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- Rajasthan has launched Raj-UNNATI, a state-level digital governance platform inspired by the Government of India's PRAGATI (Pro-Active Governance and Timely Implementation) model.
- राजस्थान ने केंद्र सरकार के प्रगति (Pro-Active Governance and Timely Implementation) मॉडल से प्रेरित राज-उन्नति नामक राज्य-स्तरीय डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
- With this initiative, Rajasthan has become the first Indian state to replicate the PRAGATI governance framework at the regional level.
- इस पहल के साथ राजस्थान क्षेत्रीय स्तर पर प्रगति गवर्नेंस फ्रेमवर्क को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
- PRAGATI is an electronic (e-governance) and monitoring platform initiated by the Government of India in 2014.
- प्रगति (PRAGATI) एक इलेक्ट्रॉनिक (ई-गवर्नेंस) एवं निगरानी प्लेटफॉर्म है, जिसे 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था।
- The platform is designed to monitor key infrastructure and development projects in real time.
- यह प्लेटफॉर्म प्रमुख अवसंरचना और विकास परियोजनाओं की रीयल-टाइम निगरानी के लिए बनाया गया है।
- PRAGATI integrates technology, administration, and coordination to reduce delays in public service delivery.
- प्रगति प्लेटफॉर्म तकनीक, प्रशासन और समन्वय को एकीकृत कर सार्वजनिक सेवा वितरण में देरी को कम करने में सहायक है।

About Rajasthan :

- Capital : Jaipur
- CM : Bhajan Lal Sharma
- Governor : Haribhau Bagade



Ques: What was the main objective of the Federated Intelligence Hackathon organized by the National Health Authority (NHA)?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा आयोजित फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का मुख्य उद्देश्य क्या था?

- A) To promote commercial AI startups in healthcare / स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यावसायिक AI स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना
- B) To develop Digital Public Goods (DPGs) for Health Artificial Intelligence / स्वास्थ्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के लिए डिजिटल पब्लिक गुड्स (DPGs) विकसित करना
- C) To create a centralized national health data repository / एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय स्वास्थ्य डेटा भंडार बनाना
- D) To train doctors in clinical AI applications / चिकित्सकों को क्लिनिकल AI अनुप्रयोगों में प्रशिक्षित करना
- E) To replace existing health IT systems / मौजूदा स्वास्थ्य आईटी प्रणालियों को बदलना

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The National Health Authority (NHA) organized a Federated Intelligence Hackathon at IIT Kanpur.

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने IIT कानपुर में फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया।
- The hackathon focused on developing Digital Public Goods (DPGs) for Health AI.
- हैकाथॉन का मुख्य फोकस स्वास्थ्य AI के लिए डिजिटल पब्लिक गुड्स (DPGs) का विकास था।

• It was organized in collaboration with:

- National Institute for Research in Digital Health and Data Science (NIRDHDS)
- Indian Institute of Technology Kanpur (IIT Kanpur)
- यह निम्न संस्थानों के सहयोग से आयोजित किया गया:
 - राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य एवं डेटा विज्ञान अनुसंधान संस्थान (NIRDHDS)
 - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर (IIT Kanpur)

• Key objectives included promoting:

- Responsible and ethical AI
- Privacy-preserving innovation
- Federated AI frameworks
- प्रमुख उद्देश्यों में शामिल थे:
 - जिम्मेदार और नैतिक AI
 - गोपनीयता-संरक्षण नवाचार
 - फेडरेटेड AI ढांचे



Ques: Mukhya Mantrir Eti Koli Duti Paat Scheme launched by which state Government?

मुख्यमंत्री एति कोली दुति पात योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई?

- A) Assam / असम
- B) Tripura / त्रिपुरा
- C) Gujarat / गुजरात
- D) Himachal Pradesh / हिमाचल प्रदेश
- E) Sikkim / सिक्किम

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- The Mukhya Mantrir Eti Koli Duti Paat Scheme was launched by Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma.
- मुख्यमंत्री एति कोली दूटी पाट योजना असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा शुरू की गई।
- The scheme was launched at Doomdooma in Tinsukia district of Assam.
- यह योजना असम के तिनसुकिया ज़िले के डूमडूमा में शुरू की गई।
- The objective of the scheme is to honour the contribution of tea garden workers on the completion of 200 years of Assam's tea industry.
- इस योजना का उद्देश्य असम के चाय उद्योग के 200 वर्ष पूरे होने पर चाय बागान श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करना है।
- Under the scheme, the Government of Assam will provide a one-time financial assistance of ₹5,000.
- इस योजना के तहत असम सरकार ₹5,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- The benefit will be extended to more than six lakh tea garden workers, including both permanent and casual workers, across the state.
- यह लाभ राज्यभर के स्थायी और अस्थायी (कैजुअल) श्रमिकों सहित छह लाख से अधिक चाय बागान श्रमिकों को मिलेगा।

About Assam :

- Capital : Dispur
- CM : Himanta Biswa Sarma
- Governor : Lakshman Acharya





Ques: Where was the Bharat Electricity Summit 2026 held?

भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया?

- A) Mumbai / मुंबई
- B) Bengaluru / बेंगलुरु
- C) Hyderabad / हैदराबाद
- D) New Delhi / नई दिल्ली
- E) Chennai / चेन्नई

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- Bharat Electricity Summit 2026 was held at Yashobhoomi, New Delhi, and hosted by India.
- भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन यशोभूमि, नई दिल्ली में किया गया और इसकी मेजबानी भारत ने की।
- The summit was inaugurated by Union Power Minister Manohar Lal.
- इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल द्वारा किया गया।
- The theme of Bharat Electricity Summit 2026 was “Electrifying Growth. Empowering Sustainability. Connecting Globally.”
- भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 की थीम थी — “Electrifying Growth. Empowering Sustainability. Connecting Globally.”

EXAM
Genius





Ques: ONGC and Reliance Industries signed an agreement to share deepwater offshore resources primarily in which region?

ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र में गहरे समुद्री अपतटीय संसाधन साझा करने के लिए समझौता किया है?

- A) Mumbai High Basin / मुंबई हाई बेसिन
- B) Cauvery Basin / कावेरी बेसिन
- C) Krishna Godavari Basin / कृष्णा-गोदावरी बेसिन
- D) Assam–Arakan Basin / असम–अराकान बेसिन
- E) Cambay Basin / कंबे बेसिन

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- ONGC and Reliance Industries Ltd (RIL) have signed an agreement to share resources for deepwater offshore exploration and production (E&P) operations.
- ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने गहरे समुद्री अपतटीय अन्वेषण एवं उत्पादन (E&P) कार्यों के लिए संसाधन साझा करने का समझौता किया है।
- The collaboration focuses on India's East Coast, particularly the Krishna Godavari (KG) Basin, and also includes the Andaman offshore region.
- यह सहयोग भारत के पूर्वी तट, विशेष रूप से कृष्णा–गोदावरी (KG) बेसिन पर केंद्रित है तथा इसमें अंडमान अपतटीय क्षेत्र भी शामिल है।
- The agreement aims at cost optimisation, faster execution, and improved utilisation of high-value assets in complex deepwater projects.
- इस समझौते का उद्देश्य जटिल गहरे समुद्री परियोजनाओं में लागत अनुकूलन, तेज़ क्रियान्वयन और उच्च-मूल्य परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करना है।
- Shared resources include drilling rigs, marine vessels, pipelines, processing facilities, logistics, and specialised subsea equipment.
- साझा किए जाने वाले संसाधनों में ड्रिलिंग रिग, समुद्री पोत, पाइपलाइन, प्रोसेसिंग सुविधाएँ, लॉजिस्टिक्स और विशेष सबसी उपकरण शामिल हैं।
- The pact aligns with the Oilfields (Regulation and Development) Amendment Act, 2025, promoting infrastructure sharing and industry collaboration to strengthen India's energy security.
- यह समझौता ऑयलफील्ड्स (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) संशोधन अधिनियम, 2025 के अनुरूप है, जो अवसंरचना साझेदारी और उद्योग सहयोग को बढ़ावा देकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है।



Ques : Where will one of the new World Economic Forum centres for the Fourth Industrial Revolution be established in India?

भारत में विश्व आर्थिक मंच (WEF) का चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा?

- A) Maharashtra / महाराष्ट्र
- B) Telangana / तेलंगाना
- C) Karnataka / कर्नाटक
- D) Gujarat / गुजरात
- E) Andhra Pradesh / आंध्र प्रदेश

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- The World Economic Forum (WEF) will establish five new centres for the Fourth Industrial Revolution globally.
- विश्व आर्थिक मंच (WEF) वैश्विक स्तर पर चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए पाँच नए केंद्र स्थापित करेगा।
- One of these new centres will be set up in Andhra Pradesh, India.
- इनमें से एक नया केंद्र भारत के आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा।
- The other centres will be established in France, the United Kingdom and the United Arab Emirates.
- अन्य केंद्र फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित किए जाएंगे।
- These centres will focus on artificial intelligence (AI), frontier technologies, energy transition and cyber resilience.
- ये केंद्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा संक्रमण और साइबर लचीलापन पर केंद्रित होंगे।
- This will be the third Fourth Industrial Revolution centre in India after Mumbai and Telangana.
- मुंबई और तेलंगाना के बाद यह भारत में चौथी औद्योगिक क्रांति का तीसरा केंद्र होगा।
- The term Fourth Industrial Revolution (IR 4.0) was coined in 2017 by WEF founder Klaus Schwab.
- चौथी औद्योगिक क्रांति (IR 4.0) शब्द 2017 में WEF के संस्थापक क्लॉस श्वाब द्वारा दिया गया था।





Ques: Why were the Jeevan Raksha Padak Series of Awards-2025 approved by the President of India?

भारत के राष्ट्रपति द्वारा जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार-2025 को क्यों स्वीकृति दी गई?

- A) For courage and selfless life-saving acts / साहस और निस्वार्थ जीवन-रक्षा कार्यों के लिए
- B) For outstanding achievements in sports / खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए
- C) For excellence in public administration / लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए
- D) For contributions to literature and culture / साहित्य और संस्कृति में योगदान के लिए
- E) For service in disaster management planning / आपदा प्रबंधन योजना में सेवा के लिए

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- President of India Droupadi Murmu approved the conferment of the Jeevan Raksha Padak Series of Awards-2025 on 30 individuals for their courage and selfless life-saving acts.
- भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहस और निस्वार्थ जीवन-रक्षा कार्यों के लिए 30 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार-2025 प्रदान करने की स्वीकृति दी।
- The awards are given under three categories: Sarvottam Jeevan Raksha Padak (6 awardees), Uttam Jeevan Raksha Padak (6 awardees), and Jeevan Raksha Padak (18 awardees).
- ये पुरस्कार तीन श्रेणियों में प्रदान किए गए: सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक (6), उत्तम जीवन रक्षा पदक (6) और जीवन रक्षा पदक (18)।
- Out of the total awardees, 6 individuals were honoured posthumously.
- कुल पुरस्कारार्थियों में से 6 को मरणोपरांत सम्मानित किया गया।
- The Jeevan Raksha Padak was established in 1961 to honour acts of bravery involving the saving of human lives.
- जीवन रक्षा पदक की स्थापना 1961 में मानव जीवन की रक्षा हेतु साहसिक कार्यों को सम्मानित करने के लिए की गई थी।
- The awards include a medal, a certificate, and a one-time monetary allowance of ₹2 lakh for Sarvottam, ₹1.5 lakh for Uttam, and ₹1 lakh for Jeevan Raksha Padak.
- इन पुरस्कारों में पदक, प्रमाण-पत्र और एकमुश्त नकद राशि शामिल है: सर्वोत्तम के लिए ₹2 लाख, उत्तम के लिए ₹1.5 लाख और जीवन रक्षा पदक के लिए ₹1 लाख।





Ques: Why is the Memorandum of Understanding (MoU) signed between the All India Institute of Ayurveda (AIIA) and CAYEIT significant?

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) और CAYEIT के बीच हस्ताक्षरित समझौता (MoU) क्यों महत्वपूर्ण है?

- A) It aims to promote Ayurvedic tourism only / यह केवल आयुर्वेदिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है
- B) It focuses on traditional medicine exports / यह पारंपरिक औषधि निर्यात पर केंद्रित है
- C) It seeks to promote research, technology transfer and innovation in Ayurveda / यह आयुर्वेद में अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए है
- D) It replaces existing AYUSH institutions / यह मौजूदा आयुष संस्थानों को प्रतिस्थापित करता है
- E) It is limited to undergraduate education / यह केवल स्नातक शिक्षा तक सीमित है

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The All India Institute of Ayurveda (AIIA), the apex institute under the Ministry of AYUSH, signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Centre for Ayurveda Education, Innovation & Technology (CAYEIT).
- आयुष मंत्रालय के अंतर्गत शीर्ष संस्थान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) ने सेंटर फॉर आयुर्वेद एजुकेशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (CAYEIT) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- The partnership marks a significant milestone in the field of digital health within the Ayurvedic sector.
- यह साझेदारी आयुर्वेदिक क्षेत्र में डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।
- The objective of the MoU is to foster cutting-edge research, technology transfer, and innovative educational frameworks in Ayurveda.
- इस MoU का उद्देश्य आयुर्वेद में अत्याधुनिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नवोन्मेषी शैक्षणिक ढांचे को बढ़ावा देना है।
- The All India Institute of Ayurveda was established in 2015 and is headquartered in New Delhi.
- अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- The Director of AIIA is Dr. Pradeep Kumar Prajapati.
- AIIA के निदेशक डॉ. प्रदीप कुमार प्रजापति हैं।



Ques: Why did UNESCO announce an emergency assistance package for Vietnam?

यूनेस्को ने वियतनाम के लिए आपातकालीन सहायता पैकेज की घोषणा क्यों की?

- A) Due to earthquake damage to heritage sites / विरासत स्थलों को आए भूकंप नुकसान के कारण
- B) Due to flooding caused by river overflow / नदियों के उफान से आई बाढ़ के कारण
- C) Due to severe damage caused by multiple typhoons / कई शक्तिशाली तूफानों से हुए गंभीर नुकसान के कारण
- D) Due to armed conflict affecting education / शिक्षा को प्रभावित करने वाले सशस्त्र संघर्ष के कारण
- E) Due to volcanic eruptions / ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- UNESCO announced an emergency assistance package of USD 740,000 to protect cultural heritage and education in Vietnam after severe storm damage.
- यूनेस्को ने गंभीर तूफानी क्षति के बाद वियतनाम में सांस्कृतिक विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए 7.40 लाख अमेरिकी डॉलर की आपातकालीन सहायता की घोषणा की।
- The damage was caused by three major typhoons — Wipha, Bualoi, and Matmo.
- यह नुकसान विष्ठा, बुआलोई और माट्मो नामक तीन प्रमुख तूफानों के कारण हुआ।
- The storms led to hundreds of deaths and damaged hundreds of thousands of homes.
- इन तूफानों से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई और लाखों घरों को नुकसान पहुंचा।
- Large-scale destruction was reported to cultural heritage sites and educational infrastructure.
- सांस्कृतिक विरासत स्थलों और शैक्षणिक अवसंरचना को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची।
- UNESCO's intervention focuses on World Heritage Sites such as Hue and Hoi An.
- यूनेस्को का हस्तक्षेप हुए और होई आन जैसे विश्व धरोहर स्थलों पर केंद्रित है।
- Key actions include technical damage assessments, emergency protection measures, conservation planning, and restoration support, implemented in coordination with Vietnam's Ministry of Culture.





Ques: Who was Sir William Mark Tully, who recently passed away at the age of 90?

हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन करने वाले सर विलियम मार्क टली कौन थे?

- A) Former editor of The Times of India / टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व संपादक
- B) Veteran journalist and former BBC Bureau Chief in India / वरिष्ठ पत्रकार एवं भारत में बीबीसी के पूर्व ब्यूरो प्रमुख
- C) British diplomat to India / भारत में ब्रिटेन के पूर्व राजनयिक
- D) Former Director General of Doordarshan / दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक
- E) Author and former Indian Information Service officer / लेखक एवं भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Sir William Mark Tully was a veteran journalist and renowned broadcaster, widely known as the British Broadcasting Corporation (BBC)'s 'voice of India'.
- सर विलियम मार्क टली एक वरिष्ठ पत्रकार और प्रसिद्ध प्रसारक थे, जिन्हें बीबीसी की 'भारत की आवाज़' के रूप में जाना जाता था।
- He served as the Bureau Chief of BBC, New Delhi for 22 years, playing a key role in shaping international reporting on India.
- उन्होंने 22 वर्षों तक बीबीसी, नई दिल्ली के ब्यूरो प्रमुख के रूप में कार्य किया और भारत पर अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग को आकार दिया।
- He was awarded the Padma Shri in 1992 and the Padma Bhushan in 2005 in the field of Literature and Education for his outstanding contributions.
- उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1992 में पद्म श्री और 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
- In 2002, he was knighted (KBE) by the British government for his exceptional services to journalism.
- वर्ष 2002 में पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें नाइटहुड (KBE) से सम्मानित किया गया।





Ques: When is the 3rd International Day of Clean Energy observed and what is its theme for 2026?

तीसरा अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है और 2026 की इसकी थीम क्या है?

- A) 24 January – Renewable Energy for Future / 24 जनवरी – भविष्य के लिए नवीकरणीय ऊर्जा
- B) 25 January – Sustainable Power for All / 25 जनवरी – सभी के लिए सतत ऊर्जा
- C) 26 January – Clean Energy for People and Planet / 26 जनवरी – लोगों और पृथ्वी के लिए स्वच्छ ऊर्जा
- D) 28 January – Energy Transition for Growth / 28 जनवरी – विकास के लिए ऊर्जा परिवर्तन
- E) 1 February – Green Energy for Climate Action / 1 फरवरी – जलवायु कार्रवाई के लिए हरित ऊर्जा

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The 3rd International Day of Clean Energy is observed on 26 January.
- तीसरा अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है।
- The theme for the year 2026 is “Clean Energy for People and Planet.”
- वर्ष 2026 की थीम है — “लोगों और पृथ्वी के लिए स्वच्छ ऊर्जा।”
- The International Day of Clean Energy was first observed in 2023.
- अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस की शुरुआत वर्ष 2023 में हुई थी।
- The day highlights the importance of clean energy in addressing climate change, promoting sustainable development, and ensuring energy access for all.
- यह दिवस जलवायु परिवर्तन से निपटने, सतत विकास को बढ़ावा देने और सभी के लिए ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करने में स्वच्छ ऊर्जा के महत्व को रेखांकित करता है।





Ques: What is the maximum timeline prescribed by RBI for banks to take credit decisions on loans up to ₹25 lakh for Micro and Small Enterprises?

माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए ₹25 लाख तक के ऋण पर क्रेडिट निर्णय लेने हेतु आरबीआई द्वारा निर्धारित अधिकतम समय-सीमा क्या है?

- A) 7 working days
- B) 10 working days
- C) 14 working days
- D) 21 working days
- E) 30 working days

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The investment and turnover limits for classification of MSMEs have been revised to enable higher efficiency of scale, technology upgradation, better access to capital, and global competitiveness.
- एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमाओं में संशोधन किया गया है ताकि बड़े पैमाने की दक्षता, तकनीकी उन्नयन, पूंजी तक बेहतर पहुंच और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सके।
- As per RBI (informed by DFS), for loans up to ₹25 lakh to Micro and Small Enterprises, banks must take credit decisions within 14 working days.
- डीएफएस द्वारा सूचित आरबीआई के अनुसार, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को ₹25 लाख तक के ऋण के लिए बैंकों को 14 कार्यदिवसों के भीतर क्रेडिट निर्णय लेना होगा।
- For loans above ₹25 lakh, timelines will follow board-approved sanction time norms of banks.
- ₹25 लाख से अधिक के ऋण के लिए समय-सीमा बैंकों के बोर्ड-अनुमोदित स्वीकृति मानकों के अनुसार होगी।
- Banks are required to prominently display MSME credit-related information, timelines, and indicative document checklists on their websites.
- बैंकों को एमएसएमई से जुड़े क्रेडिट विवरण, समय-सीमा और दस्तावेज़ सूची अपनी वेबसाइट पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित करनी होगी।
- Under CGTMSE, loan applications, sanctions, and disbursements under the Credit Guarantee Scheme (CGS) for MSEs are monitored quarterly by the Empowered





Committee on MSME chaired by RBI along with SLBCs.

- सीजीटीएमएसई के तहत, एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (CGS) में ऋण आवेदन, स्वीकृति और वितरण की तिमाही निगरानी आरबीआई अध्यक्षता वाली एमएसएमई सशक्त समिति और एसएलबीसी द्वारा की जाती है।
- The credit guarantee cover for MSEs has been enhanced from ₹5 crore to ₹10 crore with effect from 01.04.2025 under CGS.
- सीजीएस के तहत एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 01.04.2025 से ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दिया गया है।



EXAM
Genius





Ques: Which bank has received RBI approval to open a branch at the International Financial Services Centre (IFSC) in GIFT City, Gujarat?

किस बैंक को गुजरात के GIFT सिटी स्थित इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (IFSC) में शाखा खोलने के लिए RBI की मंजूरी मिली है?

- A) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- B) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- C) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- D) Canara Bank / केनरा बैंक
- E) Punjab & Sind Bank / पंजाब एंड सिंध बैंक

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Punjab & Sind Bank has received approval from the Reserve Bank of India (RBI) to open a branch at the International Financial Services Centre (IFSC) in GIFT City, Gandhinagar, Gujarat.
- पंजाब एंड सिंध बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से गुजरात के गांधीनगर स्थित GIFT सिटी के IFSC में शाखा खोलने की अनुमति मिली है।
- GIFT City IFSC is India's premier international financial hub, created to facilitate cross-border financial transactions.
- GIFT सिटी IFSC भारत का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र है, जिसे सीमा-पार वित्तीय लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है।
- It provides a world-class ecosystem for international trade finance, offshore banking, and capital market activities.
- यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्त, ऑफशोर बैंकिंग और पूंजी बाज़ार गतिविधियों के लिए विश्वस्तरीय ढांचा उपलब्ध कराता है।

About Punjab & Sind Bank :

- Established : 1908
- HQ : New Delhi
- MD & CEO : Swarup Kumar Saha
- Tagline : Where service is a way of life





Ques: As per the revised World Bank International Poverty Line, what was India's extreme poverty rate in 2022–23?

संशोधित विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा के अनुसार 2022–23 में भारत की अत्यधिक गरीबी दर कितनी थी?

- A) 3.1%
- B) 4.5%
- C) 5.3%
- D) 12.9
- E) 23.9%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The World Bank has revised the International Poverty Line (IPL) from USD 2.15 to USD 3.00 per day, adjusted for 2021 Purchasing Power Parity (PPP).
- विश्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा (IPL) को USD 2.15 प्रति दिन से बढ़ाकर USD 3.00 प्रति दिन कर दिया है, जो 2021 की क्रय शक्ति समता (PPP) के अनुसार समायोजित है।
- The revision accounts for changes in global price levels and consumption patterns.
- यह संशोधन वैश्विक मूल्य स्तर और उपभोग पैटर्न में आए बदलावों को दर्शाता है।
- According to the revised IPL, India's extreme poverty rate in 2022–23 stood at 5.3%.
- संशोधित IPL के अनुसार, वर्ष 2022–23 में भारत में अत्यधिक गरीबी दर 5.3% रही।
- India's lower-middle-income poverty rate in 2022–23 was estimated at 23.9%.
- 2022–23 में भारत की निम्न-मध्यम आय वर्ग गरीबी दर 23.9% आंकी गई।
- These estimates are highlighted in the Economic Survey.
- ये अनुमान आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तुत किए गए हैं।





Ques: In which locations will the pilot project of CBDC-based “digital food currency” under the free ration scheme be rolled out?

मुफ्त राशन योजना के तहत CBDC आधारित “डिजिटल फूड करेंसी” की पायलट परियोजना किन स्थानों पर शुरू की जाएगी?

- A) Chandigarh, Puducherry and three districts of Gujarat / चंडीगढ़, पुदुचेरी और गुजरात के तीन जिले
- B) Delhi, Mumbai and Chennai / दिल्ली, मुंबई और चेन्नई
- C) Gujarat and Rajasthan only / केवल गुजरात और राजस्थान
- D) All Union Territories of India / भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेश
- E) Punjab, Haryana and Himachal Pradesh / पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- The Government of India is set to roll out a pilot project for Central Bank Digital Currency (CBDC), also called “digital food currency”, under the free ration scheme.
- भारत सरकार मुफ्त राशन योजना के तहत केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) यानी “डिजिटल फूड करेंसी” का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है।
- The pilot will be implemented in Chandigarh, Puducherry, and three districts of Gujarat.
- यह पायलट चंडीगढ़, पुदुचेरी और गुजरात के तीन जिलों में लागू किया जाएगा।
- Beneficiaries will receive monthly digital food coupons directly into an RBI-enabled digital wallet on their mobile phones.
- लाभार्थियों को उनके मोबाइल फोन पर RBI-सक्षम डिजिटल वॉलेट में मासिक डिजिटल फूड कूपन मिलेंगे।
- Coupons can be redeemed at ration shops by scanning the QR code of the shop owner to obtain free foodgrains.
- राशन दुकानदार के QR कोड को स्कैन कर कूपन भुनाए जा सकेंगे और निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त होगा।
- A soft launch was conducted earlier in Ahmedabad with 25 beneficiaries.
- इससे पहले अहमदाबाद में 25 लाभार्थियों के साथ इसका सॉफ्ट लॉन्च किया गया था।
- The next phase will cover Anand, Sabarmati and Dahod districts of Gujarat.
- अगले चरण में गुजरात के आणंद, साबरमती और दाहोद जिलों को शामिल किया जाएगा।





Ques: Who has issued draft guidelines on resolution plans for borrowers affected by natural disasters?

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित उधारकर्ताओं के लिए समाधान योजनाओं पर मसौदा दिशानिर्देश किसने जारी किए हैं?

- A) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
- B) National Disaster Management Authority / राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
- C) State Governments / राज्य सरकारें
- D) NITI Aayog / नीति आयोग
- E) Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has issued draft guidelines for banks and other regulated entities on resolution plans during natural disasters.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान समाधान योजनाओं को लेकर बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- The framework will be applicable from April 1, and RBI has invited public and stakeholder feedback until February 17.
- यह ढांचा 1 अप्रैल से लागू होगा और RBI ने 17 फरवरी तक सार्वजनिक एवं हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।
- The proposed framework requires banks to proactively plan for natural calamities while framing their credit policies, instead of relying on ad hoc relief measures.
- प्रस्तावित ढांचे के तहत बैंकों को तदर्थ राहत उपायों के बजाय क्रेडिट नीतियाँ बनाते समय प्राकृतिक आपदाओं के लिए अग्रिम योजना बनानी होगी।
- Banks will need to assess climate risks in advance and prepare pre-defined resolution mechanisms.
- बैंकों को जलवायु जोखिमों का पूर्व मूल्यांकन कर पूर्व-निर्धारित समाधान तंत्र तैयार करना होगा।
- RBI has clarified that only standard borrowers will be eligible for relief.
- RBI ने स्पष्ट किया है कि केवल मानक (स्टैंडर्ड) उधारकर्ता ही राहत के पात्र होंगे।
- Borrowers who have not defaulted for more than 30 days at the time of the disaster will qualify for relief.
- आपदा के समय जिन उधारकर्ताओं ने 30 दिनों से अधिक की चूक नहीं की है, वे राहत के लिए पात्र होंगे।





Ques: At the end of December 2025, India's fiscal deficit stood at what percentage of the FY26 Budget Estimate?

दिसंबर 2025 के अंत तक भारत का राजकोषीय घाटा FY26 के बजट अनुमान का कितना प्रतिशत था?

- A) 48.0%
- B) 50.2%
- C) 52.8%
- D) 54.5%
- E) 56.7%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- At the end of December 2025, India's fiscal deficit stood at ₹8.55 lakh crore, which was 54.5% of the FY26 Budget Estimate.
- दिसंबर 2025 के अंत तक भारत का राजकोषीय घाटा ₹8.55 लाख करोड़ रहा, जो FY26 के बजट अनुमान का 54.5% था।
- This level was lower than the 56.7% of the annual target recorded during the same period in the previous year.
- यह पिछले वर्ष की समान अवधि में दर्ज 56.7% के स्तर से कम था।
- The improvement in fiscal position was driven by stronger tax revenues and a fiscal surplus recorded in December.
- राजकोषीय स्थिति में यह सुधार मजबूत कर राजस्व और दिसंबर में दर्ज राजकोषीय अधिशेष के कारण हुआ।
- Gross tax revenues rose sharply by 32.3% in December, taking overall growth during April–December to 8.5%.
- दिसंबर में सकल कर राजस्व 32.3% बढ़ा, जिससे अप्रैल–दिसंबर अवधि की कुल वृद्धि 8.5% हो गई।
- Capital expenditure growth slowed during this period, which helped in containing the fiscal deficit.
- इस अवधि में पूंजीगत व्यय की वृद्धि धीमी रही, जिससे राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में मदद मिली।
- The government has targeted limiting the full-year FY26 fiscal deficit to 4.4% of GDP.
- सरकार ने पूरे FY26 के लिए राजकोषीय घाटे को GDP के 4.4% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है।





Ques: Who is set to become the first woman Deputy Chief Minister of Maharashtra?

महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री कौन बनने जा रही हैं?

- A) Supriya Sule / सुप्रिया सुले
- B) Sunetra Pawar / सुनेत्रा पवार
- C) Pankaja Munde / पंकजा मुंडे
- D) Rohini Khadse / रोहिणी खडसे
- E) Amruta Fadnavis / अमृता फडणवीस

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Sunetra Pawar is set to become the first woman Deputy Chief Minister of Maharashtra, creating history in the state's political landscape.
- सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, जिससे राज्य की राजनीति में इतिहास रचेगा।
- She is the wife of senior Nationalist Congress Party (NCP) leader Ajit Pawar.
- वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता अजित पवार की पत्नी हैं।
- The decision was taken unanimously by the NCP leadership.
- यह निर्णय NCP नेतृत्व द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।
- The Maharashtra government has assured its support to the NCP's decision.
- महाराष्ट्र सरकार ने NCP के इस निर्णय को समर्थन देने का आश्वासन दिया है।
- With this appointment, Sunetra Pawar will become the first woman to hold the post of Deputy Chief Minister in Maharashtra.
- इस नियुक्ति के साथ सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र में उपमुख्यमंत्री पद संभालने वाली पहली महिला बन जाएंगी।





Ques: As on January 24, 2026, what percentage of rural households have tap water supply under Jal Jeevan Mission?

24 जनवरी 2026 तक जल जीवन मिशन के तहत कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल से जल आपूर्ति उपलब्ध है?

- A) 65%
- B) 72%
- C) 75%
- D) 81.56%
- E) 90%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- Jal Jeevan Mission (JJM) has been implemented since August 2019 by the Government of India in partnership with States to provide potable tap water to every rural household.
- जल जीवन मिशन (JJM) अगस्त 2019 से भारत सरकार द्वारा राज्यों के सहयोग से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया है।
- The total estimated outlay of the Mission is ₹3.60 लाख करोड़, of which the Central share is ₹2.08 लाख करोड़.
- मिशन का कुल अनुमानित परिव्यय ₹3.60 लाख करोड़ है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा ₹2.08 लाख करोड़ है।
- At the launch of the Mission, only 3.23 करोड़ (17%) rural households had tap water connections.
- मिशन की शुरुआत के समय केवल 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण घरों में नल से जल कनेक्शन था।
- As reported by States and Union Territories, about 12.56 करोड़ additional rural households were provided tap water connections till 24.01.2026.
- राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के अनुसार, 24.01.2026 तक लगभग 12.56 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घरों को नल से जल कनेक्शन दिया गया है।
- As on 24.01.2026, out of 19.36 करोड़ rural households, more than 15.79 करोड़ households have tap water supply at home, which is 81.56% coverage.
- 24.01.2026 तक कुल 19.36 करोड़ ग्रामीण घरों में से 15.79 करोड़ से अधिक घरों (81.56%) में नल से जल आपूर्ति उपलब्ध है।
- Water is a State subject, and the implementation as well as saturation plans are carried out by the respective States and Union Territories.
- जल एक राज्य विषय है, तथा इसका कार्यान्वयन और संतृप्ति योजना संबंधित राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा की जाती है।



Ques: Which cricketer has been provisionally banned by the International Cricket Council (ICC) under its Anti-Corruption Code?

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने भ्रष्टाचार रोधी संहिता के तहत किस क्रिकेटर को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया है?

- A) Shai Hope / शाई होप
- B) Nicholas Pooran / निकोलस पूरन
- C) David Warner / डेविड वॉर्नर
- D) Aaron Jones / एरॉन जोन्स
- E) Jason Holder / जेसन होल्डर

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The International Cricket Council (ICC) has provisionally banned USA batter Aaron Jones from all formats of cricket under its Anti-Corruption Code.
- अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने अमेरिका के बल्लेबाज़ एरॉन जोन्स को भ्रष्टाचार रोधी संहिता के तहत सभी प्रारूपों से अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया है।
- Aaron Jones faces five charges related to alleged breaches of anti-corruption rules under both the ICC and Cricket West Indies (CWI) codes.
- एरॉन जोन्स पर ICC और क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) की भ्रष्टाचार रोधी संहिताओं के तहत पाँच आरोप लगाए गए हैं।
- He has been given 14 days from 28 January 2026 to submit a formal response to the charges.
- उन्हें आरोपों पर औपचारिक जवाब देने के लिए 28 जनवरी 2026 से 14 दिन का समय दिया गया है।
- Due to the suspension, he is ineligible for selection in the 2026 ICC Men's T20 World Cup, which begins on 7 February 2026.
- इस प्रतिबंध के कारण वह 7 फरवरी 2026 से शुरू होने वाले ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए चयन के अयोग्य हो गए हैं।





Ques: Which PSU secured the 'Great Place to Work' certification for the third consecutive year (2026–27)?

किस PSU को 2026–27 के लिए लगातार तीसरी बार 'ग्रेट प्लेस टू वर्क' प्रमाणन प्राप्त हुआ है?

- A) BHEL / भेल
- B) ONGC / ओएनजीसी
- C) GAIL / गेल
- D) NTPC / एनटीपीसी
- E) Steel Authority of India Limited (SAIL) / स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Steel Authority of India Limited (SAIL) has secured the 'Great Place to Work' certification for the period February 2026 to February 2027 for the third consecutive year.
- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) को फरवरी 2026 से फरवरी 2027 की अवधि के लिए लगातार तीसरी बार 'ग्रेट प्लेस टू वर्क' प्रमाणन प्राप्त हुआ है।
- SAIL is a Maharatna Public Sector Undertaking (PSU) and India's largest public sector steel manufacturer under the Ministry of Steel.
- SAIL एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है और इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील उत्पादक कंपनी है।
- The certification was awarded after a company-wide assessment conducted by the Great Place to Work Institute, India.
- यह प्रमाणन ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट, इंडिया द्वारा किए गए कंपनी-स्तरीय मूल्यांकन के बाद प्रदान किया गया।
- SAIL recorded a significant improvement in its TRUST INDEX© score, reflecting strong workplace culture and positive employee feedback.
- SAIL के TRUST INDEX© स्कोर में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जो मजबूत कार्यस्थल संस्कृति और कर्मचारियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाता है।
- The recognition highlights SAIL's focus on transparent, performance-driven HR practices and employee initiatives such as 'SAIL DARPAN'.
- यह सम्मान पारदर्शी, प्रदर्शन-आधारित HR प्रथाओं और 'SAIL DARPAN' जैसे कर्मचारी विकास कार्यक्रमों के प्रति SAIL की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।





Ques: How many tableaux participated in the 77th Republic Day Parade 2026 on Kartavya Path?

77वें गणतंत्र दिवस परेड 2026 में कर्तव्य पथ पर कुल कितनी झांकियाँ (टैब्लो) प्रदर्शित की गईं?

- A) 25 tableaux
- B) 27 tableaux
- C) 28 tableaux
- D) 30 tableaux
- E) 32 tableaux

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- A total of 30 tableaux rolled down Kartavya Path during the 77th Republic Day Parade 2026.
- 77वें गणतंत्र दिवस परेड 2026 में कर्तव्य पथ पर कुल 30 झांकियाँ प्रदर्शित की गईं।
- These included 17 tableaux from States and Union Territories and 13 tableaux from Ministries, Departments and Services
- इनमें शामिल थीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 17 झांकियाँ और मंत्रालयों, विभागों और सेवाओं की 13 झांकियाँ
- The overall theme of the Republic Day tableaux revolved around two core ideas “Svatantrata Ka Mantra – Vande Mataram” and “Samriddhi Ka Mantra – Aatmanirbhar Bharat”
- गणतंत्र दिवस झांकियों की मुख्य थीम थी “स्वतंत्रता का मंत्र – वंदे मातरम्” और “समृद्धि का मंत्र – आत्मनिर्भर भारत”
- The winners of the tableaux are selected by an expert jury constituted by the Ministry of Defence.
- झांकियों के विजेताओं का चयन रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ जूरी द्वारा किया जाता है।
- Additionally, a Popular Choice Award is given based on public voting through platforms like MyGov and SMS-based systems.
- इसके अतिरिक्त, MyGov और SMS आधारित मतदान के माध्यम से पॉपुलर चॉइस अवार्ड भी दिया जाता है।
- States not selected for the main parade can showcase their tableaux at Bharat Parv, held at the Red Fort from January 26 to 31.
- मुख्य परेड में चयन न होने वाले राज्य 26–31 जनवरी तक लाल किले में आयोजित भारत पर्व में अपनी झांकियाँ प्रदर्शित कर सकते हैं।





Official Awards (Judges' Panel) :

- Best Marching Contingent (Services) (1st) - Indian Navy
- Best Marching Contingent (CAPF / Auxiliary Forces) (1st) - Delhi Police
- Best Tableau (States/UTs) (1st) - Maharashtra (Ganeshotsav: A Symbol of Aatmanirbharta)
- Best Tableau (States/UTs) (2nd) - Jammu & Kashmir (Handicrafts and Folk Dances of J&K)
- Best Tableau (States/UTs) (3rd) - Kerala (Water Metro & 100% Digital Literacy)
- Best Tableau (Central Ministries) - Ministry of Culture (Vande Mataram – The Soul Cry of a Nation)
- Special Prize - Central Public Works Department (CPWD) (Vande Mataram – Commemoration of 150 Years)
- Best Cultural Performance - Vande Mataram: The Eternal Resonance of India (Dance Presentation)

Popular Choice Awards (MyGov Public Voting) :

- Best Marching Contingent (Services) (1st) - Assam Regiment
- Best Marching Contingent (CAPF / Auxiliary Forces) (1st) - CRPF
- Best Tableau (States/UTs) (1st) - Gujarat (4th Consecutive Year) (Mantra of Swadeshi – Self-Reliance – Freedom)
- Best Tableau (States/UTs) (2nd) - Uttar Pradesh (Culture of Bundelkhand)
- Best Tableau (States/UTs) (3rd) - Rajasthan (Golden Touch of the Desert: Bikaner Gold Art) (Usta Art)
- Best Tableau (Central Ministries) - Dept. of School Education & Literacy (National Education Policy 2020)





Ques: Which of the following personalities will be honoured with the Uttar Pradesh Gaurav Samman 2026 during Uttar Pradesh Day 2026?

निम्नलिखित में से किन व्यक्तित्वों को उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के अवसर पर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2026 से सम्मानित किया जाएगा?

- A) Wing Commander Shubhanshu Shukla / विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला
- B) Alakh Pandey / आलख पांडे
- C) Dr Hariom Panwar / डॉ. हरिओम पंवार
- D) Rashmi Arya / रश्मि आर्य
- E) All of the above / उपरोक्त सभी

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- The Uttar Pradesh Government will honour five distinguished personalities with the Uttar Pradesh Gaurav Samman during Uttar Pradesh Day 2026.
- उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के अवसर पर पाँच विशिष्ट व्यक्तित्वों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी।
- The award recognises outstanding contributions in diverse fields and highlights the achievements of individuals who have brought pride to Uttar Pradesh.
- यह सम्मान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है और उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करता है।

• Awardees – Uttar Pradesh Gaurav Samman 2026:

- Wing Commander Shubhanshu Shukla – Space Science
- Alakh Pandey – Education
- Dr Hariom Panwar – Literature & Education
- Rashmi Arya – Women Empowerment
- Dr Sudhanshu Singh – Agriculture

• पुरस्कार विजेता – उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2026:

- विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला – अंतरिक्ष विज्ञान
- आलख पांडे – शिक्षा
- डॉ. हरिओम पंवार – साहित्य एवं शिक्षा
- रश्मि आर्य – महिला सशक्तिकरण





Ques: The recently completed 100 m long 'Make in India' steel bridge is associated with which project?

हाल ही में पूरा किया गया 100 मीटर लंबा 'मेक इन इंडिया' स्टील ब्रिज किस परियोजना से संबंधित है?

- A) Delhi–Meerut RRTS / दिल्ली–मेरठ आरआरटीएस
- B) Mumbai–Nagpur Samruddhi Expressway / मुंबई–नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे
- C) Mumbai–Ahmedabad Bullet Train Project / मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना
- D) Ahmedabad Metro Phase-II / अहमदाबाद मेट्रो चरण-II
- E) Dedicated Freight Corridor / डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- A 100-metre-long 'Make in India' steel bridge has been successfully completed in Ahmedabad district for the Mumbai–Ahmedabad Bullet Train Project.
- मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए अहमदाबाद जिले में 100 मीटर लंबा 'मेक इन इंडिया' स्टील ब्रिज सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।
- This is the 13th steel bridge completed in Gujarat out of a total of 17 steel bridges planned in the state.
- यह गुजरात में नियोजित कुल 17 स्टील ब्रिजों में से पूरा किया गया 13वां स्टील ब्रिज है।
- The bridge has been constructed over an underground metro tunnel connecting Kalupur and Shahpur metro stations.
- यह ब्रिज कालूपुर और शाहपुर मेट्रो स्टेशनों को जोड़ने वाली भूमिगत मेट्रो सुरंग के ऊपर बनाया गया है।
- To avoid load transfer to the metro tunnel, the span length was increased to about 100 metres and the structure was redesigned as a Steel Truss Bridge.
- मेट्रो सुरंग पर भार न पड़े, इसके लिए स्पैन लंबाई लगभग 100 मीटर की गई और संरचना को स्टील ट्रस ब्रिज के रूप में पुनः डिज़ाइन किया गया।
- The bridge was assembled at a height of 16.5 metres on temporary trestles and later placed on permanent supports.
- ब्रिज को 16.5 मीटर की ऊँचाई पर अस्थायी ट्रेस्टल्स पर जोड़ा गया और बाद में स्थायी सपोर्ट पर स्थापित किया गया।
- The project strengthens high-speed rail connectivity while ensuring the safety of existing urban transport infrastructure.
- यह परियोजना हाई-स्पीड रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करती है और मौजूदा शहरी परिवहन ढांचे की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है।



Ques: Which organisation has been formally designated as a terrorist organisation by the European Union, marking a major escalation in its policy towards Iran?

यूरोपीय संघ ने ईरान के प्रति अपनी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए किस संगठन को औपचारिक रूप से आतंकवादी संगठन घोषित किया है?

- A) Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) / इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC)
- B) Hamas / हमास
- C) Hezbollah / हिज़्बुल्लाह
- D) Al-Qaeda / अल-कायदा
- E) Houthis / हूती

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- The European Union (EU) has formally designated Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) as a terrorist organisation.
- यूरोपीय संघ (EU) ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को आतंकवादी संगठन घोषित किया है।
- This decision marks a sharp escalation in EU policy towards Tehran.
- यह फैसला तेहरान के प्रति EU की नीति में बड़ा कड़ा कदम माना जा रहा है।
- The IRGC was established after the 1979 Islamic Revolution to safeguard Iran's clerical (theocratic) system.
- IRGC की स्थापना 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान की धार्मिक शासन प्रणाली की रक्षा के लिए की गई थी।
- Under EU law, the IRGC is now placed in the same legal terrorism category as al-Qaeda and ISIS, despite being a state-linked military force, unlike non-state militant groups.
- EU क़ानून के तहत IRGC को अब अल-कायदा और ISIS जैसे संगठनों की श्रेणी में रखा गया है, जबकि IRGC एक राज्य से जुड़ी सैन्य शक्ति है।





Ques: Coking Coal has been notified as a Critical and Strategic Mineral under which Act?

कोकिंग कोल को किस अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज घोषित किया गया है?

- A) Coal Mines Act, 1973 / कोयला खान अधिनियम, 1973
- B) MMDR Act, 1957 / MMDR अधिनियम, 1957
- C) Environment Protection Act, 1986 / पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
- D) National Steel Policy, 2017 / राष्ट्रीय स्टील नीति, 2017
- E) Mines Act, 1952 / खान अधिनियम, 1952

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Government of India has notified Coking Coal as a Critical and Strategic Mineral under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.
- भारत सरकार ने कोकिंग कोल को खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज घोषित किया है।
- This decision supports the vision of Aatmanirbhar Bharat and Viksit Bharat 2047 by strengthening domestic mineral security.
- यह निर्णय आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को समर्थन देता है।
- The move is based on recommendations of the High-Level Committee on Viksit Bharat goals and policy inputs from NITI Aayog.
- यह कदम विकसित भारत लक्ष्यों पर उच्च-स्तरीय समिति और नीति आयोग के सुझावों के आधार पर लिया गया है।
- India has around 37.37 billion tonnes of coking coal resources, mainly concentrated in Jharkhand, with reserves also in Madhya Pradesh, West Bengal, and Chhattisgarh.
- भारत में लगभग 37.37 बिलियन टन कोकिंग कोल संसाधन हैं, जिनका प्रमुख हिस्सा झारखंड में तथा अन्य भंडार मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में हैं।
- Despite domestic availability, nearly 95% of the steel sector's coking coal requirement is met through imports.
- घरेलू उपलब्धता के बावजूद, स्टील क्षेत्र की लगभग 95% कोकिंग कोल आवश्यकता आयात से पूरी होती है।
- Declaring coking coal as a critical mineral will enable faster approvals, promote ease of doing business, accelerate exploration and mining, and reduce import dependence while supporting the National Steel Policy.
- कोकिंग कोल को महत्वपूर्ण खनिज घोषित करने से तेज़ मंजूरी, ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस, खोज एवं खनन में तेजी आएगी, आयात निर्भरता घटेगी और राष्ट्रीय स्टील नीति को समर्थन मिलेगा।





Ques: The PM SVANidhi Credit Card launched by the Prime Minister aims to provide formal credit access to which group?

प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया PM SVANidhi क्रेडिट कार्ड किस वर्ग को औपचारिक ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए है?

- A) Small farmers / छोटे किसान
- B) Self-help group members / स्वयं सहायता समूह सदस्य
- C) Street vendors / रेहड़ी-पटरी विक्रेता
- D) MSME owners / एमएसएमई उद्यमी
- E) Gig workers / गिग वर्कर्स

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Prime Minister of India launched the PM SVANidhi Credit Card to provide easy and formal credit access to street vendors.
- भारत के प्रधानमंत्री ने रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को आसान एवं औपचारिक ऋण सुविधा देने के लिए PM SVANidhi क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया।
- Eligibility: The credit card is available to street vendors who have successfully repaid the second tranche loan and are eligible for the third tranche under the PM SVANidhi Scheme.
- पात्रता: यह कार्ड उन रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के लिए है जिन्होंने दूसरी किश्त का ऋण चुका दिया है और तीसरी किश्त के लिए पात्र हैं।
- **Credit Features:**
 - Type: RuPay retail (personal) credit card
 - Credit Limit: ₹30,000
 - Facility: Revolving credit (amount can be reused after repayment)
- क्रेडिट की विशेषताएँ:
 - प्रकार: रूपे रिटेल (पर्सनल) क्रेडिट कार्ड
 - क्रेडिट सीमा: ₹30,000
 - सुविधा: रिवॉल्विंग क्रेडिट (चुकाने के बाद पुनः उपयोग संभव)





- Objectives: Promote financial inclusion, reduce dependence on informal moneylenders, encourage digital transactions and credit discipline, and support small livelihoods.
- उद्देश्य: वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, अनौपचारिक साहूकारों पर निर्भरता कम करना, डिजिटल लेन-देन और क्रेडिट अनुशासन को प्रोत्साहित करना तथा छोटी आजीविकाओं को समर्थन देना।

About PM SVANidhi Scheme | PM SVANidhi योजना के बारे में:

- PM SVANidhi stands for Prime Minister Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi.
- PM SVANidhi का पूर्ण रूप है — Prime Minister Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi
- It was launched in 2020 as a Central Sector Scheme to provide affordable working capital loans to street vendors affected by the COVID-19 lockdown.
- इसे 2020 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य COVID-19 लॉकडाउन से प्रभावित रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है।
- The scheme is implemented by the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) and the Department of Financial Services (DFS).
- इस योजना का क्रियान्वयन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) और वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा किया जाता है।

EXAM
Genius





Ques: INOXGFL Group signed MoUs worth ₹17,000 crore to invest in the renewable energy sector with which state governments?

INOXGFL Group ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ₹17,000 करोड़ के निवेश हेतु किन राज्य सरकारों के साथ समझौते (MoUs) पर हस्ताक्षर किए?

- A) Maharashtra, Gujarat and Rajasthan / महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान
- B) Uttar Pradesh, Assam and Kerala / उत्तर प्रदेश, असम और केरल
- C) Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh / तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश
- D) Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh / राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
- E) Odisha, West Bengal and Bihar / ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- INOXGFL Group signed three Memoranda of Understanding (MoUs) worth ₹17,000 crore to invest in the renewable energy sector.
- INOXGFL Group ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ₹17,000 करोड़ के निवेश हेतु तीन समझौता ज्ञापन (MoUs) पर हस्ताक्षर किए।
- The MoUs were signed with the governments of Uttar Pradesh, Assam and Kerala.
- ये समझौते उत्तर प्रदेश, असम और केरल की राज्य सरकारों के साथ किए गए।
- The agreements were signed at the World Economic Forum (WEF) Summit held in Davos, Switzerland.
- इन समझौतों पर दावोस, स्विट्ज़रलैंड में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (WEF) शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए।

• State-wise Investment Details:

- Uttar Pradesh: ₹10,500 crore (initial agreement)
- Assam & Kerala: Combined investment of ₹6,500 crore

• राज्यवार निवेश विवरण:

- उत्तर प्रदेश: ₹10,500 करोड़ (प्रारंभिक समझौता)
- असम और केरल: संयुक्त रूप से ₹6,500 करोड़





Ques: What is India's Global Innovation Index (GII) rank in 2025?

2025 में भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) रैंक क्या है?

- A) 66th
- B) 55th
- C) 45th
- D) 38th
- E) 30th

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- India's Global Innovation Index (GII) rank improved to 38th in 2025 from 66th in 2019, indicating steady strengthening of the country's innovation performance.
- भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) रैंक 2019 में 66वें स्थान से सुधरकर 2025 में 38वें स्थान पर पहुंच गई है, जो देश की नवाचार क्षमता में निरंतर सुधार को दर्शाती है।
- This improvement reflects progress in innovation ecosystems, research, and technological capabilities.
- यह सुधार नवाचार इकोसिस्टम, अनुसंधान और तकनीकी क्षमताओं में प्रगति को दर्शाता है।
- The India Semiconductor Mission has approved 10 semiconductor manufacturing and packaging projects across 6 States.
- इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 6 राज्यों में 10 सेमीकंडक्टर निर्माण एवं पैकेजिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
- These projects involve an investment of about ₹1.60 lakh crore.
- इन परियोजनाओं में लगभग ₹1.60 लाख करोड़ का निवेश शामिल है।
- The approved projects aim to strengthen India's domestic semiconductor manufacturing and packaging capabilities.
- स्वीकृत परियोजनाओं का उद्देश्य भारत की घरेलू सेमीकंडक्टर निर्माण एवं पैकेजिंग क्षमता को मजबूत करना है।
- Together, the rise in GII ranking and progress under the Semiconductor Mission highlight India's growing focus on innovation-driven and technology-led development.
- GII रैंक में सुधार और सेमीकंडक्टर मिशन की प्रगति मिलकर नवाचार आधारित एवं प्रौद्योगिकी-प्रेरित विकास पर भारत के बढ़ते फोकस को दर्शाते हैं।





Ques: Why did the Bombay Natural History Society (BNHS) sign a five-year MoU with the Chief Wildlife Warden of Jharkhand?

बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) ने झारखंड के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के साथ पाँच वर्षीय समझौता (MoU) क्यों किया?

- A) To promote eco-tourism in Jharkhand / झारखंड में इको-टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए
- B) To conserve critically endangered vulture species / गंभीर रूप से संकटग्रस्त गिद्ध प्रजातियों के संरक्षण के लिए
- C) To establish new wildlife sanctuaries / नए वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना के लिए
- D) To conduct a nationwide bird census / राष्ट्रीय स्तर पर पक्षी जनगणना कराने के लिए
- E) To promote commercial bird breeding / व्यावसायिक पक्षी प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Bombay Natural History Society (BNHS) has signed a five-year Memorandum of Understanding with the Chief Wildlife Warden of Jharkhand.
- बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) ने झारखंड के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के साथ पाँच वर्ष का समझौता ज्ञापन (MoU) किया है।
- The objective of the MoU is to strengthen the conservation of critically endangered vulture species in the state.
- इस MoU का उद्देश्य राज्य में गंभीर रूप से संकटग्रस्त गिद्ध प्रजातियों के संरक्षण को सुदृढ़ करना है।
- The agreement focuses on scientific breeding, monitoring, capacity-building, and long-term protection of vultures.
- यह समझौता गिद्धों के वैज्ञानिक प्रजनन, निगरानी, क्षमता निर्माण और दीर्घकालिक संरक्षण पर केंद्रित है।
- The two critically endangered vulture species covered under the MoU are the Oriental White-backed Vulture and the Long-billed Vulture.
- इस समझौते के अंतर्गत शामिल दो गंभीर रूप से संकटग्रस्त गिद्ध प्रजातियाँ हैं — ओरिएंटल व्हाइट-बैकड गिद्ध और लॉन्ग-बिल्ड गिद्ध।





Ques: Cashless Treatment for Road Accident Victims Scheme, 2025 has been notified under which provision of the Motor Vehicles Act?

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 2025 मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अधिसूचित की गई है?

- A) Section 146 of Motor Vehicles Act
- B) Section 159 of Motor Vehicles Act
- C) Section 162 of Motor Vehicles Act
- D) Section 164 of Motor Vehicles Act
- E) Section 166 of Motor Vehicles Act

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Cashless Treatment for Road Accident Victims Scheme, 2025 has been notified under Section 162 of the Motor Vehicles Act, 1988.
- सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 2025 को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।
- The scheme provides cashless medical treatment up to ₹1.5 lakh per victim for a maximum period of 7 days from the date of accident.
- इस योजना के अंतर्गत प्रति पीड़ित अधिकतम ₹1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों तक प्रदान किया जाएगा।
- All motor vehicle road accident victims are eligible under the scheme, irrespective of the type of road or vehicle involved.
- सड़क या वाहन की श्रेणी की परवाह किए बिना सभी मोटर वाहन सड़क दुर्घटना पीड़ित इस योजना के पात्र होंगे।
- Stabilisation treatment is provided for up to 24 hours in non-life-threatening cases and up to 48 hours in life-threatening cases.
- गैर-जीवन-घातक मामलों में 24 घंटे तक और जीवन-घातक मामलों में 48 घंटे तक स्थिरीकरण उपचार प्रदान किया जाएगा।
- The scheme is implemented through the integration of eDAR (electronic Detailed Accident Report) and TMS 2.0 platforms.
- यह योजना eDAR (इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट) और TMS 2.0 प्लेटफॉर्म के एकीकरण के माध्यम से लागू की जा रही है।



Ques: Which district became the first in India to implement online property tax collection through the SAMARTH Panchayat portal?

कौन-सा जिला SAMARTH पंचायत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संपत्ति कर संग्रह लागू करने वाला भारत का पहला जिला बना है?

- A) Raipur, Chhattisgarh / रायपुर, छत्तीसगढ़
- B) Durg, Chhattisgarh / दुर्ग, छत्तीसगढ़
- C) Bilaspur, Chhattisgarh / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
- D) Dhamtari, Chhattisgarh / धमतरी, छत्तीसगढ़
- E) Bastar, Chhattisgarh / बस्तर, छत्तीसगढ़

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- Dhamtari district in Chhattisgarh has become the first district in India to implement online property tax collection through the SAMARTH Panchayat portal.
- छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला SAMARTH पंचायत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संपत्ति कर संग्रह लागू करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है।
- The initiative was launched on January 29, 2026, at Saankra (Sankara) Gram Panchayat in Nagri block.
- इस पहल की शुरुआत 29 जनवरी 2026 को नगरी ब्लॉक के सांकरा ग्राम पंचायत में की गई।
- The digital property tax collection system has been rolled out across nearly 400 gram panchayats in the district.
- यह डिजिटल संपत्ति कर संग्रह प्रणाली जिले की लगभग 400 ग्राम पंचायतों में लागू की गई है।





Ques: From which date will the Solid Waste Management (SWM) Rules, 2026 come into effect?

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026 किस तिथि से लागू होंगे?

- A) 1 January 2026
- B) 1 March 2026
- C) 1 April 2026
- D) 15 April 2026
- E) 1 July 2026

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Government of India has notified the Solid Waste Management (SWM) Rules, 2026, which will come into force from 1 April 2026.
- भारत सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026 को अधिसूचित किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे।
- The rules have been issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC).
- ये नियम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा जारी किए गए हैं।
- The SWM Rules, 2026 integrate the principles of Circular Economy and Extended Producer Responsibility (EPR).
- SWM नियम, 2026 में सर्कुलर इकोनॉमी और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) के सिद्धांतों को शामिल किया गया है।
- Four-stream segregation of solid waste at source has been made mandatory.
- स्रोत पर ठोस कचरे का चार-धारा पृथक्करण अनिवार्य किया गया है।
- Environmental compensation will be imposed based on the 'Polluter Pays' principle for non-compliance.
- अनुपालन न करने पर 'Polluter Pays' सिद्धांत के आधार पर पर्यावरणीय मुआवजा लगाया जाएगा।
- Penalties include violations such as operating without registration, false reporting, and improper waste management practices.
- दंड में बिना पंजीकरण संचालन, गलत रिपोर्टिंग, और अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन जैसे उल्लंघन शामिल हैं।
- The rules introduce graded development criteria around solid waste processing and disposal facilities to enable faster land allocation.



Ques: In Agriculture Year 2024–25, which sector recorded higher production in India?

कृषि वर्ष 2024–25 में भारत में किस क्षेत्र का उत्पादन अधिक रहा?

- A) Foodgrains / खाद्यान्न
- B) Pulses / दलहन
- C) Oilseeds / तिलहन
- D) Horticulture / बागवानी
- E) Cotton / कपास

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- India's foodgrain production in Agriculture Year (AY) 2024–25 is estimated at 357.7 million tonnes (MT).
- कृषि वर्ष 2024–25 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 357.7 मिलियन टन (MT) रहने का अनुमान है।
- The increase in foodgrain output is attributed to a good monsoon and higher production of rice, wheat, maize, and coarse cereals.
- खाद्यान्न उत्पादन में यह वृद्धि अच्छे मानसून तथा चावल, गेहूं, मक्का और मोटे अनाजों के अधिक उत्पादन के कारण हुई है।
- Horticulture production in 2024–25 reached 362.08 million tonnes (MT).
- 2024–25 में बागवानी उत्पादन 362.08 मिलियन टन (MT) तक पहुंच गया।
- Horticulture output surpassed foodgrain production, highlighting increasing diversification in Indian agriculture.
- बागवानी उत्पादन ने खाद्यान्न उत्पादन को पीछे छोड़ दिया, जो भारतीय कृषि में बढ़ते विविधीकरण को दर्शाता है।
- Horticulture contributes about 33% of agricultural Gross Value Added (GVA), emerging as a key driver of agricultural growth.
- बागवानी कृषि सकल मूल्य वर्धन (GVA) में लगभग 33% का योगदान देती है और कृषि विकास का प्रमुख चालक बनकर उभरी है।





Ques: Which organisation launched the ACASA-India digital platform while reviewing 15 years of the NICRA programme?

किस संगठन ने NICRA कार्यक्रम के 15 वर्ष पूरे होने पर ACASA-India डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया?

- A) Indian Council of Agricultural Research (ICAR) / भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
- B) NITI Aayog / नीति आयोग
- C) Ministry of Agriculture & Farmers Welfare / कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
- D) Food and Agriculture Organization (FAO) / खाद्य एवं कृषि संगठन
- E) Indian Meteorological Department (IMD) / भारतीय मौसम विज्ञान विभाग

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) reviewed the progress of the National Innovations in Climate Resilient Agriculture (NICRA) programme, which has completed 15 years, and launched the ACASA-India digital platform.
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने राष्ट्रीय जलवायु-सहिष्णु कृषि नवाचार (NICRA) कार्यक्रम के 15 वर्ष पूरे होने पर उसकी प्रगति की समीक्षा की और ACASA-India डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।
- The review was conducted during a workshop organised by ICAR and the Borlaug Institute for South Asia (BISA).
- यह समीक्षा ICAR और बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया (BISA) द्वारा आयोजित कार्यशाला के दौरान की गई।
- M L Jat, Director General (DG), ICAR and Secretary, Department of Agricultural Research and Education (DARE), was a key figure in the initiative.
- एम. एल. जाट, ICAR के महानिदेशक (DG) एवं कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (DARE) के सचिव, इस पहल से जुड़े प्रमुख व्यक्ति रहे।
- The programme covers 200+ locations across 151 climate-vulnerable districts.
- यह कार्यक्रम 151 जलवायु-संवेदनशील जिलों में 200 से अधिक स्थानों को कवर करता है।
- Its objective is to enhance the climate resilience of Indian agriculture, with a focus on droughts, floods, heat stress, cyclones, and rainfed farming systems.
- इसका उद्देश्य भारतीय कृषि की जलवायु सहनशीलता बढ़ाना है, विशेष रूप से सूखा, बाढ़, हीट स्ट्रेस, चक्रवात और वर्षा आधारित कृषि प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करना।
- NICRA stands for National Innovations in Climate Resilient Agriculture.





Ques: Which state presented India's first elderly budget linking local body funds to the senior citizen population?

किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों की आबादी से स्थानीय निकाय फंड को जोड़ते हुए भारत का पहला बुजुर्ग बजट प्रस्तुत किया?

- A) Tamil Nadu / तमिलनाडु
- B) Kerala / केरल
- C) Maharashtra / महाराष्ट्र
- D) Karnataka / कर्नाटक
- E) Odisha / ओडिशा

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Kerala has presented India's first-ever budget exclusively focused on senior citizens.
- केरल ने वरिष्ठ नागरिकों पर केंद्रित भारत का पहला विशेष बुजुर्ग बजट प्रस्तुत किया है।
- The budget proposes linking the devolution of funds to local bodies with the proportion of senior citizens in the population.
- इस बजट में स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले फंड को वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या के अनुपात से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है।
- The initiative aims to strengthen welfare services such as healthcare, social security, and elderly care infrastructure at the grassroots level.
- इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा और बुजुर्ग देखभाल अवसंरचना को मजबूत करना है।
- Kerala has one of the highest proportions of elderly population in India, making age-responsive budgeting especially important.
- केरल में भारत में बुजुर्ग आबादी का अनुपात सबसे अधिक है, जिससे आयु-संवेदनशील बजटिंग अत्यंत आवश्यक हो जाती है।
- The initiative aligns with Kerala's broader focus on inclusive governance and effective management of demographic transition.
- यह पहल समावेशी शासन और जनसांख्यिकीय परिवर्तन के प्रभावी प्रबंधन पर केरल के व्यापक फोकस के अनुरूप है।





Ques: Where is the Beating Retreat ceremony usually held in India?

भारत में बीटिंग रिट्रीट समारोह सामान्यतः कहाँ आयोजित किया जाता है?

- A) Vijay Chowk, New Delhi / विजय चौक, नई दिल्ली
- B) Rajpath, New Delhi / राजपथ, नई दिल्ली
- C) Red Fort, New Delhi / लाल किला, नई दिल्ली
- D) India Gate, New Delhi / इंडिया गेट, नई दिल्ली
- E) Rashtrapati Bhavan, New Delhi / राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- President Droupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi attended the Beating Retreat ceremony, marking the formal conclusion of India's Republic Day celebrations.
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीटिंग रिट्रीट समारोह में भाग लिया, जो गणतंत्र दिवस समारोहों के औपचारिक समापन का प्रतीक है।
- The ceremony features synchronised musical performances by bands of the Indian Army, Navy and Air Force.
- इस समारोह में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बैंडों द्वारा समन्वित संगीत प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं।
- In India, the Beating Retreat ceremony is organised three days after Republic Day, i.e., on 29 January.
- भारत में यह समारोह गणतंत्र दिवस के तीन दिन बाद, अर्थात 29 जनवरी को आयोजित किया जाता है।
- The event is traditionally held at Vijay Chowk, New Delhi.
- यह कार्यक्रम परंपरागत रूप से नई दिल्ली के विजय चौक में आयोजित किया जाता है।





Ques: Which day is observed on 27 January to commemorate the victims of the Holocaust?

27 जनवरी को होलोकॉस्ट के पीड़ितों की स्मृति में कौन-सा दिवस मनाया जाता है?

- A) International Holocaust Remembrance Day / अंतरराष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मृति दिवस
- B) World Peace Day / विश्व शांति दिवस
- C) International Human Rights Day / अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस
- D) International Justice Day / अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस
- E) World Refugee Day / विश्व शरणार्थी दिवस

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- 27 January is observed as the International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust, also known as International Holocaust Remembrance Day.
- 27 जनवरी को होलोकॉस्ट के पीड़ितों की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय दिवस, जिसे अंतरराष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मृति दिवस भी कहा जाता है, मनाया जाता है।
- The observance was started in 2006 following a resolution of the United Nations General Assembly.
- इस दिवस की शुरुआत 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के बाद की गई थी।
- The theme for 2026 is “Holocaust Remembrance for Dignity and Human Rights.”
- 2026 की थीम है — “गरिमा और मानवाधिकारों के लिए होलोकॉस्ट स्मरण”।
- The day aims to honour the memory of millions of victims of the Holocaust and promote human dignity, tolerance, and human rights.
- इस दिवस का उद्देश्य होलोकॉस्ट के लाखों पीड़ितों की स्मृति को सम्मान देना और मानव गरिमा, सहिष्णुता एवं मानवाधिकारों को बढ़ावा देना है।





Ques: After the proposed merger of Union Bank of India and Bank of India, what will be the overall ranking of the combined entity in India? प्रस्तावित विलय के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया की संयुक्त इकाई भारत में किस स्थान पर होगी?

- A) Largest bank / सबसे बड़ा बैंक
- B) Second-largest bank / दूसरा सबसे बड़ा बैंक
- C) Third-largest bank / तीसरा सबसे बड़ा बैंक
- D) Fourth-largest bank / चौथा सबसे बड़ा बैंक
- E) Fifth-largest bank / पाँचवाँ सबसे बड़ा बैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The initial merger process between Union Bank of India and Bank of India has begun and may be completed by the end of the calendar year.
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के बीच विलय की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसे कैलेंडर वर्ष के अंत तक पूरा किया जा सकता है।
- The Government of India aims to merge smaller public sector banks with larger ones to reduce the number of PSU banks from 12 to about 4–5.
- भारत सरकार छोटे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बड़े बैंकों में विलय कर 12 के बजाय लगभग 4–5 बड़े PSU बैंक बनाना चाहती है।
- The merger would create one of India's largest public sector lenders with an expanded balance sheet, branch network, and customer base.
- यह विलय विस्तारित बैलेंस शीट, शाखा नेटवर्क और ग्राहक आधार के साथ भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं में से एक का निर्माण करेगा।
- The combined entity is expected to become the second-largest PSU bank with assets of about ₹25.4 lakh crore in FY25.
- संयुक्त इकाई FY25 में लगभग ₹25.4 लाख करोड़ की परिसंपत्तियों के साथ दूसरा सबसे बड़ा PSU बैंक बन जाएगी।
- Overall, it would be the third-largest bank in India after State Bank of India (SBI) and HDFC Bank.
- कुल मिलाकर, यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और HDFC बैंक के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा।





Ques: Which bank has launched India's first savings account linked to 100% of the RBI Repo rate? किस बैंक ने भारत का पहला 100% RBI रेपो रेट से जुड़ा बचत खाता लॉन्च किया है?

- A) AU Small Finance Bank / एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक
- B) Ujjivan Small Finance Bank / उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
- C) Jana Small Finance Bank / जना स्मॉल फाइनेंस बैंक
- D) Equitas Small Finance Bank / इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक
- E) Slice Small Finance Bank / स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Slice Small Finance Bank (Slice SFB) has introduced three new financial products.
- स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक (Slice SFB) ने तीन नए वित्तीय उत्पाद पेश किए हैं।
- These include a Digital Savings Account linked to the RBI Repo rate, a UPI-integrated credit card, and digital Fixed Deposits (FDs).
- इनमें RBI रेपो रेट से जुड़ा डिजिटल बचत खाता, UPI-इंटीग्रेटेड क्रेडिट कार्ड और डिजिटल फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) शामिल हैं।
- Slice launched India's first savings account linked to 100% of the Repo rate of the Reserve Bank of India (RBI).
- स्लाइस ने भारत का पहला ऐसा बचत खाता लॉन्च किया है जो 100% RBI रेपो रेट से जुड़ा है।
- Interest on the savings account is calculated and credited daily, allowing real-time growth of money.
- इस बचत खाते पर ब्याज की गणना और जमा प्रतिदिन की जाती है, जिससे धन वास्तविक समय में बढ़ता है।
- The digital Fixed Deposits offer interest rates of up to 7.25% per annum.
- डिजिटल फिक्स्ड डिपॉजिट पर 7.25% प्रति वर्ष तक ब्याज दिया जाता है।
- These FDs are insured up to ₹5 lakh by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC).
- ये एफडी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) द्वारा ₹5 लाख तक बीमित हैं।
- The card offers up to 3% cashback based on usage, a "Slice in 3" feature for no-cost Equated Monthly Investment (EMI) conversion on purchases above Rs.2,000, weekly rewards through Slice Sparks.





About Slice Small Finance Bank :

- Established : 2016
- HQ : Guwahati, Assam
- CEO Rajan Bajaj



EXAM
Genius





Ques: The Reinsurance Advisory Committee (RAC) has been reconstituted by which regulatory body? रीइंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी (RAC) का पुनर्गठन किस नियामक संस्था द्वारा किया गया है?

- A) Reserve Bank of India (RBI) / भारतीय रिज़र्व बैंक
- B) Securities and Exchange Board of India (SEBI) / भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड
- C) Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) / भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
- D) Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) / पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण
- E) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reinsurance Advisory Committee (RAC) has been reconstituted by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI).
- रीइंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी (RAC) का पुनर्गठन भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा किया गया है।
- The committee has been reconstituted for a period of three years.
- समिति का पुनर्गठन तीन वर्षों की अवधि के लिए किया गया है।
- It has been constituted under Section 101B of the Insurance Act, 1938.
- इसका गठन बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101B के अंतर्गत किया गया है।
- The RAC is chaired by A.V. Girija Kumar, former Chairman and Managing Director (CMD) of Oriental Insurance Company Limited (OICL).
- RAC के अध्यक्ष ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) ए.वी. गिरिजा कुमार हैं।
- Aruna Bowrampet, Deputy General Manager (Reinsurance), IRDAI, serves as the Secretary of the committee.
- IRDAI की डिप्टी जनरल मैनेजर (रीइंश्योरेंस) अरुणा बोवरामपेट समिति की सचिव हैं।
- The objective of the RAC is to strengthen IRDAI's advisory support on reinsurance-related matters.
- RAC का उद्देश्य रीइंश्योरेंस से जुड़े मामलों पर IRDAI की परामर्श सहायता को मजबूत करना है।





About IRDAI :

ESTD : 1999

HQ : Hyderabad

Chairman : Ajay Seth



EXAM
Genius





Ques: Which company recently received the Payment Aggregator–Physical (PA-P) licence from the Reserve Bank of India (RBI)? हाल ही में किस कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से पेमेंट एग्रीगेटर–फिजिकल (PA-P) लाइसेंस प्राप्त हुआ है?

- A) Paytm Payments Services / पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज
- B) Razorpay / रेज़रपे
- C) Paysharp / पेसशार्प
- D) PhonePe / फोनपे
- E) BharatPe / भारतपे

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Paysharp has received the Payment Aggregator–Physical (PA-P) licence from the Reserve Bank of India (RBI).
- पेसशार्प को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से पेमेंट एग्रीगेटर–फिजिकल (PA-P) लाइसेंस प्राप्त हुआ है।
- The licence enables Paysharp to operate as a physical (offline) payment aggregator.
- यह लाइसेंस पेसशार्प को भौतिक (ऑफलाइन) पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है।
- This approval will help the company enhance its payment service offerings.
- इस स्वीकृति से कंपनी अपनी भुगतान सेवाओं को और सुदृढ़ कर सकेगी।
- Earlier, in August 2024, Paysharp had received the Payment Aggregator–Online (PA-O) licence.
- इससे पहले, अगस्त 2024 में पेसशार्प को पेमेंट एग्रीगेटर–ऑनलाइन (PA-O) लाइसेंस प्राप्त हुआ था।

EXAM
Genius





Ques: State Bank of India (SBI) has launched CHAKRA for what primary purpose?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने CHAKRA किस मुख्य उद्देश्य के लिए लॉन्च किया है?

- A) Promoting digital retail banking / डिजिटल रिटेल बैंकिंग को बढ़ावा देना
- B) Financing MSMEs only / केवल एमएसएमई को वित्तपोषण
- C) Financing sunrise sectors critical to India's economic transformation / भारत के आर्थिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण उभरते क्षेत्रों का वित्तपोषण
- D) Strengthening agricultural credit / कृषि ऋण को मजबूत करना
- E) Expanding overseas banking operations / विदेशी बैंकिंग परिचालन का विस्तार

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- State Bank of India (SBI) has launched CHAKRA, a Centre of Excellence (CoE).
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने CHAKRA नामक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) लॉन्च किया है।
- CHAKRA aims to finance sunrise sectors that are critical to India's economic transformation.
- CHAKRA का उद्देश्य भारत के आर्थिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण उभरते क्षेत्रों को वित्तपोषित करना है।
- The combined potential investment in these sunrise sectors is estimated at around ₹100 trillion over the next five years.
- इन उभरते क्षेत्रों में अगले पाँच वर्षों में लगभग ₹100 ट्रिलियन के संभावित निवेश का अनुमान है।
- SBI has estimated a lendable opportunity of about ₹20–22 trillion in these sectors during the same period.
- SBI ने इन क्षेत्रों में अगले पाँच वर्षों में लगभग ₹20–22 ट्रिलियन के ऋण अवसर का अनुमान लगाया है।
- SBI has signed Memoranda of Understanding (MoUs) with 21 financial institutions.
- SBI ने 21 वित्तीय संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- Under these MoUs, project finance teams of partner institutions will work alongside the SBI team at CHAKRA.
- इन समझौतों के तहत साझेदार संस्थानों की परियोजना वित्त टीम CHAKRA में तैनात SBI टीम के साथ कार्य करेंगी।
- This collaboration will enable capacity building and co-financing of projects.
- इस सहयोग से क्षमता निर्माण और परियोजनाओं का सह-वित्तपोषण संभव होगा।





Ques: The Supreme Court has linked menstrual health and access to Menstrual Hygiene Management (MHM) in schools with which Constitutional Article? सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में मासिक स्वास्थ्य एवं मासिक स्वच्छता प्रबंधन (MHM) को संविधान के किस अनुच्छेद से जोड़ा है?

- A) Article 14
- B) Article 15
- C) Article 19
- D) Article 21
- E) Article 32

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The Supreme Court held that the right to menstrual health and access to Menstrual Hygiene Management (MHM) in schools is part of the fundamental right to life and dignity under Article 21 of the Constitution.
- सुप्रीम कोर्ट ने माना कि स्कूलों में मासिक स्वास्थ्य और मासिक स्वच्छता प्रबंधन (MHM) तक पहुँच संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।
- The Court observed that lack of menstrual hygiene facilities exposes girls to stigma, humiliation, and discrimination.
- अदालत ने कहा कि मासिक स्वच्छता सुविधाओं की कमी लड़कियों को कलंक, अपमान और भेदभाव का सामना कराती है।
- Denial of MHM facilities violates the right to privacy, bodily autonomy, and equal participation in education.
- MHM सुविधाओं से वंचित करना निजता, शारीरिक स्वायत्तता और शिक्षा में समान भागीदारी के अधिकार का उल्लंघन है।
- The Supreme Court directed all States and Union Territories to ensure free access to sanitary napkins in both government and private schools.
- सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सरकारी एवं निजी सभी स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
- The judgment also emphasized that the Right to Education under Article 21A includes access to basic menstrual hygiene facilities.
- फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार बुनियादी मासिक स्वच्छता सुविधाओं को भी शामिल करता है।





Ques: Who won the 2026 Australian Open Women's Singles title? 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता?

- A) Aryna Sabalenka / आर्यना सबालेंका
- B) Iga Świątek / इगा स्वियातेक
- C) Jessica Pegula / जेसिका पेगुला
- D) Coco Gauff / कोको गॉफ
- E) Elena Rybakina / एलेना रिबाकिना

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Kazakhstan's Elena Rybakina won the 2026 Australian Open women's singles title.
- कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना ने 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब जीता।
- She defeated World No. 1 Aryna Sabalenka in a three-set final held in Melbourne.
- उन्होंने मेलबर्न में खेले गए तीन सेट के फाइनल में वर्ल्ड नंबर-1 आर्यना सबालेंका को हराया।
- Rybakina maintained composure under extreme heat conditions to secure the victory.
- रिबाकिना ने भीषण गर्मी की परिस्थितियों में संयम बनाए रखते हुए जीत हासिल की।
- This was her second Grand Slam title.
- यह उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब था।
- She had earlier won her first Grand Slam title at Wimbledon four years ago.
- उन्होंने चार वर्ष पहले विंबलडन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था।
- Following this win, Elena Rybakina rose to World No. 3 in the WTA rankings.
- इस जीत के बाद एलेना रिबाकिना WTA रैंकिंग में विश्व नंबर-3 पर पहुंच गईं।
- The Australian Open is one of the four Grand Slam tournaments and is played on hard courts in Melbourne.
- ऑस्ट्रेलियन ओपन चार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में से एक है, जो मेलबर्न में हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है।





Ques: In which month did UPI record its highest-ever transaction volume of about 21.6 billion?

UPI ने लगभग 21.6 अरब का अब तक का सबसे अधिक लेन-देन किस महीने में दर्ज किया?

- A) October 2025 / अक्टूबर 2025
- B) November 2025 / नवंबर 2025
- C) August 2025 / अगस्त 2025
- D) September 2025 / सितंबर 2025
- E) December 2025 / दिसंबर 2025

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- UPI transaction volume reached a record 21.6 billion in December 2025, the highest ever recorded.
- दिसंबर 2025 में UPI लेन-देन की संख्या 21.6 अरब तक पहुँच गई, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है।
- This surpassed the previous record of 20.47 billion transactions in November 2025.
- इसने नवंबर 2025 के 20.47 अरब लेन-देन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।
- The total value of UPI transactions in December 2025 rose to around ₹28 lakh crore.
- दिसंबर 2025 में UPI लेन-देन का कुल मूल्य लगभग ₹28 लाख करोड़ रहा।
- This value exceeded the earlier peak of about ₹27.3 lakh crore recorded in October 2025.
- यह अक्टूबर 2025 में दर्ज ₹27.3 लाख करोड़ के पिछले उच्चतम स्तर से भी अधिक था।
- The growth reflects increased digital payment adoption, festive spending, and expansion of the UPI ecosystem.
- यह वृद्धि डिजिटल भुगतान को तेजी से अपनाने, त्योहारी खर्च और UPI इकोसिस्टम के विस्तार को दर्शाती है।





Ques: Who holds the record for presenting the highest number of Union Budgets in India?

भारत में सबसे अधिक केंद्रीय बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है?

- A) Manmohan Singh / मनमोहन सिंह
- B) Yashwant Sinha / यशवंत सिन्हा
- C) Nirmala Sitharaman / निर्मला सीतारमण
- D) Morarji Desai / मोरारजी देसाई
- E) P. Chidambaram / पी. चिदंबरम

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- Finance Minister Nirmala Sitharaman is set to present her 9th consecutive Union Budget since assuming office in 2019.
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2019 से अब तक लगातार 9वां केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं।
- She has already presented eight consecutive Union Budgets, the longest continuous run by any Finance Minister in India.
- उन्होंने अब तक लगातार 8 केंद्रीय बजट पेश किए हैं, जो किसी भी भारतीय वित्त मंत्री द्वारा सबसे लंबी निरंतर श्रृंखला है।
- With the ninth Budget, she moves closer to the all-time record held by Morarji Desai.
- 9वें बजट के साथ वह मोरारजी देसाई के सर्वकालिक रिकॉर्ड के और करीब पहुँच जाएंगी।
- Former Prime Minister Morarji Desai holds the record for presenting the highest number of Union Budgets in India — a total of 10.
- पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कुल 10 केंद्रीय बजट पेश किए थे, जो अब तक का सर्वोच्च रिकॉर्ड है।





Ques: Who has been appointed as the Chairman and Managing Director (CMD) of Hindustan Aeronautics Limited (HAL)? हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Dr. D.K. Sunil / डॉ. डी.के. सुनील
- B) Kota Ravi / कोटा रवि
- C) R. Madhavan / आर. माधवन
- D) Sanjay Seth / संजय सेठ
- E) Vinay Dube / विनय दुबे

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Kota Ravi has been appointed as the Chairman and Managing Director (CMD) of Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
- कोटा रवि को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) नियुक्त किया गया है।
- He has replaced Dr. D.K. Sunil in this position.
- उन्होंने इस पद पर डॉ. डी.के. सुनील का स्थान लिया है।
- Hindustan Aeronautics Limited (HAL) was established on 22 December 1940.
- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) की स्थापना 22 दिसंबर 1940 को हुई थी।
- The headquarters of HAL is located in Bengaluru, Karnataka.
- HAL का मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है।

EXAM
Genius





Ques: Under the India–EU Free Trade Agreement (FTA), what has India agreed regarding European Union (EU) banks? भारत-यूरोपीय संघ (EU) मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के तहत भारत ने EU बैंकों के संबंध में क्या सहमति दी है?

- A) Complete removal of banking restrictions / बैंकिंग प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाना
- B) Allowing unlimited branch expansion / असीमित शाखा विस्तार की अनुमति
- C) Allowing EU banks to open up to 15 branches over four years / चार वर्षों में EU बैंकों को 15 शाखाएँ खोलने की अनुमति
- D) Permitting only representative offices / केवल प्रतिनिधि कार्यालयों की अनुमति
- E) Restricting operations to metro cities / केवल महानगरों तक संचालन सीमित

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- India has agreed to allow European Union (EU) banks to open up to 15 branches over a four-year period under the India–EU Free Trade Agreement (FTA).
- भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के तहत भारत ने EU बैंकों को चार वर्षों में 15 शाखाएँ खोलने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है।
- European banks currently operating in India include Deutsche Bank, BNP Paribas, and Societe Generale.
- वर्तमान में भारत में कार्यरत यूरोपीय बैंकों में डॉयचे बैंक, बीएनपी परिबास और सोसाइटी जेनरल शामिल हैं।
- Under the FTA, India allows 100% foreign direct investment (FDI) in the insurance sector.
- FTA के तहत भारत बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देता है।
- India also permits 74% FDI in banking services under the agreement.
- इस समझौते के अंतर्गत बैंकिंग सेवाओं में 74% FDI की अनुमति भी दी गई है।
- The agreement provides for a general review by a joint committee within five years of its entry into force.
- समझौते के प्रभावी होने के पाँच वर्षों के भीतर संयुक्त समिति द्वारा सामान्य समीक्षा का प्रावधान है।
- Subsequent reviews will be conducted every five years, allowing recalibration based on trade and investment flows.
- इसके बाद हर पाँच वर्ष में समीक्षा की जाएगी, जिससे व्यापार और निवेश प्रवाह के अनुसार पुनर्संतुलन किया जा सकेगा।





Ques: National Shipbuilding & Heavy Industries Park (NSHIP), recently in news, has been established at which location? राष्ट्रीय जहाज निर्माण एवं भारी उद्योग पार्क (NSHIP) हाल ही में किस स्थान पर स्थापित किया गया है?

- A) Kochi, Kerala / कोच्चि, केरल
- B) Visakhapatnam, Andhra Pradesh / विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश
- C) Thoothukudi, Tamil Nadu / तूतीकोरिन (थूथुकुडी), तमिलनाडु
- D) Chennai, Tamil Nadu / चेन्नई, तमिलनाडु
- E) Paradip, Odisha / पारादीप, ओडिशा

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Government of India, in collaboration with the Government of Tamil Nadu, has established the National Shipbuilding & Heavy Industries Park (NSHIP).
- भारत सरकार ने तमिलनाडु सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय जहाज निर्माण एवं भारी उद्योग पार्क (NSHIP) की स्थापना की है।
- NSHIP has been set up in Thoothukudi, Tamil Nadu.
- NSHIP की स्थापना तमिलनाडु के थूथुकुडी में की गई है।
- NSHIP is a Special Purpose Vehicle (SPV).
- NSHIP एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) है।
- The SPV is a Joint Venture between V.O. Chidambaranar Port Authority (VOC Port) and the State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu (SIPCOT).
- यह SPV वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी (VOC पोर्ट) और तमिलनाडु स्टेट इंडस्ट्रीज़ प्रमोशन कॉरपोरेशन (SIPCOT) के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
- Both partners hold an equal 50% stake in the SPV.
- दोनों साझेदारों की हिस्सेदारी 50-50 प्रतिशत है।
- It is the first SPV formed under the Shipbuilding Development Scheme (SbDS).
- यह जहाज निर्माण विकास योजना (SbDS) के अंतर्गत गठित पहला SPV है।
- The Shipbuilding Development Scheme (SbDS) was launched under a ₹69,725 crore maritime package in October 2025.
- जहाज निर्माण विकास योजना (SbDS) को अक्टूबर 2025 में ₹69,725 करोड़ के समुद्री पैकेज के तहत लॉन्च किया गया था।
- Under SbDS, ₹19,989 crore has been allocated to enhance domestic shipbuilding capacity.
- SbDS के अंतर्गत घरेलू जहाज निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए ₹19,989 करोड़ आवंटित किए गए हैं।





- The scheme aims to boost India's shipbuilding capacity to 4.5 million Gross Tonnage (GT) per year by 2047.
- इस योजना का उद्देश्य 2047 तक भारत की जहाज निर्माण क्षमता को 4.5 मिलियन ग्रॉस टन (GT) प्रतिवर्ष तक बढ़ाना है।
- The expansion will be achieved through infrastructure and technology upgrades.
- यह विस्तार अवसंरचना और प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से किया जाएगा।



EXAM
Genius





Ques: Which two wetlands were recently added to India's list of Ramsar Sites?

हाल ही में भारत की रामसर स्थलों की सूची में किन दो आर्द्रभूमियों को जोड़ा गया है?

- A) Sultanpur & Harike / सुल्तानपुर और हरिके
- B) Patna Bird Sanctuary & Chhari-Dhand / पटना पक्षी अभयारण्य और छरी-ढांड
- C) Keoladeo & Sambhar / केवलादेव और सांभर
- D) Bhoj Wetland & Wular / भोज आर्द्रभूमि और वुलर
- E) Chilika & Pulicat / चिल्का और पुलिकट

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- India has added Patna Bird Sanctuary (Etah, Uttar Pradesh) and Chhari-Dhand (Kutch, Gujarat) to its Ramsar Sites list.
- भारत ने पटना पक्षी अभयारण्य (एटा, उत्तर प्रदेश) और छरी-ढांड (कच्छ, गुजरात) को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया है।
- With this inclusion, India's total number of Ramsar Sites has increased to 98.
- इस शामिलीकरण के साथ भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 98 हो गई है।
- The addition strengthens India's position in Asia in wetland conservation.
- यह कदम एशिया में आर्द्रभूमि संरक्षण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करता है।
- These wetlands provide critical habitats for migratory birds.
- ये आर्द्रभूमियाँ प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास उपलब्ध कराती हैं।

EXAM
Genius





**Ques: The 6th National Crop Nutrition Summit was organised by which association?
छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया था?**

- A) Fertilizer Association of India / फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया
- B) Indian Council of Agricultural Research (ICAR) / भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
- C) Indian Micro-Fertilizers Manufacturers Association / भारतीय माइक्रो-फर्टिलाइज़र निर्माता संघ
- D) National Seeds Corporation / राष्ट्रीय बीज निगम
- E) Ministry of Agriculture & Farmers Welfare / कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The 6th edition of the National Crop Nutrition Summit was held in Mumbai.
- राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन का छठा संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया।
- The summit was organised by the Indian Micro-Fertilizers Manufacturers Association.
- इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारतीय माइक्रो-फर्टिलाइज़र निर्माता संघ द्वारा किया गया।
- The summit was inaugurated by Jayakumar Jitendrasinh Rawal.
- शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जयकुमार जितेंद्रसिंह रावल द्वारा किया गया।
- He is the Minister of Marketing & Protocol, Government of Maharashtra.
- वे महाराष्ट्र सरकार के विपणन एवं प्रोटोकॉल मंत्री हैं।
- P. K. Singh, Agriculture Commissioner of India, attended the event as the Guest of Honour.
- भारत के कृषि आयुक्त पी. के. सिंह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि (गेस्ट ऑफ ऑनर) थे।
- The theme of the summit was "Converge, Collaborate & Co-create".
- शिखर सम्मेलन का विषय "Converge, Collaborate & Co-create" था।





Ques: The 6th edition of the Khelo India Winter Games (KIWG) 2026 was inaugurated where? खेलो इंडिया विंटर गेम्स (KIWG) 2026 के छठे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया?

- A) Gulmarg, Jammu & Kashmir / गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर
- B) Nawang Dorjan Stobdan (NDS) Stadium, Leh / नवांग दोरजेन स्टोबदान (NDS) स्टेडियम, लेह
- C) Shimla, Himachal Pradesh / शिमला, हिमाचल प्रदेश
- D) Auli, Uttarakhand / औली, उत्तराखंड
- E) Srinagar, Jammu & Kashmir / श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The 6th edition of the Khelo India Winter Games (KIWG) 2026 was inaugurated on 20 January 2026.
- खेलो इंडिया विंटर गेम्स (KIWG) 2026 के छठे संस्करण का उद्घाटन 20 जनवरी 2026 को किया गया।
- The inauguration was done by Lieutenant Governor Kavinder Gupta.
- इसका उद्घाटन उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता द्वारा किया गया।
- The event was held at the Nawang Dorjan Stobdan (NDS) Stadium in Leh, Union Territory of Ladakh.
- यह आयोजन लेह, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख स्थित नवांग दोरजेन स्टोबदान (NDS) स्टेडियम में आयोजित किया गया।
- In the medal tally, Haryana topped the chart with 5 Gold, 1 Silver, and 2 Bronze medals.
- पदक तालिका में हरियाणा ने 5 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया।
- Ladakh secured second position with 2 Gold, 5 Silver, and 4 Bronze medals.
- लद्दाख ने 2 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया।
- Maharashtra finished third with 2 Gold, 3 Silver, and 2 Bronze medals.
- महाराष्ट्र ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।
- Khelo India Winter Games 2026 is conducted in two phases.
- खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आयोजन दो चरणों में किया गया है।
- Phase 1 (Ice Sports) was held in Leh and has been completed.
- चरण 1 (आइस स्पोर्ट्स) लेह में आयोजित किया गया और पूरा हो चुका है।





- Phase 2 (Snow Sports) will be held in Gulmarg, Jammu & Kashmir.
- चरण 2 (स्नो स्पोर्ट्स) गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर में आयोजित किया जाएगा।
- Phase 1 disciplines include Ice Hockey and Ice Skating. Figure Skating was introduced for the first time in KIWG 2026.
- चरण 1 में आइस हॉकी और आइस स्केटिंग शामिल हैं। फिगर स्केटिंग को पहली बार KIWG 2026 में शामिल किया गया।
- Phase 2 disciplines include Alpine Skiing, Nordic Skiing, Ski Mountaineering, and Snowboarding.
- चरण 2 में अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्की माउंटेनियरिंग और स्नोबोर्डिंग शामिल हैं।
- Players from 21 States and Union Territories are participating in ice sporting events.
- 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी आइस स्पोर्टिंग इवेंट्स में भाग ले रहे हैं।
- The mascot of Khelo India Winter Games 2026 is “Sheen-E-She (Shan)” — the Snow Leopard.
- खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का शुभंकर “शीन-ए-शे (शान)” — हिम तेंदुआ है।
- The Snow Leopard symbolizes resilience, agility, and the Himalayan legacy.
- हिम तेंदुआ दृढ़ता, फुर्ती और हिमालयी विरासत का प्रतीक है।

EXAM
Genius





**Ques: Who has been nominated as the next Chair of the US Federal Reserve?
अमेरिका के अगले फेडरल रिज़र्व चेयर के रूप में किसे नामित किया गया है?**

- A) Jerome Powell / जेरोम पॉवेल
- B) Janet Yellen / जेनेट येलेन
- C) Kevin Warsh / केविन वार्श
- D) Ben Bernanke / बेन बर्नान्के
- E) Lael Brainard / लेल ब्रेनार्ड

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- US President Donald Trump has nominated Kevin Warsh as the next Chair of the Federal Reserve.
- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने केविन वार्श को फेडरल रिज़र्व के अगले चेयर के रूप में नामित किया है।
- Kevin Warsh will succeed Jerome Powell, whose term as Federal Reserve Chair ends in May.
- केविन वार्श, जेरोम पॉवेल का स्थान लेंगे, जिनका फेड चेयर के रूप में कार्यकाल मई में समाप्त हो रहा है।
- Kevin Warsh is a former Federal Reserve Governor and has earlier served on the Fed's Board of Governors.
- केविन वार्श फेडरल रिज़र्व के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और फेड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी सेवा दे चुके हैं।
- The nomination concludes a closely watched search for the next US central bank chief.
- यह नामांकन अमेरिका के अगले केंद्रीय बैंक प्रमुख की लंबे समय से चल रही तलाश का समापन करता है।
- Donald Trump has frequently criticized Jerome Powell for not cutting interest rates aggressively.
- डोनाल्ड ट्रंप ने ब्याज दरों में आक्रामक कटौती न करने को लेकर जेरोम पॉवेल की कई बार आलोचना की है।





**Ques: PAIMANA portal, recently in news, has been launched by which ministry?
हाल ही में चर्चा में रहा PAIMANA पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है?**

- A) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
- B) Ministry of Home Affairs / गृह मंत्रालय
- C) NITI Aayog / नीति आयोग
- D) Ministry of Road Transport & Highways / सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
- E) Ministry of Statistics & Programme Implementation (MoSPI) / सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- PAIMANA stands for Project Assessment, Infrastructure Monitoring & Analytics for Nation-building.
- PAIMANA का पूर्ण रूप Project Assessment, Infrastructure Monitoring & Analytics for Nation-building है।
- The PAIMANA portal has been launched by the Ministry of Statistics & Programme Implementation (MoSPI).
- PAIMANA पोर्टल को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा लॉन्च किया गया है।
- The portal is designed to monitor Central Sector Infrastructure Projects with a cost of ₹150 crore and above.
- यह पोर्टल ₹150 करोड़ और उससे अधिक लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी के लिए बनाया गया है।
- PAIMANA replaces the earlier Online Computerised Monitoring System (OCMS-2006).
- PAIMANA ने पूर्ववर्ती Online Computerised Monitoring System (OCMS-2006) का स्थान लिया है।
- About 60% of project data flows automatically from Central Ministries and Departments.
- लगभग 60% परियोजना डेटा केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से स्वतः प्राप्त होता है।
- The portal covers ongoing infrastructure projects with revised costs of ₹150 crore and above.





Ques: The 'Samvad Samaroh' organised to honour WaSH Warriors was conducted by which ministry? वॉश वॉरियर्स को सम्मानित करने हेतु आयोजित 'संवाद समरोह' किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया?

- A) Ministry of Health and Family Welfare / स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- B) Ministry of Rural Development / ग्रामीण विकास मंत्रालय
- C) Ministry of Jal Shakti / जल शक्ति मंत्रालय
- D) Ministry of Housing and Urban Affairs / आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
- E) Ministry of Environment, Forest and Climate Change / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Ministry of Jal Shakti organised a 'Samvad Samaroh' and recognition programme in New Delhi.
- जल शक्ति मंत्रालय ने नई दिल्ली में 'संवाद समरोह' एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया।
- The programme was organised to honour WaSH Warriors.
- यह कार्यक्रम WaSH वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था।
- WaSH Warriors are grassroots leaders who have made outstanding contributions in water supply, sanitation, and hygiene.
- WaSH वॉरियर्स वे जमीनी स्तर के नेता हैं जिन्होंने जल आपूर्ति, स्वच्छता और स्वच्छता (हाइजीन) के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
- A total of 58 WaSH Warriors were recognised during the event.
- इस कार्यक्रम में कुल 58 WaSH वॉरियर्स को सम्मानित किया गया।
- These WaSH Warriors represented various States and Union Territories.
- ये WaSH वॉरियर्स विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- The recognition was given under the Jal Jeevan Mission (JJM) and related rural water and sanitation initiatives.
- यह सम्मान जल जीवन मिशन (JJM) एवं संबंधित ग्रामीण जल एवं स्वच्छता पहलों के अंतर्गत प्रदान किया गया।





Ques: How many cancer-related drugs were exempted from Basic Customs Duty (BCD) in the Union Budget 2026–27?

बजट 2026–27 में कितनी कैंसर संबंधी दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) से छूट दी गई?

- A) 10
- B) 12
- C) 15
- D) 17
- E) 20

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- In the Union Budget 2026–27, the Central Government exempted Basic Customs Duty on 17 drugs and medicines used for cancer treatment.
- केंद्रीय बजट 2026–27 में केंद्र सरकार ने कैंसर उपचार में उपयोग होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी माफ की।
- The announcement was made by Finance Minister Nirmala Sitharaman while presenting the Budget in the Lok Sabha.
- यह घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में बजट पेश करते समय की गई।
- The measure aims to reduce treatment costs and provide financial relief to cancer patients.
- इस कदम का उद्देश्य इलाज की लागत कम करना और कैंसर मरीजों को आर्थिक राहत प्रदान करना है।
- Additionally, customs duty on dutiable goods imported for personal use was reduced from 20% to 10%.
- साथ ही, व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित कर योग्य वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी गई।
- Seven more rare diseases were added to the list eligible for import duty exemption on medicines and Food for Special Medical Purposes (FSMP).
- 7 और दुर्लभ बीमारियों को दवाओं और विशेष चिकित्सा उपयोग वाले खाद्य पदार्थ (FSMP) पर आयात शुल्क छूट सूची में शामिल किया गया।





Ques: Biopharma Shakti was proposed in the Union Budget 2026–27 with what objective?

केंद्रीय बजट 2026–27 में बायोफार्मा शक्ति किस उद्देश्य से प्रस्तावित की गई है?

- A) To promote traditional medicine exports / पारंपरिक औषधि निर्यात को बढ़ावा देना
- B) To develop India as a global biopharma manufacturing hub / भारत को वैश्विक बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना
- C) To regulate drug pricing / दवा मूल्य नियंत्रण
- D) To expand health insurance coverage / स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार
- E) To strengthen medical tourism / मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Finance Minister Nirmala Sitharaman proposed the 'Biopharma Shakti' initiative in the Union Budget 2026–27.
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026–27 में 'बायोफार्मा शक्ति' योजना का प्रस्ताव रखा।
- The scheme has a total outlay of ₹10,000 crore.
- इस योजना के लिए ₹10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- Its primary objective is to develop India as a global biopharma manufacturing hub.
- इसका मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में विकसित करना है।
- The initiative focuses on strengthening biopharmaceutical research, innovation, and large-scale manufacturing capacity.
- यह पहल बायोफार्मास्यूटिकल अनुसंधान, नवाचार और बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता को मजबूत करने पर केंद्रित है।
- Biopharma Shakti aligns with the vision of Viksit Bharat and Atmanirbhar Bharat.
- यह योजना विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।





Anjali, [2/4/2026 1:16 AM]

Ques: How many high-speed rail corridors were announced in the Union Budget 2026–27?

केंद्रीय बजट 2026–27 में कितने हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई?

- A) 5
- B) 6
- C) 7
- D) 8
- E) 10

Answer: Option C

Anjali, [2/4/2026 1:16 AM]

Explanation | व्याख्या:

- In the Union Budget 2026–27, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced the development of seven high-speed rail corridors.
- केंद्रीय बजट 2026–27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की।
- The objective is to promote environmentally sustainable passenger transport and reduce carbon emissions.
- इसका उद्देश्य पर्यावरण-अनुकूल यात्री परिवहन को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन कम करना है।
- These corridors will act as growth connectors between major cities and improve inter-city connectivity.
- ये कॉरिडोर प्रमुख शहरों के बीच विकास कनेक्टर के रूप में कार्य करेंगे और कनेक्टिविटी बेहतर करेंगे।
- Proposed routes include Mumbai–Pune, Pune–Hyderabad, Hyderabad–Bengaluru, Hyderabad–Chennai, Chennai–Bengaluru, Delhi–Varanasi, and Varanasi–Siliguri.
- प्रस्तावित मार्गों में मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–बेंगलुरु, हैदराबाद–चेन्नई, चेन्नई–बेंगलुरु, दिल्ली–वाराणसी और वाराणसी–सिलीगुड़ी शामिल हैं।





Ques: How many high-speed rail corridors were announced in the Union Budget 2026–27?

केंद्रीय बजट 2026–27 में कितने हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई?

- A) 5
- B) 6
- C) 7
- D) 8
- E) 10

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- In the Union Budget 2026–27, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced the development of seven high-speed rail corridors.
- केंद्रीय बजट 2026–27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की।
- The objective is to promote environmentally sustainable passenger transport and reduce carbon emissions.
- इसका उद्देश्य पर्यावरण-अनुकूल यात्री परिवहन को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन कम करना है।
- These corridors will act as growth connectors between major cities and improve inter-city connectivity.
- ये कॉरिडोर प्रमुख शहरों के बीच विकास कनेक्टर के रूप में कार्य करेंगे और कनेक्टिविटी बेहतर करेंगे।
- Proposed routes include Mumbai–Pune, Pune–Hyderabad, Hyderabad–Bengaluru, Hyderabad–Chennai, Chennai–Bengaluru, Delhi–Varanasi, and Varanasi–Siliguri.
- प्रस्तावित मार्गों में मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–बेंगलुरु, हैदराबाद–चेन्नई, चेन्नई–बेंगलुरु, दिल्ली–वाराणसी और वाराणसी–सिलीगुड़ी शामिल हैं।





Ques: India has signed an agreement with which technology firm for the procurement of the V-BAT Unmanned Aircraft System (UAS)?

V-BAT मानव रहित विमान प्रणाली (UAS) की खरीद के लिए भारत ने किस तकनीकी कंपनी के साथ समझौता किया है?

- A) Lockheed Martin / लॉकहीड मार्टिन
- B) Boeing Defence / बोइंग डिफेंस
- C) Shield AI / शील्ड एआई
- D) Northrop Grumman / नॉर्थ्रॉप ग्रुमन
- E) Raytheon Technologies / रेथियॉन टेक्नोलॉजीज

Answer: Option C

\Explanation | व्याख्या:

- India has signed an agreement with the technology firm Shield AI.
- भारत ने तकनीकी कंपनी शील्ड एआई के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- The objective of the agreement is the procurement of the V-BAT Unmanned Aircraft System (UAS).
- इस समझौते का उद्देश्य V-BAT मानव रहित विमान प्रणाली (UAS) की खरीद है।
- JSW Defence Private Limited has begun construction of a manufacturing unit for the production of V-BAT.
- JSW डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड ने V-BAT के उत्पादन हेतु एक विनिर्माण इकाई का निर्माण शुरू किया है।
- The project involves an investment of USD 90 million.
- इस परियोजना में 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश शामिल है।
- The manufacturing unit is being set up at the Electronic Manufacturing Clusters (EMC), Maheshwaram near Hyderabad, Telangana.
- यह विनिर्माण इकाई हैदराबाद (तेलंगाना) के पास महेश्वरम स्थित इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC) में स्थापित की जा रही है।





Ques: Why is 30 January observed as Martyrs' Day (Shaheed Diwas) in India?

भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस (मार्टर्स डे) के रूप में क्यों मनाया जाता है?

- A) Formation of Indian National Congress / भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
- B) Birth anniversary of Mahatma Gandhi / महात्मा गांधी की जयंती
- C) Death anniversary of Mahatma Gandhi / महात्मा गांधी की पुण्यतिथि
- D) Quit India Movement launch / भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत
- E) Adoption of Indian Constitution / भारतीय संविधान को अपनाया जाना

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- 30 January is observed as Martyrs' Day, also known as Sarvodaya Day or Shaheed Diwas.
- 30 जनवरी को शहीद दिवस, जिसे सर्वोदय दिवस भी कहा जाता है, के रूप में मनाया जाता है।
- On 30 January 2026, a Sarva-Dharma Prarthana was held at Gandhi Samadhi, Rajghat, New Delhi.
- 30 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई।
- The day commemorates the assassination of Mahatma Gandhi on 30 January 1948.
- यह दिवस 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की स्मृति में मनाया जाता है।
- Mahatma Gandhi was assassinated by Nathuram Godse at Birla House, now known as Gandhi Smriti, in New Delhi.
- महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा नई दिल्ली स्थित बिड़ला हाउस (अब गांधी स्मृति) में की गई थी।
- In 2026, India observed the 78th death anniversary of Mahatma Gandhi.
- वर्ष 2026 में महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि मनाई गई।





Ques: Under the revised Liberalised Remittance Scheme (LRS) rules, what is the new TCS rate on education and medical remittances above ₹10 lakh?

संशोधित लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) नियमों के तहत ₹10 लाख से अधिक शिक्षा और चिकित्सा रेमिटेंस पर नया TCS दर क्या है?

- A) 1%
- B) 2%
- C) 5%
- D) 10%
- E) 20%

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Union Budget rationalised Tax Collected at Source (TCS) on outward remittances under RBI's Liberalised Remittance Scheme (LRS).
- केंद्रीय बजट ने RBI की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत विदेशी रेमिटेंस पर TCS को तर्कसंगत बनाया।
- TCS on education and medical remittances above ₹10 lakh has been reduced from 5% to 2%.
- ₹10 लाख से अधिक शिक्षा और चिकित्सा रेमिटेंस पर TCS दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है।
- The reduction will ease liquidity pressure and ensure more funds directly reach students and patients abroad.
- इस कमी से नकदी दबाव कम होगा और छात्रों व मरीजों तक अधिक धन सीधे पहुंचेगा।
- Lower TCS will reduce cash blockage at the point of remittance.
- कम TCS से रेमिटेंस के समय धन अटकने की समस्या घटेगी।
- TCS on overseas tour packages has also been rationalised to a flat 2%.
- विदेशी टूर पैकेज पर TCS को भी फ्लैट 2% कर दिया गया है।
- Earlier, overseas tour remittances attracted 5% TCS below ₹10 lakh and 20% above ₹10 lakh.
- पहले विदेशी टूर रेमिटेंस पर ₹10 लाख से कम पर 5% और ₹10 लाख से अधिक पर 20% TCS लगता था।
- In November 2025, total outward remittances under LRS stood at \$1,937 million, showing a decline from October.





Ques: Under Union Budget 2026–27, what is the revised Tax Collected at Source (TCS) rate on overseas tour packages?

केंद्रीय बजट 2026–27 के तहत विदेशी टूर पैकेज पर संशोधित स्रोत पर कर संग्रह (TCS) दर क्या है?

- A) 5%
- B) 10%
- C) 20%
- D) 2%
- E) 1%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- Under the Union Budget 2026–27, interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal (MACT) to a natural person has been exempted from income tax.
- केंद्रीय बजट 2026–27 के अंतर्गत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) द्वारा प्राकृतिक व्यक्ति को दिया गया ब्याज आयकर से मुक्त कर दिया गया है।
- The TCS rate on overseas tour packages has been reduced from 5%/20% to 2% without any minimum amount threshold.
- विदेशी टूर पैकेज पर TCS दर को 5%/20% से घटाकर 2% कर दिया गया है, बिना किसी राशि सीमा के।
- Under the Liberalised Remittance Scheme (LRS), the TCS rate for education and medical purposes has also been reduced from 5% to 2%.
- उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए TCS दर को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है।
- The time limit for revising income tax returns has been extended from 31 December to 31 March with a nominal fee.
- आयकर रिटर्न संशोधन की समय-सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है, मामूली शुल्क के साथ।
- ITR-1 and ITR-2 filers can continue filing returns till 31 July, while non-audit business cases and trusts are allowed time till 31 August.
- ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने वाले करदाता 31 जुलाई तक, जबकि नॉन-ऑडिट व्यवसाय मामलों और ट्रस्ट के लिए 31 अगस्त तक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी गई है।
- These measures aim to simplify compliance and enhance ease of living for taxpayers.
- इन उपायों का उद्देश्य कर अनुपालन को सरल बनाना और करदाताओं के लिए जीवन सुगमता बढ़ाना है।



Ques: In which city did the State Bank of India launch a Global Trade Finance Centre (GTFC) to strengthen its trade finance and global banking operations?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने व्यापार वित्त और वैश्विक बैंकिंग संचालन को मजबूत करने के लिए ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर (GTFC) किस शहर में शुरू किया?

- A) Kolkata / कोलकाता
- B) New Delhi / नई दिल्ली
- C) Chennai / चेन्नई
- D) Mumbai / मुंबई
- E) Bengaluru / बेंगलुरु

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- State Bank of India, India's largest Public Sector Bank, launched a Global Trade Finance Centre to strengthen its trade finance and global banking operations.
- भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने व्यापार वित्त और वैश्विक बैंकिंग संचालन को मजबूत करने के लिए ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर शुरू किया।
- The GTFC was launched in Kolkata.
- यह GTFC कोलकाता में शुरू किया गया।
- In July 2025, SBI launched two specialized GTFCs in Kolkata and Hyderabad, Telangana, on the occasion of its 70th anniversary.
- जुलाई 2025 में, एसबीआई ने अपनी 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर कोलकाता और तेलंगाना के हैदराबाद में दो विशेष GTFC शुरू किए।
- The GTFC uses advanced technologies such as Artificial Intelligence, Machine Learning, and Blockchain.
- GTFC में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
- The initiative marks a shift from traditional paper-based trade finance systems to digital processes.
- यह पहल पारंपरिक कागज़-आधारित व्यापार वित्त प्रणालियों से डिजिटल प्रक्रियाओं की ओर बदलाव को दर्शाती है।





Ques: What was the total value of UPI transactions in January, as per NPCI data?

NPCI के अनुसार जनवरी में UPI लेनदेन का कुल मूल्य कितना था?

- A) ₹27.97 lakh crore
- B) ₹25.40 lakh crore
- C) ₹28.33 lakh crore
- D) ₹30.10 lakh crore
- E) ₹21.75 lakh crore

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- As per data released by the National Payments Corporation of India (NPCI), UPI transaction value touched a record high of ₹28.33 lakh crore in January.
- नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के अनुसार जनवरी में UPI लेनदेन का मूल्य ₹28.33 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।
- The total number of UPI transactions in January stood at 2,170 crore.
- जनवरी में कुल UPI लेनदेन 2,170 करोड़ दर्ज किए गए।
- In December, the UPI transaction value was ₹27.97 lakh crore, showing a sharp rise in January.
- दिसंबर में UPI लेनदेन का मूल्य ₹27.97 लाख करोड़ था, जो जनवरी में बढ़ गया।
- Month-on-month growth in UPI transaction value was recorded at 21%.
- मूल्य के आधार पर UPI लेनदेन में महीने-दर-महीने 21% की वृद्धि हुई।
- Average daily UPI transactions during January were around 70 crore.
- जनवरी में औसतन प्रतिदिन लगभग 70 करोड़ UPI लेनदेन हुए।
- The average daily transaction value stood at about ₹91,400 crore.
- औसत दैनिक लेनदेन मूल्य लगभग ₹91,400 करोड़ रहा।
- In January 2026, UPI transactions recorded a year-on-year growth of 28% in value terms.
- जनवरी 2026 में UPI लेनदेन मूल्य में 28% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।
- NPCI noted that the growth momentum of UPI continues to strengthen with increasing adoption of digital payments.
- NPCI के अनुसार डिजिटल भुगतान को अपनाने के साथ UPI की विकास गति लगातार मजबूत हो रही है।





Ques: What is the annual financing commitment under the new Country Partnership Framework (CPF) announced by the Government of India and the World Bank Group?

भारत सरकार और विश्व बैंक समूह द्वारा घोषित नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क (CPF) के तहत वार्षिक वित्तपोषण प्रतिबद्धता कितनी है?

- A) USD 3–5 billion
- B) USD 5–7 billion
- C) USD 6–8 billion
- D) USD 10–12 billion
- E) USD 8–10 billion

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- The Government of India and the World Bank Group announced a new Country Partnership Framework to accelerate job creation in both urban and rural areas.
- भारत सरकार और विश्व बैंक समूह ने शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन को तेज करने के लिए नया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क घोषित किया।
- The framework includes an annual financing commitment of USD 8–10 billion for the next five years.
- इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत अगले पाँच वर्षों के लिए USD 8–10 बिलियन का वार्षिक वित्तपोषण प्रस्तावित है।
- The new CPF came into effect from the beginning of January 2026.
- यह नया CPF जनवरी 2026 की शुरुआत से प्रभावी हुआ।
- The framework aligns with India's "Viksit Bharat" vision of becoming a developed nation by 2047.
- यह फ्रेमवर्क भारत के "विकसित भारत" विज़न के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है।
- The World Bank was established in 1944 and is headquartered in Washington D.C.
- विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में स्थित है।
- The World Bank has 189 member countries.
- विश्व बैंक के 189 सदस्य देश हैं।





Ques: From which date will the Income Tax Act, 2025 come into effect?

आयकर अधिनियम, 2025 किस तिथि से लागू होगा?

- A) 1st January 2026
- B) 1st April 2025
- C) 1st April 2026
- D) 1st July 2026
- E) 31st March 2026

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Income Tax Act, 2025 will come into force from 1st April 2026.
- आयकर अधिनियम, 2025 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा।
- The Finance Minister announced that simplified Income Tax Rules and Forms will be notified soon.
- वित्त मंत्री ने बताया कि सरलीकृत आयकर नियम और फॉर्म जल्द अधिसूचित किए जाएंगे।
- Tax forms have been redesigned to make compliance easier for common taxpayers.
- आम करदाताओं के लिए अनुपालन आसान बनाने हेतु आयकर फॉर्म को पुनः डिज़ाइन किया गया है।
- The timeline for filing Income Tax Returns has been extended.
- आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाई गई है।
- ITR-1 and ITR-2 filers can file returns till 31st July.
- ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने वाले करदाता 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
- Non-audit business cases and trusts will be allowed to file returns till 31st August.
- नॉन-ऑडिट बिजनेस मामलों और ट्रस्ट को 31 अगस्त तक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति होगी।
- The fiscal deficit for FY 2026–27 is estimated at 4.3% of GDP, lower than 4.4% in the current fiscal year.
- वित्त वर्ष 2026–27 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का 4.3% अनुमानित है, जो वर्तमान वित्त वर्ष के 4.4% से कम है।
- No deduction will be allowed on interest expenditure related to dividend income or mutual fund income.
- डिविडेंड आय या म्यूचुअल फंड आय से संबंधित ब्याज व्यय पर कोई कटौती अनुमत्य नहीं होगी।
- These provisions aim to improve ease of compliance and enhance ease of living for taxpayers.
- इन प्रावधानों का उद्देश्य कर अनुपालन को सरल बनाना और करदाताओं के लिए जीवन सुगमता बढ़ाना है।



Ques: Which port will host the 150 Tonnes Per Day e-Methanol plant proposed by Assam Petro-Chemicals Limited?

असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 150 टन प्रतिदिन ई-मेथनॉल संयंत्र किस बंदरगाह पर स्थापित किया जाएगा?

- A) Mumbai Port / मुंबई बंदरगाह
- B) Paradip Port / पारादीप बंदरगाह
- C) Kandla Port / कांडला बंदरगाह
- D) Visakhapatnam Port / विशाखापत्तनम बंदरगाह
- E) Kochi Port / कोच्चि बंदरगाह

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Assam Petro-Chemicals Limited signed a Memorandum of Understanding with Deendayal Port Authority to establish a 150 TPD e-Methanol plant at Kandla Port, Gujarat.
- असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड ने गुजरात के कांडला बंदरगाह पर 150 टीपीडी ई-मेथनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- The project involves a capital investment of over ₹1,200 crore.
- इस परियोजना में ₹1,200 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश शामिल है।
- E-Methanol is produced using green hydrogen and captured carbon dioxide, powered by renewable electricity.
- ई-मेथनॉल का उत्पादन हरित हाइड्रोजन और कैप्चर किए गए कार्बन डाइऑक्साइड से नवीकरणीय ऊर्जा की सहायता से किया जाता है।
- The fuel serves as a clean alternative for marine and industrial use, especially in sectors where electrification is difficult.
- यह ईंधन समुद्री और औद्योगिक उपयोग के लिए एक स्वच्छ विकल्प है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ विद्युतीकरण कठिन है।
- The e-Methanol will supply vessels operating along the Singapore–Rotterdam corridor and position Kandla Port as a green fuel hub.
- ई-मेथनॉल ईंधन सिंगापुर–रॉटरडैम कॉरिडोर पर संचालित जहाजों को आपूर्ति करेगा और कांडला बंदरगाह को हरित ईंधन केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।

About Assam :

- Capital : Dispur
- CM : Himanta Biswa Sarma • Governor : Lakshman Acharya





Ques: Where was the second India–Arab Foreign Ministers' Meeting held in January 2026?

जनवरी 2026 में दूसरा भारत–अरब विदेश मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया?

- A) Riyadh / रियाद
- B) Manama / मनामा
- C) Abu Dhabi / अबू धाबी
- D) New Delhi / नई दिल्ली
- E) Cairo / काहिरा

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The second India–Arab Foreign Ministers' Meeting was held on 31 January 2026 in New Delhi.
- दूसरा भारत–अरब विदेश मंत्रियों का सम्मेलन 31 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
- The meeting was co-chaired by India and the United Arab Emirates (UAE).
- इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने की।
- Foreign Ministers of Arab League member countries and the Secretary-General of the Arab League participated in the meeting.
- अरब लीग के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों और अरब लीग के महासचिव ने इस बैठक में भाग लिया।
- Representatives from all 22 Arab countries participated in the event.
- इस कार्यक्रम में सभी 22 अरब देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- This was the first India–Arab Foreign Ministers' Meeting hosted by India in New Delhi.
- यह पहली बार था जब भारत ने नई दिल्ली में भारत–अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की।
- The meeting was held after a gap of 10 years; the first India–Arab Foreign Ministers' Meeting was held in Bahrain in 2016.
- यह बैठक 10 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित की गई; पहली भारत–अरब विदेश मंत्रियों की बैठक 2016 में बहरीन में हुई थी।





Ques: By how much did the allocation for the Union Education Ministry increase in the latest Union Budget?

नवीनतम केंद्रीय बजट में शिक्षा मंत्रालय के आवंटन में कितनी वृद्धि की गई है?

- A) 8.5%
- B) 10.2%
- C) 12.6%
- D) 14.21%
- E) 18.0%

Answer: Option D

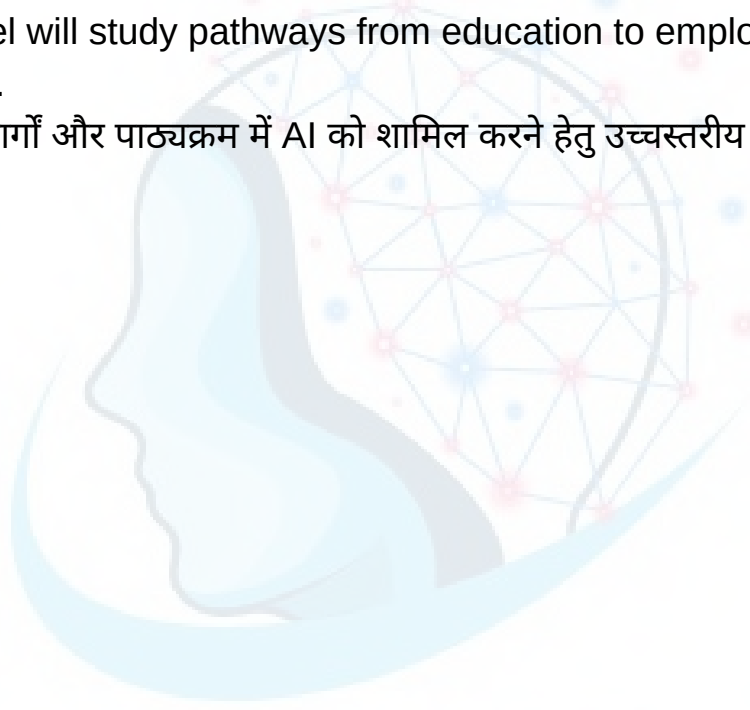
Explanation | व्याख्या:

- Allocation for the Union Education Ministry increased by 14.21% to about ₹1.39 lakh crore in the Union Budget.
- केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का आवंटन 14.21% बढ़कर लगभग ₹1.39 लाख करोड़ हो गया है।
- Major boost has been given to school education, skilling, and employability-linked programmes.
- स्कूली शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार से जुड़े कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया है।
- Allocation for the Samagra Shiksha scheme has increased significantly.
- समग्र शिक्षा योजना के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।
- Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) received around ₹600 crore more than the revised estimates.
- केंद्रीय विद्यालय संगठन को संशोधित अनुमान से लगभग ₹600 करोड़ अधिक आवंटन मिला है।
- Allocation for Atal Tinkering Labs increased sharply from ₹500 crore to ₹3,200 crore.
- अटल टिंकरिंग लैब्स का बजट ₹500 करोड़ से बढ़कर ₹3,200 करोड़ हो गया है।
- PM Poshan Scheme allocation rose by about ₹2,150 crore.
- पीएम पोषण योजना के बजट में लगभग ₹2,150 करोड़ की वृद्धि हुई है।
- Budget for the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship increased by 62% to about ₹3,885.8 crore.
- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का बजट 62% बढ़कर लगभग ₹3,885.8 करोड़ हो गया है।
- Focus is on PM Skill India, employability enhancement, and upgrading ITIs.
- पीएम स्किल इंडिया, रोजगार क्षमता बढ़ाने और आईटीआई उन्नयन पर फोकस किया गया है।
- Announcement made to establish five university townships near industrial and logistics corridors.





- औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के पास पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की गई है।
- Proposal to create Content Creator Labs in 15,000 schools and 500 colleges for the AVGC sector.
- AVGC सेक्टर के लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- TCS on foreign education has been reduced from 5% to 2%.
- विदेशी शिक्षा पर TCS को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है।
- A high-powered panel will study pathways from education to employment, including AI integration in curricula.
- शिक्षा से रोजगार तक के मार्गों और पाठ्यक्रम में AI को शामिल करने हेतु उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी।



EXAM
Genius





Ques: Which organisation signed an MoU with the Andhra Pradesh Economic Development Board to establish a Women Entrepreneurs' Industrial Park?

महिला उद्यमियों के औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश आर्थिक विकास बोर्ड ने किस संगठन के साथ समझौता किया है?

- A) Confederation of Indian Industry (CII) / भारतीय उद्योग परिसंघ
- B) Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) / भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य मंडल महासंघ
- C) FICCI Ladies Organisation (FICCI-FLO) / फिक्की लेडीज ऑर्गनाइजेशन
- D) National Federation of Indian Women Entrepreneurs / भारतीय महिला उद्यमियों का राष्ट्रीय महासंघ
- E) ASSOCHAM Women's Council / एसोचैम महिला परिषद

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Andhra Pradesh Economic Development Board signed a Memorandum of Understanding with the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry Ladies Organisation (FICCI-FLO).
- आंध्र प्रदेश आर्थिक विकास बोर्ड ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेडीज ऑर्गनाइजेशन (FICCI-FLO) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- The MoU is aimed at establishing a Women Entrepreneurs' Industrial Park in Andhra Pradesh.
- इस समझौते का उद्देश्य आंध्र प्रदेश में महिला उद्यमियों के लिए एक औद्योगिक पार्क की स्थापना करना है।
- The industrial park will cater exclusively to women entrepreneurs who are members of FICCI-FLO.
- यह औद्योगिक पार्क केवल FICCI-FLO की सदस्य महिला उद्यमियों के लिए होगा।
- The initiative seeks to promote financial self-reliance among women, generate employment, nurture local talent, and reduce regional industrial disparities.
- इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना, स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना और क्षेत्रीय औद्योगिक असमानताओं को कम करना है।
- The project aligns with Andhra Pradesh's 'One Family, One Entrepreneur' vision.
- यह परियोजना आंध्र प्रदेश की 'एक परिवार, एक उद्यमी' परिकल्पना के अनुरूप है।
- It also complements the state's plan to establish 175 MSME parks across all assembly constituencies.
- यह राज्य की सभी विधानसभा क्षेत्रों में 175 MSME पार्क स्थापित करने की योजना को भी पूरक करती है।





About Andhra Pradesh :

- Capital : Amaravati
- CM : N.Chandrababu Naidu
- Governor : S. Abdul Nazeer



EXAM
Genius





Ques: What is the main objective of the SHE Mart initiative?

SHE Mart पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A) Promote urban women entrepreneurship / शहरी महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना
- B) Provide subsidies to SHGs only / केवल स्वयं सहायता समूहों को सब्सिडी देना
- C) Shift rural women from SHGs to enterprise ownership / ग्रामीण महिलाओं को SHGs से उद्यम स्वामित्व की ओर ले जाना
- D) Expand welfare schemes for women / महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार करना
- E) Promote exports by women-led firms / महिला-नेतृत्व वाली कंपनियों द्वारा निर्यात को बढ़ावा देना

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- SHE Mart initiative aims to move rural women from Self Help Groups (SHGs) to enterprise ownership.
- SHE Mart पहल का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से उद्यम स्वामित्व की ओर ले जाना है।
- The initiative was announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman in the Union Budget.
- यह पहल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट में घोषित की गई।
- SHE Marts will be established as community-owned retail outlets at the cluster level.
- SHE Mart को क्लस्टर स्तर पर समुदाय-स्वामित्व वाले रिटेल आउटलेट के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- It builds upon the success of the Lakhpati Didi Programme.
- यह लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है।
- The focus is on women-centric economic participation rather than welfare-based support.
- इसका जोर कल्याण आधारित सहायता के बजाय महिला-केंद्रित आर्थिक भागीदारी पर है।
- The initiative supports formalisation and scaling up of women-led enterprises and livelihoods.
- यह महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों के औपचारिकीकरण और आजीविका के विस्तार में मदद करता है।
- Existing schemes such as SHG networks, DAY-NRLM and Lakhpati Didi initiatives will be leveraged.
- SHG नेटवर्क, DAY-NRLM और लखपति दीदी जैसी मौजूदा योजनाओं का लाभ उठाया जाएगा।
- Key challenges include digital and skill gaps, infrastructure constraints, logistics, and Centre–State coordination.
- प्रमुख चुनौतियों में डिजिटल व कौशल अंतर, बुनियादी ढांचा, लॉजिस्टिक्स और केंद्र–राज्य समन्वय शामिल हैं।
- Experts view SHE Mart as a structural instrument for inclusive rural economic growth.
- विशेषज्ञ इसे समावेशी ग्रामीण आर्थिक विकास का संरचनात्मक साधन मानते हैं।





Ques: How much allocation has been made for the new rural jobs scheme under the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025?

VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के तहत नई ग्रामीण रोजगार योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है?

- A) ₹75,000 crore / ₹75,000 करोड़
- B) ₹85,000 crore / ₹85,000 करोड़
- C) ₹95,692 crore / ₹95,692 करोड़
- D) ₹1.25 lakh crore / ₹1.25 लाख करोड़
- E) ₹2.3 lakh crore / ₹2.3 लाख करोड़

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Union Budget allocated ₹95,692.31 crore for the new rural jobs scheme under the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025.
- केंद्रीय बजट में Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025 के तहत नई ग्रामीण रोजगार योजना के लिए ₹95,692.31 करोड़ का आवंटन किया गया।
- An additional ₹30,000 crore has been allocated for MGNREGS to clear pending liabilities and meet ongoing expenditure.
- लंबित देनदारियों को निपटाने और जारी खर्चों को पूरा करने के लिए MGNREGS हेतु ₹30,000 करोड़ अतिरिक्त आवंटित किए गए।
- The total allocation for both rural employment schemes stands at ₹1,25,692.31 crore.
- दोनों ग्रामीण रोजगार योजनाओं के लिए कुल आवंटन ₹1,25,692.31 करोड़ है।
- The budget allocation for rural employment witnessed a 43 percent increase.
- ग्रामीण रोजगार के बजट में 43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- Experts believe the allocation is insufficient to provide 125 days of work to all workers.
- विशेषज्ञों के अनुसार यह आवंटन सभी श्रमिकों को 125 कार्यदिवस देने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- To achieve the 125-day employment target, the government may require around ₹2.3 lakh crore.
- 125 कार्यदिवस के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार को लगभग ₹2.3 लाख करोड़ की आवश्यकता हो सकती है।
- Around 8.65 crore active job card holders are eligible under the scheme.
- योजना के तहत लगभग 8.65 करोड़ सक्रिय जॉब कार्ड धारक पात्र हैं।
- The new VB-G RAM G Act will replace the MGNREGA, 2005 after it is officially notified.
- नई VB-G RAM G अधिनियम के अधिसूचित होने के बाद यह MGNREGA, 2005 का स्थान लेगा।





Ques: Who became the first artist to win a major Grammy with a song entirely in Spanish?

पूरी तरह स्पेनिश भाषा में गाने के साथ बड़ा ग्रैमी जीतने वाला पहला कलाकार कौन बना?

- A) Shakira / शकीरा
- B) Bad Bunny / बैड बनी
- C) Rosalía / रोसलिया
- D) J Balvin / जे बाल्विन
- E) Ricky Martin / रिकी मार्टिन

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The 68th Annual Grammy Awards were held in Los Angeles and witnessed several historic achievements.
- 68वें वार्षिक ग्रैमी अवॉर्ड्स लॉस एंजेलिस में आयोजित हुए, जहां कई ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज की गईं।
- Puerto Rican musician Bad Bunny won three Grammy Awards, including Album of the Year, Best Música Urbana Album, and Global Music Performance.
- प्यूर्टो रिको के गायक बैड बनी ने एल्बम ऑफ द ईयर, बेस्ट म्यूज़िका अर्बाना एल्बम और ग्लोबल म्यूज़िक परफॉर्मेंस सहित तीन ग्रैमी अवॉर्ड जीते।
- Bad Bunny became the first artist to win a major Grammy with a song entirely in Spanish.
- बैड बनी पूरी तरह स्पेनिश भाषा में गाने के साथ बड़ा ग्रैमी जीतने वाले पहले कलाकार बने।
- The Dalai Lama, at the age of 90, won the Grammy for Best Audio Book, Narration & Storytelling Recording for his album “Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama.”
- 90 वर्षीय दलाई लामा ने “Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama” एल्बम के लिए बेस्ट ऑडियो बुक, नैरेशन और स्टोरीटेलिंग रिकॉर्डिंग का ग्रैमी जीता।
- K-Pop created history as the song “Golden” from the animated film K-Pop Demon Hunters became the first-ever K-Pop song to win a Grammy Award.
- एनिमेटेड फिल्म K-Pop Demon Hunters के गीत “Golden” ने ग्रैमी जीतकर इतिहास रचा और यह पहला के-पॉप गीत बना जिसे यह सम्मान मिला।
- Indian artists like Anoushka Shankar and Siddhant Bhatia were nominated but did not win.
- अनुष्का शंकर और सिद्धांत भाटिया जैसे भारतीय कलाकार नामांकित हुए, लेकिन पुरस्कार नहीं जीत सके।
- Other major winners included Billie Eilish (Song of the Year – Wildflower), Kendrick Lamar feat. SZA (Record of the Year – Luther), and Olivia Dean (Best New Artist).



Ques: India's first Artificial Intelligence-enabled university pilot has been launched at which university?

भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-सक्षम विश्वविद्यालय पायलट किस विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है?

- A) Banaras Hindu University / बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
- B) Jawaharlal Nehru University / जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
- C) Aligarh Muslim University / अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
- D) Chaudhary Charan Singh University / चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय
- E) Delhi University / दिल्ली विश्वविद्यालय

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- Union Minister of State Jayant Chaudhary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and Ministry of Education, announced India's first AI-enabled university pilot.
- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने भारत के पहले AI-सक्षम विश्वविद्यालय पायलट की घोषणा की।
- The pilot has been launched at Chaudhary Charan Singh University (CCSU), Meerut.
- यह पायलट मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) में शुरू किया गया है।
- The initiative has been developed in collaboration with Google Cloud.
- यह पहल Google Cloud के सहयोग से विकसित की गई है।
- Advanced AI tools will be integrated across teaching, learning, administration, and employability, making it a scalable model for Indian universities.
- उन्नत AI टूल्स को शिक्षण, अधिगम, प्रशासन और रोजगार-योग्यता में एकीकृत किया जाएगा, जिससे यह भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए एक स्केलेबल मॉडल बनेगा।
- Google has pledged a grant of ₹85 crore (लगभग USD 10 मिलियन) to Wadhvani AI.
- Google ने Wadhvani AI को ₹85 करोड़ (लगभग 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का अनुदान देने की घोषणा की है।
- The grant will support AI integration in national platforms such as SWAYAM and POSHAN Tracker.
- यह अनुदान SWAYAM और POSHAN ट्रैकर जैसे राष्ट्रीय प्लेटफार्मों में AI एकीकरण को समर्थन देगा।





Ques: The tax holiday for IFSC units in GIFT City has been extended to how many years?

GIFT सिटी में IFSC इकाइयों के लिए टैक्स हॉलिडे कितने वर्षों तक बढ़ाया गया है?

- A) 20 years
- B) 15 years
- C) 18 years
- D) 10 years
- E) 25 years

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- The Union Budget has extended the tax holiday for IFSC (GIFT City) units from 10 years to 20 years.
- केंद्रीय बजट में IFSC (GIFT सिटी) इकाइयों के लिए टैक्स हॉलिडे 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया है।
- Under Section 80LA of the Income Tax Act, eligible IFSC units are entitled to 100 percent tax deduction on specified incomes.
- आयकर अधिनियम की धारा 80LA के तहत पात्र IFSC इकाइयों को कुछ आय पर 100 प्रतिशत कर छूट मिलती है।
- Earlier, the deduction was available for 10 consecutive years out of 15 years.
- पहले 15 वर्षों में से 10 लगातार वर्षों तक कर छूट उपलब्ध थी।
- Now, the deduction will be available for 20 consecutive years out of 25 years.
- अब 25 वर्षों में से 20 लगातार वर्षों तक कर छूट उपलब्ध होगी।
- After the expiry of the deduction period, business income will be taxed at a concessional rate of 15 percent.
- छूट अवधि समाप्त होने के बाद व्यावसायिक आय पर 15 प्रतिशत की रियायती कर दर लागू होगी।
- The move aims to enhance the global competitiveness of GIFT City as an international financial services hub.
- इस कदम का उद्देश्य GIFT सिटी को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है।
- It also provides long-term certainty and predictability for global investors and financial institutions.
- इससे वैश्विक निवेशकों और वित्तीय संस्थानों को दीर्घकालिक स्थिरता और स्पष्टता मिलेगी।
- The policy is expected to attract offshore funds, treasury operations and global capital to India.





Ques: Who launched the voice-based accounting app 'Pilloo AI' in Andhra Pradesh?

आंध्र प्रदेश में 'पिल्लो एआई' वॉयस-आधारित अकाउंटिंग ऐप किसने लॉन्च किया?

- A) Y. S. Jagan Mohan Reddy / वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी
- B) K. Chandrashekar Rao / के. चंद्रशेखर राव
- C) N. Chandrababu Naidu / एन. चंद्रबाबू नायडू
- D) Pinarayi Vijayan / पिनरायी विजयन
- E) M. K. Stalin / एम. के. स्टालिन

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu launched Pilloo AI, a next-generation voice-based billing and accounting application.
- आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने पिल्लो एआई नामक वॉयस-आधारित बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप लॉन्च किया।
- Pilloo AI has been designed to empower small and medium business owners (SMEs).
- पिल्लो एआई को छोटे और मध्यम व्यवसायों (SMEs) को सशक्त बनाने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है।
- The app enables users to generate invoices using simple voice commands.
- यह ऐप उपयोगकर्ताओं को आवाज़ के माध्यम से इनवॉइस बनाने की सुविधा देता है।
- Users can easily record sales transactions and payments through the app.
- उपयोगकर्ता इस ऐप के जरिए बिक्री और भुगतान को आसानी से दर्ज कर सकते हैं।
- Pilloo AI assists in tracking expenses, receivables, and payables in real time.
- पिल्लो एआई खर्च, प्राप्तियां और देनदारियों को ट्रैक करने में मदद करता है।
- No formal accounting knowledge is required to operate the application.
- इस ऐप को उपयोग करने के लिए औपचारिक अकाउंटिंग ज्ञान की आवश्यकता नहीं है।
- The launch aligns with Andhra Pradesh's broader push towards digital governance and MSME support.
- यह लॉन्च डिजिटल गवर्नेंस और MSME समर्थन को बढ़ावा देने की आंध्र प्रदेश सरकार की पहल के अनुरूप है।





Ques: Mukhyamantri Gramotthan Yojana (MGY) was launched by the Chief Minister of which state?

मुख्यमंत्री ग्रामोन्नयन योजना (MGY) किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई?

- A) Gujarat / गुजरात
- B) Madhya Pradesh / मध्य प्रदेश
- C) Rajasthan / राजस्थान
- D) Maharashtra / महाराष्ट्र
- E) Haryana / हरियाणा

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Mukhyamantri Gramotthan Yojana (MGY) was launched by Bhupendra Patel, the Chief Minister of Gujarat.
- मुख्यमंत्री ग्रामोन्नयन योजना (MGY) गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा शुरू की गई।
- The scheme was launched from Bhadran in Anand district of Gujarat.
- यह योजना गुजरात के आनंद जिले के भद्रन से शुरू की गई।
- The objective of the scheme is to provide urban-equivalent facilities in rural areas.
- इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्तर की सुविधाएँ प्रदान करना है।
- In the first phase, 114 villages that function as Taluka headquarters will be developed with modern amenities.
- पहले चरण में तालुका मुख्यालय के रूप में कार्य करने वाले 114 गांवों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा।
- The scheme aims to strengthen rural infrastructure and improve quality of life.
- यह योजना ग्रामीण अवसंरचना को मजबूत करने और जीवन स्तर में सुधार लाने का लक्ष्य रखती है।

About Gujarat :

- Capital : Gandhinagar
- CM : Bhupendra Patel
- Governor : Acharya Devvrat





Ques: Which airport will become India's first to operate hydrogen fuel cell electric buses for passenger transportation?

हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन-सा होगा?

- A) Indira Gandhi International Airport / इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
- B) Kempegowda International Airport / केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
- C) Cochin International Airport / कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
- D) Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport / छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
- E) Rajiv Gandhi International Airport / राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Cochin International Airport Limited (CIAL) will become India's first airport to operate hydrogen fuel cell electric buses for passenger transportation.
- कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (CIAL) यात्रियों के परिवहन के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बनेगा।
- The initiative supports green mobility and aims to promote carbon-neutral transportation at airports.
- यह पहल ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देती है और एयरपोर्ट पर कार्बन-न्यूट्रल परिवहन को प्रोत्साहित करती है।
- A Memorandum of Agreement (MoA) was signed between CIAL and the Kerala Hydrogen Valley Innovation Cluster Foundation for this project.
- इस परियोजना के लिए CIAL और केरल हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर फाउंडेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoA) किया गया है।
- The project aligns with India's National Green Hydrogen Mission.
- यह परियोजना भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है।
- Cochin International Airport is already globally recognised as the world's first fully solar-powered airport.
- कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहले से ही दुनिया का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट होने के लिए प्रसिद्ध है।





Ques: Adampur Airport in Punjab has been renamed after which personality?

पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है?

- A) Shri Guru Ravidas Maharaj Ji / श्री गुरु रविदास महाराज जी
- B) Guru Gobind Singh Ji / गुरु गोबिंद सिंह जी
- C) Guru Nanak Dev Ji / गुरु नानक देव जी
- D) Sant Kabir Das / संत कबीर दास
- E) Swami Vivekananda / स्वामी विवेकानंद

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Prime Minister Narendra Modi renamed Adampur Airport located in Jalandhar district of Punjab as Shri Guru Ravidas Maharaj Ji Airport.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर जिले स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट रखा।
- The announcement was made on the occasion of Sant Ravidas Jayanti.
- यह घोषणा संत रविदास जयंती के अवसर पर की गई।
- Guru Ravidas was a revered saint, poet, and social reformer.
- गुरु रविदास एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे।
- The renaming aims to honour the social and spiritual contributions of Guru Ravidas.
- नाम परिवर्तन का उद्देश्य गुरु रविदास के सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान को सम्मान देना है।
- On the same occasion, Prime Minister Modi virtually inaugurated the civil terminal building at Halwara Airport in Ludhiana.
- इसी अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने लुधियाना स्थित हलवाड़ा हवाई अड्डे के सिविल टर्मिनल भवन का वर्चुअल उद्घाटन भी किया।





Ques: Which country's grant assistance was increased by 74 percent by India in the Union Budget FY27?

FY27 के केंद्रीय बजट में भारत ने किस देश को दिए जाने वाले अनुदान में 74 प्रतिशत की वृद्धि की है?

- A) Nepal / नेपाल
- B) Sri Lanka / श्रीलंका
- C) Bhutan / भूटान
- D) Afghanistan / अफगानिस्तान
- E) Bangladesh / बांग्लादेश

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- India has increased grant assistance to Bangladesh by 74 percent in the Union Budget for FY27.
- भारत ने FY27 के केंद्रीय बजट में बांग्लादेश को दिए जाने वाले अनुदान में 74 प्रतिशत की वृद्धि की है।
- Grant allocation to Bangladesh has been raised to ₹60 crore from ₹34.48 crore in FY26 (Revised Estimates).
- बांग्लादेश को दिया जाने वाला अनुदान FY26 (संशोधित अनुमान) के ₹34.48 करोड़ से बढ़ाकर ₹60 करोड़ कर दिया गया है।
- At the same time, India has discontinued grant funding for Iran's Chabahar Port in FY27.
- इसी दौरान FY27 में ईरान के चाबहार बंदरगाह के लिए भारत की अनुदान सहायता रोक दी गई है।
- The decision has been influenced by US tariff pressures and the risk of secondary sanctions on countries supporting Iran's infrastructure projects.
- यह निर्णय अमेरिकी टैरिफ दबाव और ईरान की अवसंरचना परियोजनाओं का समर्थन करने वाले देशों पर द्वितीयक प्रतिबंधों की आशंका से प्रभावित है।
- India had earlier provided ₹400 crore to Chabahar Port in FY25, with another ₹400 crore earlier promised for FY26.
- भारत ने FY25 में चाबहार बंदरगाह को ₹400 करोड़ दिए थे और FY26 के लिए भी ₹400 करोड़ का वादा किया गया था।
- Among India's aid recipients, Bhutan continues to receive the highest grant allocation at ₹2,288 crore in FY27.





- भारत की सहायता प्राप्त देशों में FY27 में भूटान को सबसे अधिक ₹2,288 करोड़ मिले हैं।
- Grants to Sri Lanka (33 percent increase) and Seychelles (27 percent increase) have also been enhanced.
- श्रीलंका (33 प्रतिशत वृद्धि) और सेशेल्स (27 प्रतिशत वृद्धि) को भी अधिक अनुदान दिया गया है।
- Overall, India's grants and loans to foreign governments in FY27 stand at ₹8,792 crore, reflecting a 27 percent decline from FY26.
- कुल मिलाकर FY27 में भारत की विदेशी सरकारों को दी जाने वाली सहायता ₹8,792 करोड़ है, जो FY26 की तुलना में 27 प्रतिशत कम है।



EXAM
Genius





Ques: Which aircraft was involved in the air accident at Baramati while operating the Mumbai–Baramati sector?

मुंबई–बारामती सेक्टर पर उड़ान भरते समय बारामती में हुए विमान हादसे में कौन-सा विमान शामिल था?

- A) Falcon 2000
- B) Cessna Citation XLS
- C) Gulfstream G280
- D) Embraer Phenom 300
- E) Learjet 45

Answer: Option E

\Explanation | व्याख्या:

- A Learjet 45 aircraft operated by M/s VSR Ventures Pvt. Ltd., with registration VT-SSK, was involved in an air accident at Baramati.
- M/s VSR Ventures Pvt. Ltd. का Learjet 45 विमान (पंजीकरण: VT-SSK) बारामती में हुए विमान हादसे में शामिल था।
- The aircraft was operating a flight on the Mumbai–Baramati sector at the time of the incident.
- यह विमान हादसे के समय मुंबई–बारामती सेक्टर पर उड़ान भर रहा था।
- There were a total of 05 persons on board, including 02 crew members.
- विमान में कुल 05 लोग सवार थे, जिनमें 02 क्रू मेंबर शामिल थे।
- The passengers included Deputy Chief Minister of Maharashtra, Shri Ajit Pawar.
- यात्रियों में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार भी शामिल थे।
- Baramati is an uncontrolled airfield, where traffic information is provided by instructors or pilots of Flying Training Organisations (FTOs).
- बारामती एक अनियंत्रित हवाई अड्डा है, जहाँ यातायात संबंधी जानकारी फ्लाइटिंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (FTO) के प्रशिक्षकों/पायलटों द्वारा दी जाती है।





Ques: “Kattam” Kanjeevaram silk saree, recently in news, has received GI tag from which state?

हाल ही में चर्चा में रही “कट्टम” कांचीवरम सिल्क साड़ी को किस राज्य से GI टैग मिला है?

- A) Karnataka / कर्नाटक
- B) Andhra Pradesh / आंध्र प्रदेश
- C) Telangana / तेलंगाना
- D) Kerala / केरल
- E) Tamil Nadu / तमिलनाडु

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- “Kattam” Kanjeevaram (Kanchipuram) silk saree has been granted the Geographical Indication (GI) tag.
- “कट्टम” कांचीवरम (कांचीपुरम) सिल्क साड़ी को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्रदान किया गया है।
- The GI tag has been awarded to Tamil Nadu for this traditional handwoven saree.
- यह GI टैग इस पारंपरिक हथकरघा साड़ी के लिए तमिलनाडु को दिया गया है।
- The term “Kattam” refers to a checkered or square pattern, which is the defining design feature of this saree.
- “कट्टम” शब्द का अर्थ चेकदार (चौकोर) डिज़ाइन होता है, जो इस साड़ी की प्रमुख पहचान है।
- Kanjeevaram silk sarees are famous for high-quality mulberry silk, rich zari work and long-lasting durability.
- कांचीवरम सिल्क साड़ियां उच्च गुणवत्ता वाले शहतूत रेशम, समृद्ध ज़री कार्य और मजबूती के लिए प्रसिद्ध हैं।
- The GI tag helps protect traditional craftsmanship and prevents misuse of the regional name.
- GI टैग पारंपरिक शिल्प की रक्षा करता है और नाम के दुरुपयोग को रोकता है।





Ques: Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and GeoInformatics (BISAG-N) signed an MoU with which company to develop quantum-resilient cybersecurity solutions?

क्वांटम-रेज़िलिएंट साइबर सुरक्षा समाधान विकसित करने के लिए भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है?

- A) Tata Advanced Systems / टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स
- B) Infosys / इंफोसिस
- C) Tech Mahindra / टेक महिंद्रा
- D) Bharat Electronics Limited / भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
- E) QNu Labs Private Limited / क्यूएनयू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and GeoInformatics (BISAG-N), under the Ministry of Electronics and Information Technology, signed a Memorandum of Understanding with QNu Labs Private Limited.
- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) ने क्यूएनयू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- The collaboration aims to develop and deploy quantum-resilient cybersecurity solutions.
- इस सहयोग का उद्देश्य क्वांटम-रेज़िलिएंट साइबर सुरक्षा समाधान विकसित करना और उन्हें लागू करना है।
- Under the MoU, 'Vedic Kavach', an indigenous cryptographic software developed by BISAG-N, will be integrated with quantum hardware and secure infrastructure platforms of QNu Labs.
- इस MoU के तहत BISAG-N द्वारा विकसित स्वदेशी क्रिप्टोग्राफिक सॉफ्टवेयर 'वैदिक कवच' को QNu लैब्स के क्वांटम हार्डवेयर और सुरक्षित अवसंरचना प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जाएगा।
- The initiative strengthens India's capabilities in quantum-safe communication and cybersecurity.
- यह पहल क्वांटम-सुरक्षित संचार और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को सुदृढ़ करेगी।





Ques: Kerala has been selected for setting up a Dedicated Rare Earth Corridor along with which other states?

केरल को डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर के लिए किन राज्यों के साथ चुना गया है?

- A) Gujarat, Maharashtra, Rajasthan / गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान
- B) Andhra Pradesh, Odisha, Tamil Nadu / आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु
- C) Karnataka, Telangana, Goa / कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा
- D) Bihar, Jharkhand, West Bengal / बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल
- E) Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh / मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश

Answer: Option B

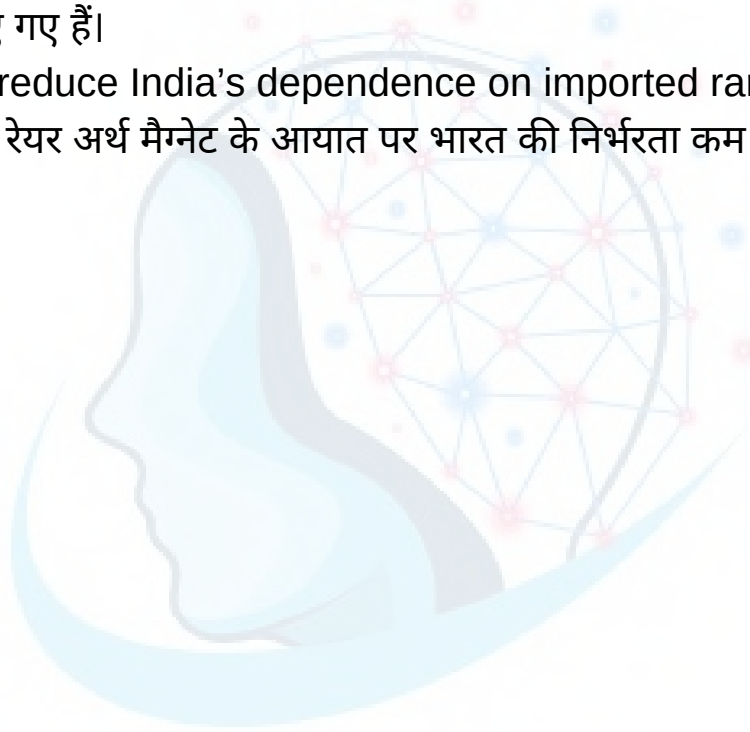
Explanation | व्याख्या:

- Kerala has been selected along with Andhra Pradesh, Odisha and Tamil Nadu for setting up Dedicated Rare Earth Corridors.
- केरल को आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु के साथ डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने के लिए चुना गया है।
- The proposal was part of Kerala's Union Budget wish list and also featured in the State Budget 2026–27.
- यह प्रस्ताव केरल की केंद्रीय बजट मांग सूची और राज्य बजट 2026–27 में शामिल था।
- Kerala sought ₹1,000 crore for corridor infrastructure, technology acquisition and related development.
- केरल ने कॉरिडोर अवसंरचना, तकनीक अधिग्रहण और विकास के लिए ₹1,000 करोड़ की मांग की थी।
- The corridor aims to promote mining, processing, research and manufacturing of rare earth minerals.
- इस कॉरिडोर का उद्देश्य रेयर अर्थ खनिजों के खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
- Kerala's coastline has abundant rare earth elements such as thorium and scandium, important for space, defence, energy, aviation and EV sectors.
- केरल के तट पर थोरियम और स्कैंडियम जैसे रेयर अर्थ तत्व प्रचुर मात्रा में हैं, जो अंतरिक्ष, रक्षा, ऊर्जा, विमानन और ईवी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- The corridor is proposed to link Vizhinjam International Seaport with Chavara (Kollam), where KMML is located.
- प्रस्तावित कॉरिडोर विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह को चावरा (कोल्लम) से जोड़ेगा, जहां KMML स्थित है।





- Kerala expects ₹42,000 crore investment and generation of around 50,000 jobs through this initiative.
- इस पहल से केरल को लगभग ₹42,000 करोड़ का निवेश और 50,000 रोजगार मिलने की उम्मीद है।
- ₹100 crore has been earmarked to set up a Rare Earth Critical Minerals Mission with KMML, KELTRON and NFTDC.
- KMML, KELTRON और NFTDC के साथ रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनेरल्स मिशन स्थापित करने के लिए ₹100 करोड़ निर्धारित किए गए हैं।
- The project aims to reduce India's dependence on imported rare-earth magnets.
- इस परियोजना का उद्देश्य रेयर अर्थ मैग्नेट के आयात पर भारत की निर्भरता कम करना है।



EXAM
Genius





Ques: Who won the Squash on Fire Open by defeating England's top seed Georgina Kennedy?

जॉर्जिना केनेडी को हराकर स्ववैश ऑन फायर ओपन किसने जीता?

- A) Joshna Chinappa / जोशना चिनप्पा
- B) Anahat Singh / अनाहत सिंह
- C) Dipika Pallikal / दीपिका पल्लीकल
- D) Nour El Sherbini / नूर एल शेरबिनी
- E) Saurav Ghosal / सौरव घोषाल

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Indian squash player Anahat Singh defeated England's top seed Georgina Kennedy to win the Squash on Fire Open held in Washington.
- भारतीय स्ववैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने वॉशिंगटन में आयोजित स्ववैश ऑन फायर ओपन में इंग्लैंड की टॉप सीड जॉर्जिना केनेडी को हराया।
- This victory earned Anahat Singh her maiden PSA Bronze-level title.
- इस जीत के साथ अनाहत सिंह ने अपना पहला PSA ब्रॉन्ज-लेवल खिताब जीता।
- It is the biggest title of her professional career so far.
- यह अब तक उनके करियर का सबसे बड़ा खिताब है।
- The Squash on Fire Open title was her 15th PSA Tour title in just 26 tournaments.
- यह केवल 26 टूर्नामेंटों में अनाहत सिंह का 15वां PSA टूर खिताब है।
- In the men's final, Egypt's Mohamed ElShorbagy defeated England's Declan James.
- पुरुष वर्ग के फाइनल में मिस्र के मोहम्मद एलशोरबागी ने इंग्लैंड के डेक्लन जेम्स को हराया।
- With this win, Mohamed ElShorbagy secured his 52nd PSA Tour title.
- इस जीत के साथ मोहम्मद एलशोरबागी ने अपना 52वां PSA टूर खिताब हासिल किया।





Ques: Who won the Tata Steel Chess Tournament 2026 (Masters)?

टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2026 (मास्टर्स) किसने जीता?

- A) Magnus Carlsen / मैग्नस कार्लसन
- B) Fabiano Caruana / फैबियानो कारुआना
- C) Nodirbek Abdusattorov / नोडिरबेक अब्दुसत्तोरुव
- D) Ding Liren / डिंग लिरिन
- E) Anish Giri / अनिश गिरी

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Uzbek Grandmaster Nodirbek Abdusattorov won the Tata Steel Chess Tournament 2026 (Masters).
- उज़्बेकिस्तान के ग्रैंडमास्टर नोडिरबेक अब्दुसत्तोरुव ने टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2026 (मास्टर्स) का खिताब जीता।
- He secured the title after 13 rounds of elite-level chess competition.
- उन्होंने 13 राउंड की उच्च-स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता के बाद यह खिताब अपने नाम किया।
- The tournament was held in Wijk aan Zee, Netherlands.
- यह टूर्नामेंट वाइक आन ज़ी, नीदरलैंड्स में आयोजित किया गया था।
- This was Abdusattorov's first Tata Steel Masters title, achieved on his fourth attempt.
- यह नोडिरबेक अब्दुसत्तोरुव का पहला टाटा स्टील मास्टर्स खिताब था, जिसे उन्होंने चौथे प्रयास में जीता।
- The 2026 edition marked the 88th edition of the Tata Steel Chess Tournament.
- वर्ष 2026 में यह टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का 88वां संस्करण था।
- Due to its long history and prestige, the tournament is often referred to as the "Wimbledon of Chess".
- अपनी लंबी परंपरा और प्रतिष्ठा के कारण इस टूर्नामेंट को "शतरंज का विंबलडन" कहा जाता है।





Ques: Where will the Smart and Integrated Fishing Harbour approved under PMMSY be developed?

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत स्वीकृत स्मार्ट और एकीकृत मछली पकड़ने का बंदरगाह कहाँ विकसित किया जाएगा?

- A) Mayabunder / मायाबंदर
- B) Campbell Bay / कैम्पबेल बे
- C) Port Blair / पोर्ट ब्लेयर
- D) Diglipur / डिगलीपुर
- E) Havelock Island / हैवलॉक द्वीप

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- The Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying approved the proposal for development of a Smart and Integrated Fishing Harbour at Mayabunder in Andaman & Nicobar Islands.
- मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के मायाबंदर में स्मार्ट एवं एकीकृत फिशिंग हार्बर के विकास को मंजूरी दी।
- The project has an estimated cost of ₹199.24 crore with 100% Central Financial Assistance under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY).
- इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹199.24 करोड़ है, जिसे PMMSY के तहत 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
- The Andaman & Nicobar Islands have a vast marine resource base with 6 lakh sq. km Exclusive Economic Zone (EEZ) and an estimated 60,000 MT of tuna and tuna-like species.
- अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के पास 6 लाख वर्ग किमी का EEZ और लगभग 60,000 मीट्रिक टन टूना एवं टूना-सदृश मछली संसाधन हैं।
- India's fish production has more than doubled from 96 lakh tonnes (2013–14) to 197.75 lakh tonnes (2024–25) due to sustained public investment.
- भारत में मछली उत्पादन 96 लाख टन (2013–14) से बढ़कर 197.75 लाख टन (2024–25) हो गया है।
- Seafood exports have doubled in value to ₹62,408 crore, covering 350+ product varieties exported to nearly 130 countries.
- समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य बढ़कर ₹62,408 करोड़ हो गया है, जिसमें 350 से अधिक उत्पाद 130 देशों को निर्यात किए जाते हैं।
- The Mayabunder harbour project will help unlock the fisheries potential of the Islands and support India's target of ₹1 lakh crore seafood exports by 2030–31.





- मायाबंदर फिशिंग हार्बर परियोजना द्वीपों की मत्स्य क्षमता को बढ़ाने और 2030–31 तक ₹1 लाख करोड़ समुद्री खाद्य निर्यात लक्ष्य को समर्थन देगी।
- Under PMMSY, the Andaman & Nicobar Islands have received total fisheries investment of ₹5,573.02 lakh for infrastructure and livelihood support.
- PMMSY के अंतर्गत अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में ₹5,573.02 लाख का निवेश मत्स्य अवसंरचना और आजीविका समर्थन हेतु किया गया है।



EXAM
Genius





Ques: Where will the Smart and Integrated Fishing Harbour approved under PMMSY be developed?

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत स्वीकृत स्मार्ट और एकीकृत मछली पकड़ने का बंदरगाह कहाँ विकसित किया जाएगा?

- A) Mayabunder / मायाबंदर
- B) Campbell Bay / कैम्पबेल बे
- C) Port Blair / पोर्ट ब्लेयर
- D) Diglipur / डिगलीपुर
- E) Havelock Island / हैवलॉक द्वीप

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- The Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying approved the proposal for development of a Smart and Integrated Fishing Harbour at Mayabunder in Andaman & Nicobar Islands.
- मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के मायाबंदर में स्मार्ट एवं एकीकृत फिशिंग हार्बर के विकास को मंजूरी दी।
- The project has an estimated cost of ₹199.24 crore with 100% Central Financial Assistance under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY).
- इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹199.24 करोड़ है, जिसे PMMSY के तहत 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
- The Andaman & Nicobar Islands have a vast marine resource base with 6 lakh sq. km Exclusive Economic Zone (EEZ) and an estimated 60,000 MT of tuna and tuna-like species.
- अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के पास 6 लाख वर्ग किमी का EEZ और लगभग 60,000 मीट्रिक टन टूना एवं टूना-सदृश मछली संसाधन हैं।
- India's fish production has more than doubled from 96 lakh tonnes (2013–14) to 197.75 lakh tonnes (2024–25) due to sustained public investment.
- भारत में मछली उत्पादन 96 लाख टन (2013–14) से बढ़कर 197.75 लाख टन (2024–25) हो गया है।
- Seafood exports have doubled in value to ₹62,408 crore, covering 350+ product varieties exported to nearly 130 countries.
- समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य बढ़कर ₹62,408 करोड़ हो गया है, जिसमें 350 से अधिक उत्पाद 130 देशों को निर्यात किए जाते हैं।
- The Mayabunder harbour project will help unlock the fisheries potential of the Islands and support India's target of ₹1 lakh crore seafood exports by 2030–31.



Ques: What forest cover target has Himachal Pradesh set to achieve by 2030?

हिमाचल प्रदेश ने 2030 तक वन क्षेत्र का कितना लक्ष्य तय किया है?

- A) 25%
- B) 27%
- C) 29.5%
- D) 31%
- E) 33%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The Himachal Pradesh government has set a target to increase the State's forest cover to 31% by the year 2030.
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2030 तक राज्य के वन क्षेत्र को 31% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- At present, the forest cover in Himachal Pradesh stands at 29.5%.
- वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 29.5% वन क्षेत्र मौजूद है।
- Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu has directed the Forest Department to prepare a comprehensive and sustainable roadmap to achieve this goal.
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन विभाग को एक व्यापक और सतत रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
- The strategy focuses on careful planning and sustainable forest management practices.
- इस रणनीति में सावधानीपूर्वक योजना और सतत वन प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया है।
- Community participation has been identified as a key factor in forest protection and conservation efforts.
- वन संरक्षण और सुरक्षा के प्रयासों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को महत्वपूर्ण माना गया है।
- The decision has been taken in the context of rising environmental and climate-related challenges.
- यह निर्णय बढ़ती पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी चुनौतियों के संदर्भ में लिया गया है।





Ques: Which institution secured the first position in the National Awards for Model Youth Gram Sabha in the Jawahar Navodaya Vidyalaya category?

मॉडल यूथ ग्राम सभा के राष्ट्रीय पुरस्कारों में जवाहर नवोदय विद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान किस संस्था ने प्राप्त किया?

- A) JNV Una, Himachal Pradesh / जेएनवी ऊना, हिमाचल प्रदेश
- B) JNV Ukhrul-I, Manipur / जेएनवी उखरूल-I, मणिपुर
- C) JNV Kannur, Kerala / जेएनवी कन्नूर, केरल
- D) JNV Jabalpur, Madhya Pradesh / जेएनवी जबलपुर, मध्य प्रदेश
- E) JNV Hirli, Odisha / जेएनवी हिरली, ओडिशा

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Union Minister of State for Panchayati Raj, Prof. S.P. Singh Baghel, conferred the National Awards to winners of the Model Youth Gram Sabha.
- पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल ने मॉडल यूथ ग्राम सभा के विजेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।
- In the Jawahar Navodaya Vidyalaya category, JNV Una, Himachal Pradesh secured the first position and was awarded prize money of ₹1 crore.
- जवाहर नवोदय विद्यालय श्रेणी में हिमाचल प्रदेश के जेएनवी ऊना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और ₹1 करोड़ की पुरस्कार राशि प्राप्त की।
- JNV Kannur, Kerala secured second position with a prize of ₹75 lakh.
- केरल के जेएनवी कन्नूर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और ₹75 लाख की पुरस्कार राशि प्राप्त की।
- JNV Ukhrul-I, Manipur secured third position and received ₹50 lakh as prize money.
- मणिपुर के जेएनवी उखरूल-I ने तृतीय स्थान प्राप्त किया और ₹50 लाख की पुरस्कार राशि प्राप्त की।
- In the Eklavya Model Residential School category, EMRS Kosambuda, Chhattisgarh secured first position and was awarded ₹1 crore.
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय श्रेणी में छत्तीसगढ़ के ईएमआरएस कोसामबुड़ा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और ₹1 करोड़ का पुरस्कार मिला।
- EMRS Hirli, Odisha and EMRS Jabalpur, Madhya Pradesh secured second and third with prize money Rs.75 lakh and Rs.50 lakh positions respectively.
- ओडिशा के ईएमआरएस हिरली और मध्य प्रदेश के ईएमआरएस जबलपुर ने क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया।





Ques: Which institution will act as the host institution for the high-level Committee formed to review the functioning of Farmer Producer Organisations (FPOs) in Tamil Nadu?

तमिलनाडु में किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के कार्यकलापों की समीक्षा हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति के लिए कौन-सा संस्थान होस्ट संस्थान के रूप में कार्य करेगा?

- A) National Bank for Agriculture and Rural Development, Mumbai / नाबार्ड, मुंबई
B) National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd, New Delhi / नाफेड, नई दिल्ली
C) ICAR–National Research Centre for Banana, Tiruchirappalli / आईसीएआर–राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, तिरुचिरापल्ली
D) Indian Council of Agricultural Research, New Delhi / भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
E) Small Farmers' Agribusiness Consortium, Hyderabad / लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ, हैदराबाद

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare formed a high-level Committee to review and strengthen the functioning of Farmer Producer Organisations in Tamil Nadu.
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने तमिलनाडु में किसान उत्पादक संगठनों के कार्यकलापों की समीक्षा और सुदृढ़ीकरण हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया।
- The Committee includes representatives from NABARD, NAFED, Small Farmers' Agribusiness Consortium, ICAR–National Research Centre for Banana, FPOs, NGOs and officials from the Department of Agriculture and Farmers Welfare.
- समिति में नाबार्ड, नाफेड, लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ, आईसीएआर–राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, FPOs, गैर-सरकारी संगठनों तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारी शामिल हैं।
- ICAR–National Research Centre for Banana (NRCB), Tiruchirappalli along with Krishi Vigyan Kendras through ICAR–Agricultural Technology Application Research Institutes, Hyderabad will act as the host institution.
- आईसीएआर–राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र (NRCB), तिरुचिरापल्ली तथा आईसीएआर–एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लिकेशन रिसर्च इंस्टिट्यूट, हैदराबाद के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र होस्ट संस्थान के रूप में कार्य करेंगे।
- The host institution will provide logistical and secretarial support to the Committee.
- होस्ट संस्थान समिति को आवश्यक लॉजिस्टिक और सचिवीय सहायता प्रदान करेगा।
- The Government of India achieved its target of establishing 10,000 FPOs under the 'Formation and Promotion of 10,000 FPOs Scheme'.





Ques: Who won the maiden BWF Super 300 title at the Thailand Masters 2025?

थाईलैंड मास्टर्स 2025 में पहला BWF सुपर 300 खिताब किसने जीता?

- A) Devika Sihag / देविका सिहाग
- B) Saina Nehwal / साइना नेहवाल
- C) P.V. Sindhu / पी.वी. सिंधु
- D) Goh Jin Wei / गोह जिन वेई
- E) Ashmita Chaliha / अश्मिता चालिहा

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Young Indian shuttler Devika Sihag won her maiden BWF Super 300 women's singles title at the Thailand Masters 2025.
- युवा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर्स 2025 में अपना पहला BWF सुपर 300 महिला एकल खिताब जीता।
- She secured the title after Malaysia's Goh Jin Wei retired mid-match due to injury in the final.
- फाइनल मुकाबले में मलेशिया की गोह जिन वेई के चोट के कारण मैच छोड़ने के बाद देविका विजेता बनीं।
- At the time of retirement, Devika was leading 21-8, 6-3.
- प्रतिद्वंद्वी के हटने के समय देविका 21-8, 6-3 से आगे थीं।
- Thailand Masters is a USD 250,000 prize money tournament under the BWF circuit.
- थाईलैंड मास्टर्स BWF सर्किट का 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर इनामी राशि वाला टूर्नामेंट है।
- Devika Sihag, aged 20, hails from Haryana.
- 20 वर्षीय देविका सिहाग हरियाणा से हैं।
- With this victory, she became only the third Indian woman to win a Super 300 women's singles title.
- इस जीत के साथ वह सुपर 300 महिला एकल खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय खिलाड़ी बनीं।
- Earlier Indian winners include P.V. Sindhu and Saina Nehwal.
- इससे पहले यह उपलब्धि पी.वी. सिंधु और साइना नेहवाल हासिल कर चुकी हैं।





Ques: With which organisation did NITI Aayog sign a Statement of Intent to promote digital literacy and financial inclusion across Aspirational Blocks?

आकांक्षी ब्लॉकों में डिजिटल साक्षरता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने किस संगठन के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए?

- A) National Skill Development Corporation / राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
- B) Digital India Corporation / डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
- C) National Institute of Information Technology Foundation / नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन
- D) Tata Institute of Social Sciences / टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान
- E) Indian Institute of Information Technology / भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- NITI Aayog signed a Statement of Intent with the National Institute of Information Technology Foundation.
- नीति आयोग ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए।
- The initiative aims to advance digital literacy, financial inclusion, and skill development across Aspirational Blocks.
- इस पहल का उद्देश्य आकांक्षी ब्लॉकों में डिजिटल साक्षरता, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास को आगे बढ़ाना है।
- Individuals will be trained in basic and advanced digital skills to access online platforms, government services, and digital tools.
- व्यक्तियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सरकारी सेवाओं और डिजिटल टूल्स तक पहुँच के लिए बुनियादी और उन्नत डिजिटल कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा।
- The programme will promote awareness of banking, insurance, and other financial services among underserved communities.
- यह कार्यक्रम वंचित समुदायों में बैंकिंग, बीमा और अन्य वित्तीय सेवाओं के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देगा।
- The initiative supports inclusive development and digital empowerment at the grassroots level.
- यह पहल समावेशी विकास और जमीनी स्तर पर डिजिटल सशक्तिकरण को समर्थन देती है।





About NITI Aayog :

- Established : January 1, 2015
- HQ : New Delhi
- CEO : BVR Subrahmanyam



EXAM
Genius





Ques: Which fund was announced to provide equity support for creating 'champion' MSMEs?

'चैंपियन' एमएसएमई के लिए इक्विटी सहायता देने हेतु कौन-सा फंड घोषित किया गया है?

- A) SME Growth Fund / एसएमई विकास निधि
- B) Self-Reliant India Fund / आत्मनिर्भर भारत निधि
- C) Startup India Fund / स्टार्टअप इंडिया निधि
- D) MSME Credit Fund / एमएसएमई ऋण निधि
- E) Production Linked Fund / उत्पादन से जुड़ी निधि

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- The Union Budget announced a three-pronged strategy to help MSMEs grow as "champions".
- केंद्रीय बजट में एमएसएमई को "चैंपियन" के रूप में विकसित करने के लिए तीन-स्तरीय रणनीति की घोषणा की गई।
- A ₹10,000 crore SME Growth Fund will provide equity support to create future MSME champions.
- ₹10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड भविष्य के एमएसएमई चैंपियन तैयार करने के लिए इक्विटी समर्थन देगा।
- Liquidity support to MSMEs will be strengthened through the Trade Receivables Discounting System (TReDS).
- TReDS के माध्यम से एमएसएमई को बेहतर तरलता सहायता प्रदान की जाएगी।
- TReDS has been mandated as the transaction settlement platform for all CPSE purchases from MSMEs.
- CPSEs द्वारा एमएसएमई से की जाने वाली सभी खरीद के लिए TReDS को अनिवार्य लेन-देन निपटान मंच बनाया गया है।
- Government e-Marketplace (GeM) will be integrated with TReDS to enhance information sharing and financing access.
- सूचना साझा करने और वित्तपोषण को बेहतर बनाने के लिए GeM को TReDS से जोड़ा जाएगा।
- A credit guarantee mechanism through CGTMSE will be introduced for invoice discounting.
- इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए CGTMSE के तहत क्रेडिट गारंटी तंत्र शुरू किया जाएगा।
- Asset-backed securities based on TReDS receivables will be introduced to develop a secondary market.
- द्वितीयक बाजार विकसित करने के लिए TReDS रिसीवेबल्स पर एसेट-बैक्ड सिक्क्योरिटीज़ लाई जाएंगी।
- The third pillar focuses on professional support through 'Corporate Mitras'.
- तीसरा स्तंभ 'कॉरपोरेट मित्रों' के माध्यम से पेशेवर सहयोग पर केंद्रित है।





Ques: When was the 73rd World Leprosy Day observed in 2026?

2026 में 73वां विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया?

- A) 30 January / 30 जनवरी
- B) 25 January / 25 जनवरी
- C) 28 January / 28 जनवरी
- D) Last Sunday of February / फरवरी का अंतिम रविवार
- E) First Sunday of January / जनवरी का पहला रविवार

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- World Leprosy Day is observed on the last Sunday of January every year.
- विश्व कुष्ठ रोग दिवस प्रतिवर्ष जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है।
- In 2026, the last Sunday of January fell on 25 January.
- 2026 में जनवरी का अंतिम रविवार 25 जनवरी को पड़ा।
- The 73rd World Leprosy Day was observed in 2026.
- वर्ष 2026 में 73वां विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया।
- The theme for World Leprosy Day 2026 was "Leprosy is curable, the real challenge is stigma".
- विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2026 की थीम थी "Leprosy is curable, the real challenge is stigma".
- In India, National Leprosy Day is observed annually on 30 January.
- भारत में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस प्रतिवर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है।
- The date coincides with the death anniversary of Mahatma Gandhi.
- यह तिथि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के साथ मेल खाती है।





Ques: Up to what level is the Government of India considering raising the FDI limit in Public Sector Banks (PSBs)?

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में FDI सीमा कितनी करने पर विचार कर रही है?

- A) 26%
- B) 40%
- C) 49%
- D) 51%
- E) 74%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- The Union Government is considering raising the FDI limit in Public Sector Banks (PSBs) from 20% to 49%.
- केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में FDI सीमा 20% से बढ़ाकर 49% करने पर विचार कर रही है।
- The proposal aims to strengthen the capital base of state-run banks and make them more competitive with private sector banks.
- इस प्रस्ताव का उद्देश्य सरकारी बैंकों की पूंजी स्थिति को मजबूत करना और उन्हें निजी बैंकों के बराबर लाना है।
- Inter-ministerial consultations are currently underway regarding this proposal.
- इस प्रस्ताव को लेकर अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श जारी है।
- The move was confirmed by Financial Services Secretary M. Nagaraju.
- इस कदम की पुष्टि वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू ने की है।
- At present, private banks are allowed up to 49% FDI, while PSBs remain capped at 20%.
- वर्तमान में निजी बैंकों में 49% तक FDI की अनुमति है, जबकि PSBs में सीमा 20% है।
- Higher FDI can help PSBs raise capital, expand lending capacity, and manage larger risks.
- अधिक FDI से PSBs को पूंजी जुटाने, ऋण विस्तार करने और बड़े जोखिम संभालने में मदद मिलेगी।
- The government believes India needs 3–4 globally large banks; currently, only SBI and HDFC Bank figure among the world's top lenders.
- सरकार का मानना है कि भारत को 3–4 वैश्विक स्तर के बड़े बैंक चाहिए, जबकि फिलहाल केवल SBI और HDFC Bank ही शीर्ष वैश्विक बैंकों में शामिल हैं।





Ques : Which bank has signed a distribution agreement with HSBC Asset Management (India) Private Limited to offer its Mutual Fund products to customers?

किस बैंक ने अपने ग्राहकों को HSBC एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के म्यूचुअल फंड उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए वितरण समझौता किया है?

- A) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- B) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- C) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- D) Central Bank of India / सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- E) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या :

- Central Bank of India (CBI) has signed a distribution agreement with HSBC Asset Management (India) Private Limited.
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) ने HSBC एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ वितरण समझौता किया है।
- Under this partnership, CBI will offer HSBC AMC's Mutual Fund products to its customers.
- इस साझेदारी के तहत CBI अपने ग्राहकों को HSBC AMC के म्यूचुअल फंड उत्पाद उपलब्ध कराएगा।
- The offerings include equity, debt, and hybrid mutual fund schemes.
- इन पेशकशों में इक्विटी, डेट और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड योजनाएँ शामिल हैं।
- These mutual fund products will be accessible through CBI's branches as well as its digital platforms.
- ये म्यूचुअल फंड उत्पाद CBI की शाखाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

About Central Bank of India :

- Established : 1911
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : Kalyan Kumar
- Tagline : Central to you since 1911





Ques: Who has been approved by RBI as the Managing Director (MD) & CEO of YES Bank?

RBI ने YES बैंक के प्रबंध निदेशक (MD) और CEO के रूप में किसे मंजूरी दी है?

- A) Prashant Kumar / प्रशांत कुमार
- B) Ravneet Gill / रवनीत गिल
- C) Vinay Muralidhar Tonse / विनय मुरलीधर टोंसे
- D) Shaktikanta Das / शक्तिकांत दास
- E) Amitabh Chaudhry / अमिताभ चौधरी

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- The Reserve Bank of India (RBI) has approved the appointment of Vinay Muralidhar Tonse as the Managing Director (MD) and Chief Executive Officer (CEO) of YES Bank.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने विनय मुरलीधर टोंसे को YES बैंक का प्रबंध निदेशक (MD) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त करने की मंजूरी दी है।
- The appointment has been approved for a term of three years.
- यह नियुक्ति तीन वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृत की गई है।
- YES Bank is a private sector bank with its headquarters in Mumbai.
- YES बैंक एक निजी क्षेत्र का बैंक है, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है।
- As per banking regulations, RBI approval is mandatory for the appointment of MD & CEO of banks.
- बैंकिंग नियमों के तहत MD और CEO की नियुक्ति के लिए RBI की मंजूरी अनिवार्य होती है।
- The approval highlights RBI's supervisory role in ensuring fit and proper management of banks.
- यह मंजूरी बैंकों में उपयुक्त और सक्षम प्रबंधन सुनिश्चित करने में RBI की पर्यवेक्षी भूमिका को दर्शाती है।





Ques : Which country's central bank approved the first USD-backed stablecoin named USDU?

किस देश के केंद्रीय बैंक ने USDU नामक पहले USD-समर्थित स्टेबलकॉइन को मंजूरी दी है?

- A) United States / संयुक्त राज्य अमेरिका
- B) United Kingdom / यूनाइटेड किंगडम
- C) United Arab Emirates / संयुक्त अरब अमीरात
- D) Singapore / सिंगापुर
- E) Switzerland / स्विट्ज़रलैंड

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- The Central Bank of the United Arab Emirates (UAE) has approved the country's first USD-backed stablecoin.
- संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के केंद्रीय बैंक ने देश के पहले USD-समर्थित स्टेबलकॉइन को मंजूरी दी है।
- The stablecoin is named USDU.
- इस स्टेबलकॉइन का नाम USDU है।
- USDU has been approved under the Payment Token Services Regulation framework of the UAE Central Bank.
- USDU को UAE केंद्रीय बैंक के पेमेंट टोकन सर्विसेज़ रेगुलेशन फ्रेमवर्क के तहत स्वीकृति दी गई है।
- The approval marks a significant step toward regulating digital assets and payment tokens in the UAE.
- यह मंजूरी UAE में डिजिटल एसेट्स और पेमेंट टोकन के विनियमन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- USDU is issued and managed by Universal Digital Intl Limited.
- USDU को यूनिवर्सल डिजिटल इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा जारी और प्रबंधित किया जाता है।





Ques: AI India Impact Summit 2026 has been curated around which three core pillars?

AI इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026 किन तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है?

- A) Economy, Ethics, Environment / अर्थव्यवस्था, नैतिकता, पर्यावरण
- B) People, Policy, Performance / लोग, नीति, प्रदर्शन
- C) Planet, Policy, Progress / ग्रह, नीति, प्रगति
- D) People, Planet, Progress / लोग, ग्रह, प्रगति
- E) Innovation, Inclusion, Impact / नवाचार, समावेशन, प्रभाव

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या :

- The AI India Impact Summit 2026 has been curated around three core pillars — People, Planet and Progress.
- AI इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026 को पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस के तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित किया गया है।
- This information was shared by Abhishek Singh, Additional Secretary, Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY).
- यह जानकारी अभिषेक सिंह, अतिरिक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा साझा की गई।
- The People pillar focuses on AI for social good, skill development, and human-centric innovation.
- पीपल स्तंभ AI को सामाजिक कल्याण, कौशल विकास और मानव-केंद्रित नवाचार से जोड़ता है।
- The Planet pillar highlights the role of AI in sustainability, climate action, and environmental protection.
- प्लैनेट स्तंभ स्थिरता, जलवायु कार्रवाई और पर्यावरण संरक्षण में AI समाधानों पर केंद्रित है।
- The Progress pillar emphasizes economic growth, digital transformation, and technological leadership through AI.
- प्रोग्रेस स्तंभ AI के माध्यम से आर्थिक विकास, डिजिटल परिवर्तन और तकनीकी नेतृत्व पर ध्यान देता है।
- Overall, the summit aligns with India's vision of responsible, ethical, and scalable adoption of Artificial Intelligence.
- समग्र रूप से यह समिट जिम्मेदार, नैतिक और स्केलेबल AI अपनाने की भारत की दृष्टि के अनुरूप है।





Ques: Which ministry launched the “Survey Module” and “Waqf Property Lease Module” on the UMEED Central Portal?

UMEED केंद्रीय पोर्टल पर “सर्वे मॉड्यूल” और “वक्फ संपत्ति पट्टा मॉड्यूल” किस मंत्रालय ने लॉन्च किए?

- A) Ministry of Home Affairs / गृह मंत्रालय
- B) Ministry of Housing and Urban Affairs / आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
- C) Ministry of Minority Affairs / अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
- D) Ministry of Social Justice and Empowerment / सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- E) Ministry of Law and Justice / विधि एवं न्याय मंत्रालय

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- The Ministry of Minority Affairs launched two additional modules — Survey Module and Waqf Property Lease Module — on the UMEED Central Portal.
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने UMEED केंद्रीय पोर्टल पर सर्वे मॉड्यूल और वक्फ संपत्ति पट्टा मॉड्यूल लॉन्च किए।
- The Survey Module provides a comprehensive digital framework for capturing, managing, and updating data related to surveys of Waqf properties.
- सर्वे मॉड्यूल वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण से संबंधित जानकारी के संग्रह, प्रबंधन और अद्यतन के लिए एक डिजिटल ढांचा प्रदान करता है।
- The Waqf Property Lease Management Module enables end-to-end digital management of leasing-related information of Waqf properties.
- वक्फ संपत्ति पट्टा प्रबंधन मॉड्यूल वक्फ संपत्तियों से जुड़े पट्टा संबंधी विवरणों के एंड-टू-एंड डिजिटल प्रबंधन की सुविधा देता है।
- The UMEED Central Portal was inaugurated on 6 June 2025.
- UMEED केंद्रीय पोर्टल का उद्घाटन 6 जून 2025 को किया गया था।
- It functions as a centralised digital platform for real-time uploading, verification, and monitoring of Waqf properties.
- यह वक्फ संपत्तियों के रियल-टाइम अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
- The portal operates under the Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development Act, 1995.
- यह पोर्टल यूनिफाइड वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 के तहत कार्य करता है।





Ques: Who has been awarded the 2026 Crafoord Prize in Geosciences, often referred to as the “Nobel Prize of Geosciences”?

“भू-विज्ञान का नोबेल” कहे जाने वाले 2026 के क्राफोर्ड भू-विज्ञान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?

- A) Sunita Narain / सुनीता नारायण
- B) Raghunath Mashelkar / रघुनाथ माशेलकर
- C) Veerabhadran Ramanathan / वीरभद्रन रामनाथन
- D) M. S. Swaminathan / एम. एस. स्वामीनाथन
- E) Rajendra Pachauri / राजेंद्र पचौरी

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- Veerabhadran Ramanathan, an 82-year-old Indian-origin climate scientist, has been awarded the 2026 Crafoord Prize in Geosciences.
- 82 वर्षीय भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को 2026 का क्राफोर्ड भू-विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- The Crafoord Prize is often referred to as the “Nobel Prize of Geosciences.”
- क्राफोर्ड पुरस्कार को अक्सर “भू-विज्ञान का नोबेल” कहा जाता है।
- The award is presented by the Royal Swedish Academy of Sciences.
- यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज़ द्वारा प्रदान किया जाता है।
- The same academy also awards the Nobel Prizes in Physics, Chemistry and Economic Sciences.
- यही अकादमी भौतिकी, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार भी प्रदान करती है।
- Ramanathan is globally renowned for his pioneering research on climate change, especially related to greenhouse gases, aerosols and atmospheric science.
- रामनाथन जलवायु परिवर्तन, विशेष रूप से ग्रीनहाउस गैसों, एरोसोल और वायुमंडलीय विज्ञान पर अपने अग्रणी शोध के लिए विश्व-प्रसिद्ध हैं।
- His scientific work has significantly influenced global climate policy and environmental awareness.
- उनके शोध कार्यों ने वैश्विक जलवायु नीतियों और पर्यावरणीय जागरूकता को गहराई से प्रभावित किया है।





Ques: What decision did the Government of India take regarding Central Excise Duty on unmanufactured tobacco, effective February 1, 2026?

1 फ़रवरी 2026 से भारत सरकार ने बिना निर्मित तंबाकू पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क को लेकर क्या निर्णय लिया?

- A) Increased excise duty to 28% on all unmanufactured tobacco / सभी बिना निर्मित तंबाकू पर उत्पाद शुल्क 28% कर दिया
- B) Withdrawn 18% excise duty on unbranded, non-retail unmanufactured tobacco / बिना ब्रांड नाम और खुदरा बिक्री हेतु पैक न किए गए बिना निर्मित तंबाकू पर 18% उत्पाद शुल्क हटा दिया
- C) Withdrawn excise duty on all forms of tobacco / सभी प्रकार के तंबाकू पर उत्पाद शुल्क हटा दिया
- D) Reduced excise duty to 5% on branded tobacco / ब्रांडेड तंबाकू पर उत्पाद शुल्क घटाकर 5% कर दिया
- E) Introduced a new cess on tobacco refuse / तंबाकू अपशिष्ट पर नया उपकर लगाया

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या :

- The Government of India withdrew the 18% Central Excise Duty on unmanufactured tobacco or tobacco refuse that is cleared without a brand name and not packed for retail sale.
- भारत सरकार ने बिना ब्रांड नाम और खुदरा बिक्री के लिए पैक न किए गए बिना निर्मित तंबाकू या तंबाकू अपशिष्ट पर 18% केंद्रीय उत्पाद शुल्क वापस ले लिया है।
- The decision is effective from February 1, 2026.
- यह निर्णय 1 फ़रवरी 2026 से प्रभावी हुआ है।
- Earlier, all unmanufactured tobacco cleared from factories or warehouses attracted 18% excise duty.
- पहले, फैक्ट्री या वेयरहाउस से निकाले गए सभी बिना निर्मित तंबाकू पर 18% उत्पाद शुल्क लगता था।
- Other forms of unmanufactured tobacco, such as those that are branded or packaged for retail sale, will continue to attract 18% excise duty.
- बिना निर्मित तंबाकू के अन्य रूप, जैसे ब्रांडेड या खुदरा बिक्री हेतु पैक किए गए तंबाकू पर 18% उत्पाद शुल्क जारी रहेगा।
- The move aims to provide relief to certain segments of the tobacco trade while maintaining taxation on branded retail products.
- इस कदम का उद्देश्य तंबाकू व्यापार के कुछ वर्गों को राहत देना है, जबकि ब्रांडेड खुदरा उत्पादों पर कर व्यवस्था बनाए रखना है।





Ques: Who has been sworn in as the new Chief Minister of Manipur after the end of President's Rule?

राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं?

- A) N. Biren Singh / एन. बीरेन सिंह
- B) Nemcha Kipgen / नेमचा किपगेन
- C) Losii Dikho / लोसी डिखो
- D) Yumnam Khemchand Singh / युम्नम खेमचंद सिंह
- E) Ajay Kumar Bhalla / अजय कुमार भल्ला

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या :

- President's Rule in Manipur has ended with the formation of a BJP-led NDA government.
- मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त होकर भाजपा-नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का गठन हुआ।
- Yumnam Khemchand Singh has been sworn in as the Chief Minister of Manipur.
- युम्नम खेमचंद सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
- The oath of office was administered by Manipur Governor Ajay Kumar Bhalla.
- उन्हें मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने शपथ दिलाई।
- Khemchand Singh is the second Chief Minister of Manipur since the 2022 Assembly elections.
- वे 2022 विधानसभा चुनावों के बाद मणिपुर के दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं।
- President's Rule was imposed on February 13, 2025, following the resignation of former CM N. Biren Singh amid ethnic unrest.
- 13 फरवरी 2025 को जातीय हिंसा के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के चलते राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।
- Nemcha Kipgen (BJP) from the Kuki-Zo community and Losii Dikho (Naga People's Front) were sworn in as Deputy Chief Ministers.
- नेमचा किपगेन (भाजपा) और लोसी डिखो (नागा पीपुल्स फ्रंट) को उपमुख्यमंत्री बनाया गया।
- Two additional MLAs were sworn in as Cabinet Ministers.
- दो अन्य विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली।
- The new CM stated that peace, development, and growth would be his top priorities.
- नए मुख्यमंत्री ने कहा कि शांति, विकास और प्रगति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताएं होंगी।
- Prime Minister Narendra Modi expressed confidence in the new government's ability to restore stability in Manipur.



Ques: Which organization announced India's first-ever National Household Income Survey (NHIS) and the Annual Survey of Incorporated Service Sector Enterprises (ASISSE), to be conducted from April 2026?

अप्रैल 2026 से भारत का पहला राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण (NHIS) और वार्षिक समाविष्ट सेवा क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण (ASISSE) आयोजित करने की घोषणा किस संगठन ने की?

- A) NITI Aayog / नीति आयोग
- B) Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक
- C) National Statistical Office / राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
- D) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
- E) Economic Advisory Council to PM / प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- The National Statistical Office (NSO) announced plans to conduct India's first-ever National Household Income Survey (NHIS) and Annual Survey of Incorporated Service Sector Enterprises (ASISSE).
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने भारत का पहला राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण (NHIS) और ASISSE आयोजित करने की घोषणा की।
- Both surveys will run for one year starting April 2026.
- दोनों सर्वेक्षण अप्रैल 2026 से एक वर्ष की अवधि के लिए संचालित होंगे।
- The announcement was made during the two-day All-India Workshop of Trainers held in Chennai.
- यह घोषणा चेन्नई में आयोजित दो दिवसीय अखिल भारतीय प्रशिक्षक कार्यशाला के दौरान की गई।
- NHIS and ASISSE will be conducted digitally using Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).
- दोनों सर्वेक्षण कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग (CAPI) के माध्यम से डिजिटल रूप में किए जाएंगे।
- The surveys will cover all of India, except hard-to-access villages in the Andaman & Nicobar Islands.
- सर्वेक्षण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दुर्गम गाँवों को छोड़कर पूरे भारत में किए जाएंगे।

National Household Income Survey (NHIS) | राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण





- NHIS will collect detailed data on household income, living conditions, and income distribution.
- NHIS घरेलू आय, जीवन स्तर और आय वितरण पर विस्तृत डेटा एकत्र करेगा।
- It will enable regional and household-level comparisons and support policy formulation.
- यह क्षेत्रीय एवं घरेलू तुलना और नीति निर्माण में सहायक होगा।
- The data will help analyze poverty, inequality, and economic behaviour more accurately than expenditure-based surveys alone.
- यह डेटा केवल व्यय-आधारित सर्वेक्षणों की तुलना में गरीबी, असमानता और आर्थिक व्यवहार का अधिक सटीक विश्लेषण संभव करेगा।

Annual Survey of Incorporated Service Sector Enterprises (ASISSE) | ASISSE :

- ASISSE covers the incorporated services sector using GSTN data.
- ASISSE GSTN डेटा का उपयोग करते हुए समाविष्ट सेवा क्षेत्र को कवर करता है।
- It provides state- and industry-level estimates of GVA, capital formation, employment, and emoluments.
- यह GVA, पूंजी निर्माण, रोजगार और पारिश्रमिक के राज्य एवं उद्योग-स्तरीय अनुमान प्रदान करता है।
- The survey improves measurement of the services sector's contribution to GDP and national accounts.
- यह GDP और राष्ट्रीय आय लेखांकन में सेवा क्षेत्र के योगदान के आकलन को बेहतर बनाता है।
- ASISSE includes data on:
 - Output and value added
 - Employment and wages
 - Operating expenses and profits
 - Capital formation and assets
 - Industry-wise and region-wise performance
- ASISSE सेवा क्षेत्र के आँकड़ों में महत्वपूर्ण डेटा गैप को भरता है और नीति निर्माण, आर्थिक योजना और राष्ट्रीय आय आकलन में सहायक है।





Ques: Which hydropower project was discussed by India and Bhutan for commercial optimisation of power output?

भारत और भूटान ने किस जलविद्युत परियोजना से बिजली उत्पादन के वाणिज्यिक अनुकूलन पर चर्चा की?

- A) Mangdechhu Project / मंगदेछु परियोजना
- B) Tala Hydroelectric Project / ताला जलविद्युत परियोजना
- C) Punatsangchhu-I Project / पुनात्सांगछु-I परियोजना
- D) Punatsangchhu-II Project / पुनात्सांगछु-II परियोजना
- E) Kholongchhu Project / खोलोंगछु परियोजना

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या :

- India and Bhutan have agreed to strengthen cooperation in the power sector, as per an official statement.
- आधिकारिक बयान के अनुसार, भारत और भूटान ने बिजली क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई है।
- Bhutan's Minister of Energy and Natural Resources, Lyonpo Gem Tshering, met India's Union Power Minister Manohar Lal Khattar.
- भूटान के ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्री ल्योपो जेम त्शेरिंग ने भारत के केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की।
- Discussions focused on the commercial optimisation of power output from the Punatsangchhu-II Hydroelectric Project.
- बातचीत का केंद्र पुनात्सांगछु-II जलविद्युत परियोजना से बिजली उत्पादन के वाणिज्यिक अनुकूलन पर रहा।
- The installed capacity of the Punatsangchhu-II project is 1020 MW.
- पुनात्सांगछु-II परियोजना की स्थापित क्षमता 1020 मेगावाट है।
- The initiative highlights India–Bhutan cooperation in hydropower development and cross-border electricity trade.
- यह पहल जलविद्युत विकास और सीमा-पार ऊर्जा व्यापार में भारत-भूटान साझेदारी को दर्शाती है।





Ques: Haven-1, the world's first private space station, is scheduled to be launched aboard which rocket?

दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन Haven-1 किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा?

- A) Ariane-6 / एरियन-6
- B) New Glenn / न्यू ग्लेन
- C) Falcon Heavy / फाल्कन हेवी
- D) Falcon 9 / फाल्कन-9
- E) Gaganyaan-LVM3 / गगनयान-LVM3

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या :

- Haven-1 will become the world's first private space station, scheduled for launch in 2027.
- Haven-1 वर्ष 2027 में लॉन्च होने वाला दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन होगा।
- It is being developed by Vast, a US-based private space company.
- इसे अमेरिका की निजी अंतरिक्ष कंपनी Vast द्वारा विकसित किया जा रहा है।
- The space station will be launched aboard SpaceX's Falcon 9 rocket.
- इस अंतरिक्ष स्टेशन को SpaceX के Falcon-9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा।
- Haven-1 is designed to support commercial astronauts, private missions, and scientific research in Low-Earth Orbit (LEO).
- इसे लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) में व्यावसायिक अंतरिक्ष यात्रियों, निजी मिशनों और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए डिजाइन किया गया है।
- The station will provide crew habitation, research facilities, and docking capability for visiting spacecraft.
- इसमें कू आवास, अनुसंधान सुविधाएं और डॉकिंग क्षमता उपलब्ध होंगी।
- Haven-1 will act as a precursor to larger commercial space stations in the future.
- यह भविष्य में बनने वाले बड़े व्यावसायिक अंतरिक्ष स्टेशनों का अग्रदूत होगा।
- The project aligns with NASA's plan to transition from the International Space Station (ISS) to commercially operated space stations.
- यह परियोजना ISS से व्यावसायिक अंतरिक्ष स्टेशनों की ओर NASA के संक्रमण योजना के अनुरूप है।





Ques: Indian Railways operationalised India's first-ever LNG–diesel dual-fuel DEMU train at which location?

भारतीय रेलवे ने भारत की पहली LNG–डीजल ड्यूल-फ्यूल DEMU ट्रेन को किस स्थान पर परिचालित किया?

- A) Varanasi / वाराणसी
- B) New Delhi / नई दिल्ली
- C) Chennai / चेन्नई
- D) Ahmedabad / अहमदाबाद
- E) Pune / पुणे

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या :

- Indian Railways successfully operationalised the country's first-ever LNG–diesel dual-fuel DEMU train.
- भारतीय रेलवे ने देश की पहली LNG–डीजल ड्यूल-फ्यूल DEMU ट्रेन को सफलतापूर्वक परिचालित किया।
- The train was launched at the Sabarmati Integrated Coaching Depot, Ahmedabad.
- यह ट्रेन साबरमती इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपो, अहमदाबाद में परिचालित की गई।
- The dual-fuel system uses Liquefied Natural Gas (LNG) to replace around 40% of conventional diesel consumption without affecting performance.
- यह ड्यूल-फ्यूल सिस्टम प्रदर्शन से समझौता किए बिना लगभग 40% डीज़ल की खपत को LNG से प्रतिस्थापित करता है।
- The project involved retrofitting the Driving Power Cars (DPCs) of a 1,400 HP DEMU rake with an advanced dual-fuel system.
- इस परियोजना में 1,400 हॉर्सपावर DEMU रैक के ड्राइविंग पावर कार्स (DPCs) को उन्नत ड्यूल-फ्यूल सिस्टम से रेट्रोफिट किया गया।
- Each DPC is equipped with a 2,200-litre LNG tank.
- प्रत्येक DPC में 2,200 लीटर की LNG टंकी लगाई गई है।
- A fully refilled LNG tank allows the train to cover approximately 2,200 km.
- एक बार पूरी तरह LNG भरने पर ट्रेन लगभग 2,200 किमी की दूरी तय कर सकती है।
- The initiative supports energy efficiency, cost reduction, and lower carbon emissions in rail transport.
- यह पहल रेलवे परिवहन में ऊर्जा दक्षता, लागत में कमी और कार्बन उत्सर्जन घटाने में सहायक है।





Ques: Which organisation flagged off SAKSHAM 2026 to promote fuel conservation and judicious use of petroleum products?

ईंधन संरक्षण और पेट्रोलियम उत्पादों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सक्षम 2026 की शुरुआत किस संस्था ने की?

- A) IOCL / इंडियन ऑयल
- B) BPCL / बीपीसीएल
- C) GAIL / गैल
- D) HPCL / एचपीसीएल
- E) ONGC / ओएनजीसी

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या :

- Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) flagged off SAKSHAM 2026, an awareness campaign focused on fuel conservation and judicious use of petroleum products.
- हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने ईंधन संरक्षण और पेट्रोलियम उत्पादों के विवेकपूर्ण उपयोग पर केंद्रित जागरूकता अभियान सक्षम 2026 की शुरुआत की।
- The initiative is organised in collaboration with major oil & gas PSUs such as IOCL, BPCL, GAIL, ONGC, OIL and IGL.
- यह पहल IOCL, BPCL, GAIL, ONGC, OIL और IGL जैसी प्रमुख तेल एवं गैस सार्वजनिक कंपनियों के सहयोग से आयोजित की गई है।
- SAKSHAM 2026 is being held under the aegis of the Ministry of Petroleum and Natural Gas.
- सक्षम 2026 का आयोजन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संरक्षण में किया जा रहा है।
- The event will continue till February 15 at Laxmi Nagar.
- यह कार्यक्रम लक्ष्मी नगर में 15 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा।
- Activities under the campaign include panel discussions, walkathon and quiz competitions.
- कार्यक्रम के अंतर्गत पैनल चर्चा, वॉकथॉन और क्विज प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा रही हैं।
- Around 300 school students participated in the walkathon along with senior oil and gas officials.
- लगभग 300 स्कूली छात्रों ने वरिष्ठ तेल एवं गैस अधिकारियों के साथ वॉकथॉन में भाग लिया।





Ques: Under Project Cheetah, how many cheetahs is Madhya Pradesh planning to bring from Botswana by the end of February?

प्रोजेक्ट चीता के तहत मध्य प्रदेश सरकार फरवरी के अंत तक बोत्सवाना से कितने चीते लाने की योजना बना रही है?

- A) 4
- B) 6
- C) 8
- D) 10
- E) 12

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- The Madhya Pradesh government has announced plans to bring 8 cheetahs from Botswana by the end of February.
- मध्य प्रदेश सरकार ने फरवरी के अंत तक बोत्सवाना से 8 चीते लाने की योजना बनाई है।
- This initiative is part of Project Cheetah, which aims to restore and reintroduce cheetahs in India after their extinction from the country.
- यह कदम प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य भारत में चीतों की पुनर्स्थापना करना है।
- Chief Minister Dr. Mohan Yadav discussed this plan with Union Environment Minister Bhupender Yadav in New Delhi.
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस योजना पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से नई दिल्ली में चर्चा की।
- The cheetahs brought from Botswana are expected to be housed in designated cheetah habitats in Madhya Pradesh.
- बोत्सवाना से लाए जाने वाले चीतों को मध्य प्रदेश के निर्धारित चीता आवास क्षेत्रों में रखा जाएगा।
- The move strengthens India's efforts in wildlife conservation and biodiversity restoration.
- यह पहल भारत के वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को मजबूती प्रदान करती है।





Ques: Which defence public sector undertaking (DPSU) has been granted Miniratna Category-I status with approval from Defence Minister Rajnath Singh?

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (DPSU) को मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा प्रदान किया गया है?

- A) Yantra India Limited / यंत्र इंडिया लिमिटेड
- B) Hindustan Aeronautics Limited / हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
- C) Bharat Electronics Limited / भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
- D) Bharat Dynamics Limited / भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
- E) Mazagon Dock Shipbuilders Limited / मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या :

- Defence Minister Rajnath Singh approved the grant of Miniratna Category-I status to Yantra India Limited (YIL).
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यंत्र इंडिया लिमिटेड (YIL) को मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा देने की मंजूरी दी।
- Yantra India Limited is a Defence Public Sector Undertaking (DPSU).
- यंत्र इंडिया लिमिटेड एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (DPSU) है।
- YIL is one of the seven DPSUs formed after the corporatization of the Ordnance Factory Board (OFB) in October 2021.
- यंत्र इंडिया लिमिटेड अक्टूबर 2021 में आर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (OFB) के कॉरपोरेटाइजेशन के बाद गठित सात DPSUs में से एक है।
- The Miniratna Category-I status empowers the Board of YIL to incur capital expenditure up to ₹500 crore without prior government approval.
- मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा YIL के बोर्ड को ₹500 करोड़ तक की पूंजीगत व्यय (नई परियोजनाएँ, आधुनिकीकरण, उपकरणों की खरीद आदि) सरकारी अनुमति के बिना करने का अधिकार देता है।
- This status enhances operational and financial autonomy of the company.
- यह दर्जा कंपनी की परिचालन और वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ाता है।

About Yantra India Limited :

- Established : 1 October 2021
- HQ : Nagpur, Maharashtra
- CMD : Gurudatt Ray





Ques: How many major trade agreements has India signed or concluded over the last six years to expand its global trade footprint?

पिछले छह वर्षों में भारत ने वैश्विक व्यापार विस्तार के लिए कितने प्रमुख व्यापार समझौते किए या पूरे किए हैं?

- A) 5
- B) 6
- C) 7
- D) 9
- E) 11

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या :

- Over the last six years, India has signed or concluded 9 major trade agreements, significantly expanding its global trade footprint.
- पिछले 6 वर्षों में भारत ने 9 बड़े व्यापार समझौते किए हैं, जिससे उसका वैश्विक व्यापार दायरा काफ़ी बढ़ा है।
- These agreements aim to improve market access, boost exports, and deepen economic partnerships with key global regions.
- इन समझौतों का उद्देश्य बाज़ार पहुंच बढ़ाना, निर्यात को प्रोत्साहन देना और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है।
- **Key upcoming trade agreements include:**
 - India–US Trade Deal (2026)
 - India–EU Free Trade Agreement (FTA) (2026)
- प्रमुख आगामी व्यापार समझौतों में शामिल हैं:
 - भारत–अमेरिका व्यापार समझौता (2026)
 - भारत–EU मुक्त व्यापार समझौता (2026)
- India–New Zealand FTA (2025) is expected to improve India's access to the Pacific market.
- भारत–न्यूज़ीलैंड FTA (2025) से प्रशांत क्षेत्र में बाज़ार पहुंच बेहतर होगी।
- India–Oman CEPA (2025) and India–UK CETA (2025) focus on strategic cooperation and services trade.





• भारत-ओमान CEPA (2025) और भारत-UK CETA (2025) रणनीतिक और सेवा व्यापार पर केंद्रित हैं।

• **Recently concluded trade deals include:**

- India-EFTA TEPA (2024)
- India-Australia ECTA (2022)
- India-UAE CEPA (2022)
- India-Mauritius CECPA (2021)

• हाल में संपन्न प्रमुख समझौते हैं:

- भारत-EFTA TEPA (2024)
- भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA (2022)
- भारत-UAE CEPA (2022)
- भारत-मॉरीशस CECPA (2021)

• These trade agreements reflect India's strategic push toward trade-led growth and greater global economic integration.

• ये समझौते व्यापार आधारित विकास और वैश्विक आर्थिक एकीकरण की दिशा में भारत की नीति को दर्शाते हैं।

EXAM
Genius





Ques: Indian Oil Corporation Limited signed a Letter of Intent with which airline to explore the future supply of Sustainable Aviation Fuel (SAF) at Wings India 2026?

विंग्स इंडिया 2026 के दौरान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सतत विमानन ईंधन (SAF) की भविष्य की आपूर्ति के लिए किस एयरलाइन के साथ आशय पत्र (LoI) पर हस्ताक्षर किए?

- A) IndiGo / इंडिगो
- B) Air India / एयर इंडिया
- C) Vistara / विस्तारा
- D) Akasa Air / अकासा एयर
- E) SpiceJet / स्पाइसजेट

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या :

- Indian Oil Corporation Limited (IOCL) signed a Letter of Intent (LoI) with Akasa Air.
- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने अकासा एयर के साथ आशय पत्र (LoI) पर हस्ताक्षर किए।
- The agreement aims to jointly explore the future supply of Sustainable Aviation Fuel (SAF).
- इस समझौते का उद्देश्य सतत विमानन ईंधन (SAF) की भविष्य की आपूर्ति की संभावनाओं का संयुक्त रूप से अध्ययन करना है।
- The LoI was signed during Wings India 2026.
- यह आशय पत्र विंग्स इंडिया 2026 के दौरान हस्ताक्षरित किया गया।
- The event was held in Hyderabad, Telangana.
- यह आयोजन हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित हुआ।
- Sustainable Aviation Fuel (SAF) is a low-carbon alternative to conventional jet fuel.
- सतत विमानन ईंधन (SAF) पारंपरिक जेट ईंधन का कम-कार्बन विकल्प है।
- SAF can significantly reduce lifecycle greenhouse gas emissions from aviation.
- SAF विमानन क्षेत्र से होने वाले कुल जीवन-चक्र ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को उल्लेखनीय रूप से कम कर सकता है।

About Indian Oil Corporation :

- Established : 1959
- HQ : New Delhi
- CMD : Arvindar Singh Sahney





Ques: Apple has launched an education hub in Bengaluru in partnership with which institution?

एप्पल ने बेंगलुरु में किस संस्थान के साथ मिलकर एजुकेशन हब लॉन्च किया है?

- A) IIT Bengaluru / आईआईटी बेंगलुरु
- B) IISc Bengaluru / आईआईएससी बेंगलुरु
- C) Manipal Academy of Higher Education / मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन
- D) Amity University / एमिटी विश्वविद्यालय
- E) Tata Institute of Social Sciences / टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- Apple has launched a new education hub in Bengaluru in collaboration with the Manipal Academy of Higher Education (MAHE).
- एप्पल ने मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन (MAHE) के साथ मिलकर बेंगलुरु में नया एजुकेशन हब शुरू किया है।
- The education hub will begin offering new courses from March.
- यह एजुकेशन हब मार्च से नए कोर्स शुरू करेगा।
- The initiative aims to expand skill-building and training programs for people across Apple's supply chain in India.
- इस पहल का उद्देश्य भारत में एप्पल की सप्लायर चेन से जुड़े लोगों के लिए स्किल-बिल्डिंग और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करना है।
- Courses will focus on digital literacy, Swift coding, robotics, automation technology, and smart manufacturing.
- पाठ्यक्रमों में डिजिटल साक्षरता, स्विफ्ट कोडिंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन तकनीक और स्मार्ट मैनुफैक्चरिंग शामिल होंगे।
- Apple is also expanding training programs at over 25 supplier sites across India.
- एप्पल भारत में 25 से अधिक सप्लायर साइट्स पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार कर रही है।
- The initiative is part of Apple's \$50 million global Supplier Employee Development Fund.
- यह पहल एप्पल के \$50 मिलियन वैश्विक सप्लायर एम्प्लॉयी डेवलपमेंट फंड का हिस्सा है।
- The program aims to help supplier employees gain new skills and explore career growth opportunities.





Ques: Apple has launched an education hub in Bengaluru in partnership with which institution?

एप्पल ने बेंगलुरु में किस संस्थान के साथ मिलकर एजुकेशन हब लॉन्च किया है?

- A) IIT Bengaluru / आईआईटी बेंगलुरु
- B) IISc Bengaluru / आईआईएससी बेंगलुरु
- C) Manipal Academy of Higher Education / मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन
- D) Amity University / एमिटी विश्वविद्यालय
- E) Tata Institute of Social Sciences / टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- Apple has launched a new education hub in Bengaluru in collaboration with the Manipal Academy of Higher Education (MAHE).
- एप्पल ने मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन (MAHE) के साथ मिलकर बेंगलुरु में नया एजुकेशन हब शुरू किया है।
- The education hub will begin offering new courses from March.
- यह एजुकेशन हब मार्च से नए कोर्स शुरू करेगा।
- The initiative aims to expand skill-building and training programs for people across Apple's supply chain in India.
- इस पहल का उद्देश्य भारत में एप्पल की सप्लाय चैन से जुड़े लोगों के लिए स्किल-बिल्डिंग और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करना है।
- Courses will focus on digital literacy, Swift coding, robotics, automation technology, and smart manufacturing.
- पाठ्यक्रमों में डिजिटल साक्षरता, स्विफ्ट कोडिंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन तकनीक और स्मार्ट मैनुफैक्चरिंग शामिल होंगे।
- Apple is also expanding training programs at over 25 supplier sites across India.
- एप्पल भारत में 25 से अधिक सप्लायर साइट्स पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार कर रही है।
- The initiative is part of Apple's \$50 million global Supplier Employee Development Fund.
- यह पहल एप्पल के \$50 मिलियन वैश्विक सप्लायर एम्प्लॉयी डेवलपमेंट फंड का हिस्सा है।
- The program aims to help supplier employees gain new skills and explore career growth opportunities.





Ques: Which public sector enterprise launched the national creative challenge “सेल-e-BRATION (SAIL-eBRATION): Steel Built India, SAIL Built Trust” in collaboration with MyGov in January 2026?

जनवरी 2026 में MyGov के सहयोग से “सेल-e-BRATION (SAIL-eBRATION): Steel Built India, SAIL Built Trust” नामक राष्ट्रीय रचनात्मक प्रतियोगिता किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने शुरू की?

- A) Rashtriya Ispat Nigam Limited / राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
- B) Tata Steel / टाटा स्टील
- C) NMDC Limited / एनएमडीसी लिमिटेड
- D) National Aluminium Company / नेशनल एल्युमिनियम कंपनी
- E) Steel Authority of India Limited / स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या :

- The Steel Authority of India Limited (SAIL) launched the national creative challenge “सेल-e-BRATION (SAIL-eBRATION): Steel Built India, SAIL Built Trust”.
- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) ने “सेल-e-BRATION (SAIL-eBRATION): Steel Built India, SAIL Built Trust” नामक राष्ट्रीय रचनात्मक प्रतियोगिता शुरू की।
- The initiative was launched in collaboration with MyGov, the citizen engagement platform of the Government of India.
- यह पहल भारत सरकार के नागरिक सहभागिता मंच MyGov के सहयोग से शुरू की गई।
- The challenge was launched in January 2026.
- यह प्रतियोगिता जनवरी 2026 में शुरू की गई।
- Participants can submit entries under four themes:
- प्रतिभागी निम्न चार विषयों के अंतर्गत प्रविष्टियाँ जमा कर सकते हैं:

- Building India’s Big Dreams
- Shield & Star
- There’s a Little Bit of SAIL in Everyone’s Life
- Products Everywhere





Ques: What percentage share of central taxes for States has been recommended by the 16th Finance Commission?

16वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए केंद्रीय करों में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी की सिफारिश की है?

- A) 40%
- B) 41%
- C) 42%
- D) 45%
- E) 50%

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या :

- The 16th Finance Commission (FC) has recommended retaining the States' share in central taxes at 41%, the same level as recommended by the 15th Finance Commission.
- 16वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% पर बरकरार रखने की सिफारिश की है, जैसा कि 15वें वित्त आयोग ने किया था।
- The report of the 16th Finance Commission was tabled in Parliament on Budget Day.
- 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट बजट दिवस पर संसद में पेश की गई।
- The Commission upheld the principle of equitable redistribution of resources, with special focus on poorer and less-developed States.
- आयोग ने समान संसाधन वितरण के सिद्धांत को बनाए रखा, विशेष रूप से कम समृद्ध राज्यों के पक्ष में।
- Although the parameters of the tax devolution formula were revised, there was no major change in the overall share of States.
- यद्यपि कर वितरण फार्मूले के मापदंडों में बदलाव किया गया, लेकिन राज्यों की कुल हिस्सेदारी में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ।
- A key reform was the introduction of a new horizontal criterion to reward a State's contribution to the overall economy.
- एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में राज्य के समग्र आर्थिक योगदान को पुरस्कृत करने हेतु नया क्षैतिज मानदंड जोड़ा गया।
- This ensures that fast-growing and economically contributing States also receive due recognition along with equity-based transfers.





Ques: Which country has proposed banning social media access for children under 16 years of age?

16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किस देश ने दिया है?

- A) France / फ्रांस
- B) Denmark / डेनमार्क
- C) Spain / स्पेन
- D) Portugal / पुर्तगाल
- E) Germany / जर्मनी

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- Spain, under Prime Minister Pedro Sánchez, has announced plans to ban access to social media platforms for children below 16 years.
- स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज़ ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा की है।
- The move aims to protect children from online safety risks and harmful digital content.
- यह कदम बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा जोखिमों और हानिकारक डिजिटल सामग्री से बचाने के लिए उठाया गया है।
- Social media companies will be required to implement robust age-verification mechanisms.
- सोशल मीडिया कंपनियों को मजबूत आयु-सत्यापन तंत्र लागू करना अनिवार्य होगा।
- The proposal is expected to be approved by Spain's Council of Ministers and will amend an existing draft bill under parliamentary discussion.
- यह प्रस्ताव स्पेन की मंत्रिपरिषद से मंजूरी के बाद संसद में विचाराधीन विधेयक में संशोधन करेगा।
- The revised proposal will explicitly prohibit minors from registering on social media platforms.
- संशोधित प्रस्ताव में नाबालिगों के सोशल मीडिया पंजीकरण पर स्पष्ट प्रतिबंध होगा।
- Spain's decision is part of a broader European effort to regulate children's online activity.
- यह निर्णय बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों को नियंत्रित करने की यूरोप-व्यापी पहल का हिस्सा है।





Ques: Which state has emerged as the largest contributor to India's Renewable Energy (RE) capacity, accounting for 16.50% of the total installed capacity?

भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा (RE) क्षमता में 16.50% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन-सा राज्य बना है?

- A) Rajasthan / राजस्थान
- B) Tamil Nadu / तमिलनाडु
- C) Maharashtra / महाराष्ट्र
- D) Gujarat / गुजरात
- E) Karnataka / कर्नाटक

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या :

- Gujarat has emerged as the largest contributor to India's Renewable Energy (RE) capacity.
- गुजरात भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा है।
- The state has a cumulative installed RE capacity of 42.583 Gigawatt (GW).
- राज्य की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 42.583 गीगावाट (GW) है।
- Gujarat accounts for 16.50% of India's total Renewable Energy capacity.
- गुजरात की हिस्सेदारी भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 16.50% है।
- Gujarat ranks first in total installed RE capacity and first in wind power capacity with 14,820.94 MW.
- गुजरात कुल स्थापित RE क्षमता में पहले स्थान पर है और 14,820.94 मेगावाट के साथ पवन ऊर्जा क्षमता में भी पहले स्थान पर है।
- The state ranks second in solar power capacity with 25,529.40 MW.
- 25,529.40 मेगावाट के साथ गुजरात सौर ऊर्जा क्षमता में दूसरे स्थान पर है।
- Gujarat also ranks first in rooftop solar installations in India.
- गुजरात भारत में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में भी पहले स्थान पर है।

About Gujarat :

- Capital : Gandhinagar
- CM : Bhupendra Patel
- Governor : Acharya Devvrat





Ques: Who is the author of the book 'Four Stars of Destiny', which is in news for its insights into India's military leadership?

'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' पुस्तक के लेखक कौन हैं, जो भारतीय सैन्य नेतृत्व पर अपने विश्लेषण के कारण समाचारों में है?

- A) Major General V.K. Singh / मेजर जनरल वी.के. सिंह
- B) General Bipin Rawat / जनरल बिपिन रावत
- C) General M.M. Naravane / जनरल एम.एम. नरवणे
- D) Lt Gen Manoj Mukund Naravane / लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे
- E) Ajit Doval / अजीत डोभाल

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- 'Four Stars of Destiny' is authored by General M.M. Naravane, former Chief of the Army Staff (COAS) of India.
- 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' के लेखक भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष (COAS) जनरल एम.एम. नरवणे हैं।
- The book provides in-depth insights into India's military leadership, strategic decision-making, and civil-military relations.
- यह पुस्तक भारतीय सैन्य नेतृत्व, रणनीतिक निर्णय प्रक्रिया और सिविल-मिलिट्री संबंधों पर प्रकाश डालती है।
- Another book in news is 'India's External Intelligence — Secrets of Research and Analysis Wing'.
- समाचारों में एक अन्य पुस्तक 'इंडियाज़ एक्सटर्नल इंटेलिजेंस — सीक्रेट्स ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग' भी चर्चा में रही।
- This book is written by Major General V.K. Singh (Retired).
- इस पुस्तक के लेखक मेजर जनरल वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) हैं।
- It focuses on the working, evolution, and strategic role of RAW (Research and Analysis Wing), India's external intelligence agency.
- यह पुस्तक भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी RAW (रिसर्च एंड एनालिसिस विंग) की कार्यप्रणाली, विकास और रणनीतिक भूमिका पर केंद्रित है।
- Both books came into prominence after being referenced in Parliament and public discourse.
- दोनों पुस्तकें संसद और सार्वजनिक विमर्श में संदर्भित होने के कारण चर्चा में रहीं।





- Their mention has triggered debates on military accountability, intelligence transparency, and civil–military oversight in India.
- इनके संदर्भ ने भारत में सैन्य जवाबदेही, खुफिया पारदर्शिता और सिविल–मिलिट्री निगरानी पर बहस को गति दी है।



EXAM
Genius





Ques: Which state ranked first in the implementation of the PESA Act, 1996, according to the PESA State Performance Rankings 2024-25?

PESA अधिनियम, 1996 के क्रियान्वयन में PESA राज्य प्रदर्शन रैंकिंग 2024-25 के अनुसार कौन-सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा?

- A) Madhya Pradesh / मध्य प्रदेश
- B) Himachal Pradesh / हिमाचल प्रदेश
- C) Rajasthan / राजस्थान
- D) Maharashtra / महाराष्ट्र
- E) Chhattisgarh / छत्तीसगढ़

Answer: Option D

Explanation :

- The Union Government launched PANCHAM (Panchayat Assistance & Messaging Chatbot).
- केंद्र सरकार ने PANCHAM (पंचायत असिस्टेंस एंड मैसेजिंग चैटबॉट) लॉन्च किया है।
- It was developed in collaboration with the Ministry of Panchayati Raj (MoPR) and UNICEF.
- इसे पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) और यूनिसेफ (UNICEF) के सहयोग से विकसित किया गया है।
- PANCHAM is designed as a digital companion for Panchayats, providing contextual guidance, simplified workflows, and easy access to information for day-to-day governance and service delivery.
- PANCHAM पंचायतों के लिए एक डिजिटल साथी के रूप में कार्य करता है, जो दैनिक प्रशासन और सेवा वितरण के लिए मार्गदर्शन और सरल प्रक्रियाएँ उपलब्ध कराता है।
- For the first time, it creates a direct two-way digital connection between the Government of India and Panchayats.
- यह पहली बार भारत सरकार और पंचायतों के बीच सीधा दो-तरफ़ा डिजिटल संपर्क स्थापित करता है।
- PANCHAM is integrated with BHASHINI (BHASHA INterface for India) and supports 22 Indian languages.
- PANCHAM को BHASHINI के साथ एकीकृत किया गया है और यह 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है।
- The Ministry of Panchayati Raj released the PESA State Performance Rankings 2024-25.



- पंचायती राज मंत्रालय ने PESA राज्य प्रदर्शन रैंकिंग 2024-25 जारी की।
- Among the 10 states with Fifth Schedule Areas, Maharashtra secured the 1st position in PESA implementation.
- पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों वाले 10 राज्यों में महाराष्ट्र ने PESA के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
- Maharashtra was followed by Madhya Pradesh and Himachal Pradesh.
- महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश रहे।

PESA State Performance Categories 2024-25 :

- Front Runner – Maharashtra, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh
- Performer – Rajasthan, Chhattisgarh, Telangana
- Aspirant – Andhra Pradesh, Gujarat
- Beginner – Odisha, Jharkhand

About PESA Act, 1996 | PESA अधिनियम के बारे में :

- PESA (Provisions of the Panchayats – Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 is a landmark law enabling self-governance for tribal communities.
- PESA अधिनियम, 1996 जनजातीय समुदायों को स्वशासन प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है।
- It was enacted on 24 December 1996, based on the recommendations of the Bhuria Committee (1995).
- इसे भूरिया समिति (1995) की सिफारिशों के आधार पर 24 दिसंबर 1996 को लागू किया गया।
- Objective: To extend the 73rd Constitutional Amendment (Panchayati Raj) to Fifth Schedule Areas while protecting tribal traditions.
- उद्देश्य: 73वें संविधान संशोधन को पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक विस्तारित करना और जनजातीय परंपराओं की रक्षा करना।
- The Fifth Schedule deals with the administration and control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes (except Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram).
- पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है (असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम को छोड़कर)।





Ques: Which airport operator became the world's first to fully deploy Wi-Fi 7 technology across its entire national airport network?

कौन-सा एयरपोर्ट ऑपरेटर अपने पूरे राष्ट्रीय एयरपोर्ट नेटवर्क में Wi-Fi 7 तकनीक को पूरी तरह लागू करने वाला विश्व का पहला बना?

- A) Dubai Airports / दुबई एयरपोर्ट्स
- B) Singapore Changi Airport Group / सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट ग्रुप
- C) Heathrow Airport Holdings / हीथ्रो एयरपोर्ट होल्डिंग्स
- D) Oman Airports / ओमान एयरपोर्ट्स
- E) Qatar Airways Group / कतर एयरवेज़ ग्रुप

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या :

- Oman Airports became the world's first airport operator to fully deploy Wi-Fi 7 technology across its entire national network.
- ओमान एयरपोर्ट्स अपने पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क में Wi-Fi 7 तकनीक को पूर्ण रूप से लागू करने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट ऑपरेटर बना।
- The deployment includes Muscat International Airport.
- इस तैनाती में मस्कट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है।
- This milestone was achieved through a strategic partnership with Huawei.
- यह उपलब्धि हुवावे (Huawei) के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से हासिल की गई।
- The new Wi-Fi 7 network delivers speeds of up to 46 Gbps, nearly five times faster than Wi-Fi 6E.
- नया Wi-Fi 7 नेटवर्क 46 Gbps तक की गति प्रदान करता है, जो Wi-Fi 6E से लगभग पाँच गुना तेज़ है।
- The technology significantly reduces latency, especially in high-density areas such as check-in halls.
- यह तकनीक विशेष रूप से चेक-इन हॉल जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में लेटेंसी को काफी कम करती है।
- The system uses the Huawei iMaster NCE-Campus platform, an AI-driven network management tool.
- यह प्रणाली Huawei iMaster NCE-Campus प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है, जो एक AI-आधारित नेटवर्क प्रबंधन टूल है।
- The platform has reduced network troubleshooting time from 12 hours to just a few minutes.
- इस प्लेटफॉर्म ने नेटवर्क समस्या समाधान समय को 12 घंटे से घटाकर कुछ ही मिनटों में कर दिया है।





Ques: How many households have benefited under PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana as of December 2025?

दिसंबर 2025 तक पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने परिवारों को लाभ मिला है?

- A) 1.5 million
- B) 2.0 million
- C) 2.6 million
- D) 3.5 million
- E) 5.0 million

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana has benefited over 2.6 million (26 lakh) households across India.
- पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना से देशभर में 2.6 मिलियन (26 लाख) से अधिक परिवारों को लाभ मिला है।
- The information was informed to Parliament, with data updated as of December 2025.
- यह जानकारी दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार संसद को दी गई।
- The scheme provides central financial assistance of ₹14,771.82 crore.
- इस योजना के तहत ₹14,771.82 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
- The initiative promotes rooftop solar installations for households.
- यह योजना घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देती है।
- Objective: To reduce electricity bills and promote clean and renewable energy.
- उद्देश्य: बिजली बिल कम करना और स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करना।

Genius





Ques: Exercise 'KHANJAR' is a joint special forces exercise conducted between which two countries?

अभ्यास 'खंजर' किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है?

- A) India – Kazakhstan / भारत – कज़ाख़स्तान
- B) India – Uzbekistan / भारत – उज़्बेकिस्तान
- C) India – Kyrgyzstan / भारत – किर्गिज़स्तान
- D) India – Tajikistan / भारत – ताजिकिस्तान
- E) India – Mongolia / भारत – मंगोलिया

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- The 13th edition of India–Kyrgyzstan Joint Special Forces Exercise KHANJAR commenced at Missamari, Assam.
- भारत–किर्गिज़स्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास 'खंजर' का 13वां संस्करण मिसामारी, असम में शुरू हुआ।
- The exercise is being conducted from 04 to 17 February 2026.
- यह अभ्यास 04 से 17 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा।
- Exercise KHANJAR is an annual bilateral military exercise, held alternately in India and Kyrgyzstan.
- अभ्यास खंजर एक वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जो भारत और किर्गिज़स्तान में बारी-बारी से होता है।
- The Indian Army contingent (20 personnel) is from the Parachute Regiment (Special Forces), while the Kyrgyz contingent is represented by the ILBRIS Special Forces Brigade.
- भारतीय दल पैराशूट रेजिमेंट (स्पेशल फोर्सिस) से है, जबकि किर्गिज़स्तान का दल ILBRIS स्पेशल फोर्सिस ब्रिगेड से है।
- The exercise focuses on counter-terrorism operations, urban and mountainous warfare, including sniping and complex building intervention.
- अभ्यास में आतंकवाद-रोधी अभियान, शहरी एवं पर्वतीय युद्ध, स्नाइपिंग और जटिल इमारत हस्तक्षेप पर ध्यान दिया जाता है।
- It strengthens bilateral defence cooperation and reaffirms commitment to regional peace, stability and security.
- यह अभ्यास द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करता है और क्षेत्रीय शांति, स्थिरता व सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।





Ques: February 1 is observed as which important day in India?

1 फ़रवरी को भारत में किस महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है?

- A) Indian Navy Day / भारतीय नौसेना दिवस
- B) Indian Coast Guard Day / भारतीय तटरक्षक बल दिवस
- C) Raising Day of the Indian Coast Guard / भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस
- D) National Maritime Day / राष्ट्रीय समुद्री दिवस
- E) Defence Services Day / रक्षा सेवा दिवस

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- February 1 is observed as the Raising Day of the Indian Coast Guard (ICG).
- 1 फ़रवरी को भारतीय तटरक्षक बल (ICG) का स्थापना दिवस मनाया जाता है।
- In 2026, India celebrated the 50th Raising Day of the Indian Coast Guard.
- 2026 में भारतीय तटरक्षक बल का 50वाँ स्थापना दिवस मनाया गया।
- The Indian Coast Guard was started in 1979.
- भारतीय तटरक्षक बल की शुरुआत 1979 में हुई थी।
- The ICG was formally inaugurated on 19 August 1978.
- भारतीय तटरक्षक बल का औपचारिक उद्घाटन 19 अगस्त 1978 को किया गया था।
- It was inaugurated by the then Prime Minister Morarji Desai.
- इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा किया गया था।

EXAM
Genius

